



पाठ्यक्रम: विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, कला, श्रम, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेल।  
356-2021-2023



# BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343  
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

“The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy.”

**Admission Open**  
For The Academic Session 2026-27  
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS  
APPLY NOW

### Vision -

To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

### Mission-

To produce enriched and enlightened human resource for the country.

### Pillars -

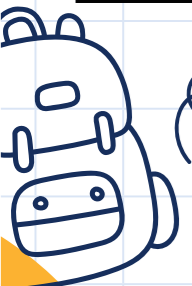
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

### Goal-

ब्रह्म तद् लक्ष्यम्



Streams:  
Science,  
Commerce &  
Humanities



Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681  
+91 7055515683

www.blmacademy.com

Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital), Uttarakhand  
blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्मुच्यते।  
अप्रमत्तेन वेद्ध्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ (मुण्डक उपनिषद्)

ई-मेल: uttaranchaldeepatrika@gmail.com

# जून 2026 उत्तरांचल दीप



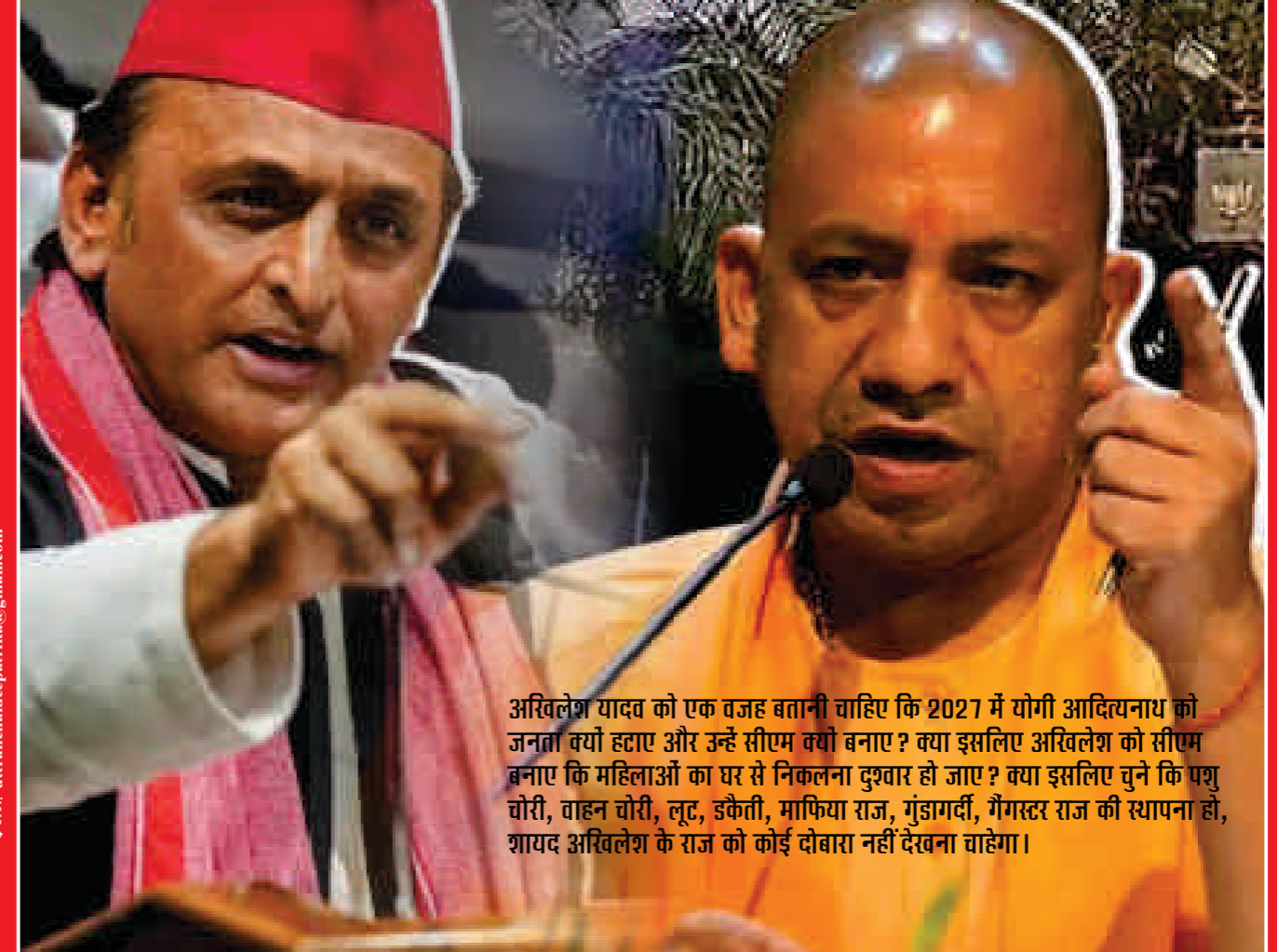
यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

पत्रिका

एनकाउंटर पर विपक्षी मातमड्ड

₹:40

# यूपी में सपा का चांस नहीं !



अखिलेश यादव को एक वजह बतानी चाहिए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को जनता क्यों हटाए और उन्हें सीएम क्यों बनाए? क्या इसलिए अखिलेश को सीएम बनाए कि महिलाओं का घर से निकलना दुश्वार हो जाए? क्या इसलिए चुने कि पशु चोरी, वाहन चोरी, लूट, डकैती, माफिया राज, गुंडागर्दी, गैंगस्टर राज की स्थापना हो, शायद अखिलेश के राज को कोई दोबारा नहीं देखना चाहेगा।

Web: uttaranchaldeep.com



# Nupur Creations

Jute Hand Bags, Craft & Many More



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल नीति से प्रेरित उत्तराखंड के हस्तकला के क्षेत्र में उभरता नाम

## नुपूर

उत्तराखंड की हस्तकला को राष्ट्रीय पहचान दिलाना हमारा लक्ष्य उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रयास जूट से बने फैंसी आइटम, होम डेकोरेशन की फैंसी सामग्री, गिफ्ट आइटम की बड़ी रेंज ऑन लाइन उपलब्ध



SHAKTI PURAM GALI,  
NAWABI ROAD, HALDWANI  
(NAINITAL), Uttarakhand

CALL:  
05946 220841, +91 9410334041

+91 9760590897

www.facebook.com/nupurnityakalakendra

You Tube: Search: nupurnityakalakendra

nupurnitya99@gmail.com

www.nupurcreations.co.in

Log in for purchase Items ONLINE:

## मासिक उत्तरांचल दीप पत्रिका

वर्ष: 9, अंक 2, जून 2026

संस्थापक संपादक  
स्व. वेदप्रकाश गुप्ता  
प्रधान संपादक  
साकेत अग्रवाल  
संपादक  
श्रीमती आदेश अग्रवाल  
मुख्य कार्यकारी संपादक  
केके चौहान  
मुख्य उप संपादक  
उदयभान सिंह  
मार्केटिंग हेड  
तारु तिवारी  
प्रबंधक  
दीपक तिवारी  
वरिष्ठ संवाददाता  
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो

दिल्ली : शालिनी चौहान  
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित  
नैनीताल : अफजल फौजी  
अल्मोड़ा : कमल कपूर  
पिथौरागढ़ : ललित जोशी  
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट  
चंपावत : मनोज राय  
बरेली : अनुज सक्सेना  
मुगदाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल  
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल  
किच्छर : राजकुमार राज  
रामनगर : एचसी भट्ट  
थत्वूड़ : मुकेश रावत  
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता  
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह  
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेन्द्र सिंह बिष्ट  
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय

हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने  
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।

आएनआई नंबर: UTTTHIN/2018/77440  
पोस्टल रजि. नं. यूए-नैनीताल-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com  
uttaranchaldeepatrika@gmail.com

+91 8881788066 @uttaranchaldeep

## अंदर

### बीजेपी का मिशन हैट्रिक!



# 10

भाजपा का विशेष फोकस उत्तराखंड की उन हाई रिस्क सीटों पर है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी को बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था अथवा भाजपा की जीत का अंतर मामूली था, इसके लिए भाजपा ने 'बूथ जीतो चुनाव जीतो' का नारा बुलंद किया है, इसी मंत्र के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतिक बिसात बिछाई जा रही है।

# 12

संवेदना

### बीसी खंडूड़ी का गौरवशाली सफर

2011 में जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चरम पर था, तब खंडूड़ी ने उत्तराखंड में सख्त लोकायुक्त बिल पेश कर ...



# 14

पश्चिम बंगाल

### टीएमसी खत्म हो जाएगी?

टीएमसी के कुछ नेताओं ने तो चुनाव के तुरंत बाद भाजपा में शामिल होने का जुगाड़ भी लगाया ...

# 16

पाकिस्तान

### ट्रंप के जाल में फंसा पाक

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसीम मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाने के लिए खलीफा ...



# 18

उत्तराखंड

### टेशन में मदरसा संचालक

धामी की सरकार ने जब सर्वे कराया था तब राज्य में 950 मदरसे चिह्नित हुए थे, यानी करीब 300 मदरसे बिना सरकार की अनुमति के ...



साकेत अग्रवाल

## भाजपा के पास मोदी मैजिक

भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना अब विपक्षी दलों के लिए कठिन होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में की गई गलतियों से सीख लेते हुए भाजपा ने जो भूल सुधार किया है उसने असंभव को भी संभव बना दिया है। पश्चिम बंगाल जीतना भाजपा के लिए शेर के मुंह से निवाला (सत्ता) खींचने जैसा था, लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों व चुनाव आयोग की सख्ती ने जब पश्चिम बंगाल की जनता को आजादी के माहौल में मतदान का मौका दिया तो ममता बनर्जी का 15 साल पुरानी सल्तन धारशाही हो गई। भाजपा अब 2027 से लेकर 2029 तक के मिशन में जुट गई है। अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2026 की तरह 2027 भी राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। 2027 में सात राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे 2029 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आधार तैयार करने वाले साबित होंगे। यानी भाजपा ने 2027 की ही नहीं बल्कि 2029 की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके विपरीत विपक्षी दलों का गठबंधन रहेगा, नहीं रहेगा अभी यही तय नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन रहा तो उसमें कौन-कौन दल रहेंगे, किसका नेतृत्व होगा? क्योंकि 2024 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब खाली हैं, इसलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के तुरंत बाद सभी विपक्षी दलों की एकता का आह्वान किया था। यानी 2024 से 2026 तक अकेले चलने वाली ममता बनर्जी को अब विपक्षी एकता की जरूरत महसूस हो रही है। ममता बनर्जी तो मई 2026 में खाली हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी तो 2014 से खाली हैं, सपा के अखिलेश यादव 2017 से बेरोजगार हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे पहले से ही खाली हैं। ऐसे में विपक्षी एकता मजबूत हो सकती है, इन सभी दलों का एक ही मिशन है भाजपा और मोदी को सत्ता से बेदखल करना, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई नेता किसी दल को सत्ता से बेदखल कर सकता है? निश्चित ही जवाब होगा नहीं। सत्ता से बेदखल करने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है और जनता मोदी और भाजपा के साथ है। इसका प्रमाण हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं। अगर जनता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों, विचारधारा, योजनाओं से नाराज होती तो असम और पुंडुचेरी में एनडीए की वापसी नहीं होती और पश्चिम बंगाल के नतीजे चौकाने वाले नहीं आते। सच कहें तो भाजपा के पास एक चमत्कारी चेहरा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। केंद्र के चुनाव हों या राज्यों के नरेंद्र मोदी मैजिक जनता के सिर चढ़कर बोलता है। उनके नाम पर और चेहरे पर ही भाजपा को वोट मिलते हैं। यानी नरेंद्र मोदी भरोसे का नाम बन गए हैं। मोदी यदि भाजपा के लिए वोट मांगते हैं तो जनता भरोसा कर उन्हें भर-भर कर वोट और आशीर्वाद देती है, जिसे विपक्षी दल वोट चोरी कहते हैं।



विपक्षी दल अगले साल होने वाले 7 राज्यों के चुनाव के लिए अभी उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। भाजपा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पांच जून से 21 जून तक देशव्यापी जनसंपर्क, सेवा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 7 जून 2026 को नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे गए हैं। भाजपा ने नया नारा दिया है कि 'बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।' इसी थीम पर 5 से 21 जून तक के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। पार्टी ने इन 12 वर्षों को गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान, किसानों के हित, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया है। निर्धारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में 8 से 12 जून तक मीडिया संवाद आयोजित किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और पार्टी नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों और विकास यात्राओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया। इसके अलावा 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया गया, इसमें जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर नागरिकों से संवाद किया और सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अभियान के तहत वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्राएं और 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रत्येक जिले में कम से कम 500 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संपर्क साधने का लक्ष्य पूरा किया गया। इसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक सरकार की योजनाओं का संदेश पहुंचा गया। 12 से 20 जून के बीच देशभर में जनकल्याण शिविर लगाए गए। जहां आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम सूर्य घर रेशनी सहित अन्य योजनाओं में पात्र लोगों का पंजीकरण कराया गया। पात्रों को घर से शिविर तक लाने की जिम्मेदारी पार्टी संगठन को सौंपी गई थी। लिहाजा संगठन ने पात्रों को शिविरों तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रत्येक जिले में सभागार बैठकों, उपलब्धियों की प्रदर्शनी और प्राकृतिक खेती पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस (5 जून) को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को भी प्राथमिकता देने का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि इस अभियान की विकसित भारत के संकल्प को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक तरफ जहां भाजपा ने सरकार का पक्ष जनता तक पहुंचा कर चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया वहीं यूपी में सपा प्रमुख अभी सिर्फ पीडीए के नाम की ही जुगाली कर रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फोविया से ग्रस्त हैं।

## पश्चिम बंगाल में निकलेगा तेल

पश्चिम बंगाल की शुभेदु सरकार द्वारा भूमि संबंधी मुद्दों को सुलझाने के बाद इस तेल प्रोजेक्ट को नई गति मिली है, शुभेदु सरकार की कैबिनेट ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को 50 एकड़ भूमि पट्टे पर दे दी है, जिससे ड्रिलिंग और बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता साफ हो गया है।

# अ

उत्तरांचल दीप डेस्क

मेरिका-ईरान व इजराइल तनाव के कारण दुनिया भर में तेल संकट बना हुआ है। सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक के कारण दुनिया महंगाई के जाल में उलझी हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीयों के लिए रहत की खबर है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के अशोकनगर में कच्चे तेल का जो भंडारण 2018 में मिला था उस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। यानी भाजपा की सरकार बनने के बाद अशोकनगर तेल क्षेत्र एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। नए सिरे से राजनीतिक ध्यान, प्रशासनिक मंजूरी और ऊर्जा अधिकारियों पर बढ़ते दबाव ने वर्षों की देरी के बाद कच्चे तेल के उत्पादन शुरू होने की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। कोलकाता से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित अशोकनगर क्षेत्र कोई साधारण ऊर्जा परियोजना नहीं है। इसे पूर्वी भारत में हाल के दशकों में व्यावसायिक रूप से तेल की पहली बड़ी खोज माना जा रहा है। ऊर्जा विशेषज्ञों का दावा है कि इस क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार हो सकता है, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण तटीय पेट्रोलियम संपत्तियों में से एक है। पश्चिम बंगाल की शुभेदु सरकार द्वारा भूमि संबंधी मुद्दों को सुलझाने के बाद इस प्रोजेक्ट को नई गति मिली है। शुभेदु सरकार की कैबिनेट ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को लगभग 50 एकड़ भूमि पट्टे पर दे दी है, जिससे ड्रिलिंग और बुनियादी ढांचे के विकास का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने परियोजना के पहले चरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया है, जो इसकी दीर्घकालिक व्यावसायिक और रणनीतिक क्षमता में मजबूत विश्वास का संकेत देता है। दरअसल ओएनजीसी ने पहली बार 2018 में अशोकनगर क्षेत्र में तेल और गैस के भंडारण का पता लगाया था। उस समय इस खोज ने काफी उत्साह पैदा किया था क्योंकि पूर्वी भारत ऐतिहासिक रूप से देश के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों से बाहर रहा है, जो असम, गुजरात और पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्रों जैसे राज्यों में केंद्रित हैं। हालांकि शुरुआती उत्साह जल्द ही बाधाओं में बदल गया। भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताएं, स्थानीय विरोध, पर्यावरणीय प्रश्न और नियामक स्वीकृतियों ने परियोजना को लटकाने का काम किया। लिहाजा भूवैज्ञानिक आकलन के बावजूद कच्चे तेल का उत्पादन काफी हद तक कागजों पर ही रह गया। इस सब के पीछे सिर्फ श्रेय की राजनीति

ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि बंगाल में तेल निकालने का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को मिले, इसलिए उनसे जितनी बाधाएं पैदा की गई वो की, यदि ममता ने इस प्रोजेक्ट में सहयोग किया होता तो न सिर्फ उन्हें श्रेय मिलता बल्कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को भी परंपरागत और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता।



हो रही थी। ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में तेल निकालने का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को मिले। इसलिए उनसे जितनी बाधाएं पैदा की गई वो की। यदि ममता बनर्जी ने इस प्रोजेक्ट में सहयोग किया होता तो न सिर्फ उन्हें श्रेय मिलता बल्कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगते और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता।

आत्मनिर्भर होगा भारत

यह नया प्रयास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए गंभीरता से प्रयासरत है। देश वर्तमान में अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का 90 फीसदी हिस्सा आयात करता है। इसलिए तेल का प्रत्येक नया घरेलू स्रोत रणनीतिक महत्व रखता है। यदि उत्पादन अनुमानित पैमाने पर शुरू होता है, तो अशोकनगर पर्याप्त राजस्व पैदा कर सकता है, रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। इस परियोजना को उत्तरी 24 परगना और पड़ोसी जिलों में आर्थिक विकास के लिए एक संभावित उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन के अलावा इससे रोजगार सृजन, सहायक उद्योगों को आकर्षित करने और स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है। ऊर्जा विश्लेषकों का मानना है कि भूमिगत बड़े तेल भंडार का मतलब यह नहीं है कि तुरंत उत्पादन शुरू हो जाएगा। बुनियादी ढांचा, शोधन व्यवस्था और निरंतर निवेश भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। इस बीच वर्षों की अनिश्चितता के बाद एक प्रोजेक्ट जिसे रुका हुआ माना जा रहा था, अब फिर से गति पकड़ रहा है। क्या यह प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल को भारत के ऊर्जा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर पाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ड्रिलिंग और उत्पादन का अगला चरण कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पश्चिम एशिया संकट ने एक बार फिर साबित किया है कि खाड़ी देशों के तेल पर अत्यधिक निर्भरता कितनी जोखिम भरी हो सकती है। होमुंज जलडमरूमध्य के पास किसी भी प्रकार का तनाव कीमतों, आपूर्ति और समुद्री मार्गों को प्रभावित कर रहा है।

मीडिल ईस्ट संकट के बाद भारत लगभग 40 देशों से तेल खरीद रहा है। लगभग 70 प्रतिशत आयात होमुंज जलडमरूमध्य के बाहर के मार्गों से हो रहा है। इससे जोखिम कम हो गया है। इससे भारत की सौदेबाजी की शक्ति भी बढ़ी है। भारत को रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जैव ईंधन, इथेनॉल मिश्रण, हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार करना होगा। आज ऊर्जा सुरक्षा केवल तेल तक सीमित नहीं है। यह एक संतुलित ऊर्जा भंडार के बारे में है। यदि अशोकनगर का उचित विकास किया जाए, तो यह पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकता है। इससे रोजगार, सड़कें, भंडारण सुविधाएं, पाइपलाइन और सेवा उद्योग विकसित हो सकते हैं। यह निवेश आकर्षित कर सकता है और औद्योगिक विश्वास को पुनर्जीवित कर सकता है। भारत पहले से ही विश्व के प्रमुख शोधन केंद्रों में से एक है। अधिक घरेलू कच्चे तेल से रिफाइनरियों को सहायता मिल सकती है, आयात लागत कम हो सकती है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत हो सकती है। यही कारण है कि अशोकनगर केवल एक स्थानीय तेल क्षेत्र नहीं है। बल्कि यह ऊर्जा स्वतंत्रता, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के भारत के व्यापक सपने से जुड़ा हुआ है।

# सुर्खियां

## दिल्ली के गेस्ट हाउस पर एक्शन

राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई। इनमें 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं, इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हादसे के पीछे की सभी कमियों और लापरवाहियों की गंभीरता से जांच की जाएगी तथा जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजधानी दिल्ली में अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति संचालित गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों व भवन उप-नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता



## माओवादी जोड़े की शादी

महाराष्ट्र में कभी हाथों में एके-47 लेकर जंगलों में खौफ का दूसरा नाम रहे दो बड़े माओवादी चेहरों ने अब समाज की मुख्यधारा में लौटकर एक-दूसरे का हाथ थाम लिया है। वर्षों तक हिंसा और अनिश्चितता के साये में जीने वाले छत्तीसगढ़ के गोलू और मध्य प्रदेश की संगीता अब हमेशा के लिए एक-दूजे के हो गए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया पुलिस मुख्यालय के प्रेरणा सभागार में 31 मई को जब इस अनोखी शादी की शहनाई बजी, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें खुशी से नम हो गईं। यहां पुलिस अधिकारी सिर्फ सुरक्षाकर्मी नहीं, बल्कि इस शादी के घराती और बाराती बने हुए थे। शादी के बंधन में बंधे वर-वधू कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि माओवादी संगठन के रीढ़ माने जाने वाले चेहरों में से थे। दूल्हा पांडू पुसू



चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली सभी संपत्तियों को सील किया जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम दक्षिण दिल्ली में अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के एक्शन में है। यह एक्शन मालवीय नगर स्थित बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) होटल में भीषण आग लगने के बाद हो रहा है, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे से क्षमता से अधिक संचालन तथा भवन के स्वीकृत नक्शे के बिना बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन उजागर हुआ है। एमसीडी का कहना है कि जिस इमारत में यह घटना हुई, उसके खिलाफ पहले कभी किसी उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया गया था। ●

वड्डे उर्फ गोलू (37 वर्ष) छत्तीसगढ़ के तहसील पाखजूरा जिला कांकर का निवासी है। यह सीपीआई (माओवादी) संगठन में दरेकसा क्षेत्र में डिविजनल कमेटी सदस्य जैसे बड़े और खतरनाक पद पर सक्रिय था। वहीं दुल्हन सैवती रायसिंग पंधरे उर्फ संगीता (36 वर्ष) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तहसील बैहर के ग्राम राशीमेटा की निवासी है। यह दरेकसा एरिया कमेटी में एरिया कमेटी सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। दोनों की शादी में शामिल हुए पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने कहा-यह विवाह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि परिवर्तन, पुनर्मिलन, विश्वास और शांतिपूर्ण भविष्य की आशा का उत्सव है। दोनों ने जंगलों की हिंसा वाली जिंदगी से तंग आकर 28 नवंबर 2025 को गोंदिया पुलिस के सामने सरेंडर किया था। जिले में अब तक 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें पुलिस कॉलोनी में सुरक्षित रखा गया है। समाज में सम्मान से जीने और अपना परिवार बसाने की चाहत ने इन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब इन दोनों युगल के नए जीवन को संवारने की कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा इनके नागरिक दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी, बैंक खाते और अन्य जरूरी कागजात तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही, इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। गोंदिया पुलिस मुख्यालय में बिना किसी बाधा के हुई यह शादी सीधे तौर पर उन नक्सलियों को कड़ा संदेश है जो आज भी भटक रहे हैं। यह घटना साबित करती है कि यदि वे हिंसा छोड़ते हैं, तो सरकार और समाज उन्हें न केवल सुरक्षा देगा, बल्कि खुशहाली से जिंदगी जीने का हक भी देगा। ●

## फौजियों को मिलेंगे शस्त्र लाइसेंस

पूर्व सैनिकों में रिटायरमेंट के बाद आत्मरक्षा के लिए निजी लाइसेंसी शस्त्र रखने का क्रेज रहता है। क्योंकि सेवाकाल में शस्त्र ही उनका गहना बन जाते हैं, यही गहना (शस्त्र) देश की सुरक्षा करता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी शस्त्र का मोह नहीं छूटता, इसलिए भी बहुत से रिटायर फौजी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र की डिमांड करते हैं। रिटायर फौजी इसलिए भी लाइसेंसी शस्त्र के लिए आवेदन करते हैं क्योंकि फौज से रिटायर होने के बाद प्राइवेट सेक्टर (सिक्वोरिटी कंपनी) में सशस्त्र फौजी को बेहतर वेतन मिल जाता है। इसलिए लम्बे समय से पूर्व सैनिकों की मांग रही है कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं। अब सूबे की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अग्निवीर योजना में रिटायर हो कर आ रहे सैनिकों के लिए भी नौकरियों का इंतजाम कर दिया है। इसके लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, पुलिस, जेल प्रहरी, वन सुरक्षा में दिए जाने की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। सरकार ने इन सभी विभागों को कह दिया है कि वे दिसंबर 2026 से पूर्व वेकेंसी निकालें। सरकार का मानना है कि आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को सेना द्वारा प्रशिक्षित और अनुशासित युवा मिलने से उनका एक बड़ा खर्चा कम हो जाएगा। धामी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को भी संदेश दिया है कि वे राष्ट्रहित में अग्निवीर पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर निश्चित करें। साथ ही सरकार पूर्व अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी योजना बना रही है। पूर्व सैनिकों की तरह पूर्व अर्ध सैनिकों के कल्याण के लिए भी धामी



सरकार कुछ योजनाओं को अंतिम रूप दे रही है। दरअसल धामी सरकार चाहती है कि रिटायर होकर आने वाले सैनिकों और उनके बच्चों को राष्ट्र निर्माण के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाए, ताकि उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो सके। धामी का कहना है कि उनकी पृष्ठभूमि भी सैनिक परिवार की है। फिर देवभूमि उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, हमारे वीरों ने राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोपरि माना है, सेवा अवधि के बाद सैनिकों के कल्याण के लिए पीएम मोदी ने विशेष तौर पर राज्य सरकार को दिशा निर्देश दे रखे हैं। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों के लिए, एक सेवक के रूप में काम कर रही है। धामी सरकार इनके बेहतर भविष्य के लिए नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भव्य सैन्यधाम की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल (रिटायर) अजय कोठियाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर कई दौर की बात हुई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर शीघ्र निर्णय लेने वाली है। ●



## वन संपत्ति पर बनी मजार गिरेगी

भारत सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों को दस्तावेज प्रमाण के साथ उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाने के बावजूद सैकड़ों संपत्तियां ऐसी सामने आई हैं जो पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा सकी हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन

संपत्तियों के जरूरी दस्तावेज नहीं मिल रहे। हैगनी की बात ये है कि जिन संपत्तियों को पूर्व में वक्फ में दर्ज कर दिया गया था वो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे करके बनाई गई थी। जबकि वक्फ संपत्ति वही कहलाई जाती है जोकि किसी व्यक्ति द्वारा दान (वक्फ) में दी गई होती है और उसकी आय से गरीबों का भला किया जाता हो। देहरादून की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलोनी कॉन्वेंट रोड की मजार भी ऐसी संपत्ति के रूप में सामने आई है जो वक्फ में यूके डीडी 0334 चढ़ा दी गई, जबकि वो वन विभाग की सरकारी भूमि पर है। अब जब केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने का विषय आया तो मजार प्रबंधकों के पास दस्तावेज नहीं मिल रहे, मिलेंगे कहां से, वो को वक्फ संपत्ति है ही नहीं। जबकि सैय्यद जमाल शाह जिनके नाम की ये मजार है वो इस जमीन के न तो कभी वारिस थे न ही उनके कोई परिजन इसके मालिक थे। सैय्यद जमाल शाह के नाम से अन्य स्थानों पर भी फ्रेंचाइजी मजारें बनी हुई हैं यानी ये साफ नहीं है कि उनकी असली मजार कहां है जहां उन्हें दफनाया गया है। फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलोनी की इस मजार को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं कि यहां आने जाने के लिए फॉरेस्ट अनुसंधान केंद्र की कॉलोनी वालों ने ही कई चोर रास्ते खोल रखे हैं क्योंकि यहां गुरवार को भीड़ आती है। बाहर कॉन्वेंट रोड पर चादर, प्रसाद, अगरबत्ती का धंधा यहां के खादिम परिवार के लोग करते हैं। खादिम यहां ताबीज बनाने, झाड़ फूंक कर अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और बदले मोटी रकम वसूल का धंधा चला रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि अंधविश्वास के शिकार हिंदू लोग ज्यादा हैं। जबकि मुस्लिम किसी भी मजार पर सजदा करने नहीं जाते वो खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं सर नहीं झुकाते। मजार सरकारी भूमि पर है और इसके खादिमों के पास भूमि संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। जिला प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजारों को हटाने का सख्त आदेश पहले ही दे रखा है। उत्तराखंड में करीब 600 से ज्यादा अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। ●

# यूपी में सपा का चांस नहीं !

अखिलेश यादव को एक वजह बतानी चाहिए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को जनता क्यों हटाए और उन्हें सीएम क्यों बनाए? क्या इसलिए अखिलेश को सीएम बनाए कि महिलाओं का घर से निकलना दुश्वार हो जाए? क्या इसलिए चुने कि पशु चोरी, वाहन चोरी, लूट, डकैती, माफिया राज, गुंडागर्दी, गैंगस्टर राज की स्थापना हो, शायद अखिलेश के राज को कोई दोबारा नहीं देखना चाहेगा।

# 2027

शालिनी चौहान  
नई दिल्ली

में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अगले बरस होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। कांग्रेस केरल की जीत के हैंगओवर में है, यूपी के प्रमुख विपक्षी दल सपा और बसपा अभी बयानबाजी ही कर रहे हैं। कांग्रेस बसपा पर डेर डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के दो बड़े दलित सांसदों तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम को मायावती से मुलाकात के लिए भेजा गया, लेकिन बहिन जी ने सांसदों के लिए गेट ही नहीं खोला। इससे कांग्रेस की भद पिटी तो सफाई दी गई कि दोनों सांसद मायावती के आवास की तरफ से गुजरे तो शिष्टाचार भेंट करना चाहते थे। खैर राजनीति में बेइज्जत होने पर इसी तरह के तर्क दिए जाते हैं। बसपा प्रमुख मायावती गठबंधन की राजनीति से दूर रहना चाहती है। क्योंकि गठबंधन में उन्हें लाभ कम नुकसान ज्यादा हुआ है। इसलिए अधिकांश चुनावों में बसपा अकेले चुनाव लड़ने की नीति अपनाती है। यूपी में सपा को लग रहा है कि 2017 और 2022 की विफलता इस बार सफलता में बदल सकती है। इसके पीछे आधार 2024 का लोकसभा चुनाव है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 6 विधानसभा सीटें होती हैं इस हिसाब से अखिलेश यादव मान रहे हैं कि 222 सीटें उनकी पक्की हैं। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में बहुमत के लिए 202 विधायकों की आवश्यकता है। लिहाजा अखिलेश को लग रहा है कि 2024 में वो यूपी के मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे।

राजनीति पल-पल रंग बदलती है, जरूरी नहीं कि 2024 में जो नरैटिव चला था वो 2027 में भी चल जाए। लोकसभा चुनाव में भाजपा के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह 'अबकी बार 400 पार' का नारा था। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने इस नारे को पकड़ लिया। विपक्षी दलों ने जनता को 400 पार का मतलब बताया कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। बस यही बात विपक्ष जनमानस को समझाने में कुछ सफल हुआ, लेकिन सत्ता से फिर भी दूर रह गया। चुनाव बाद भाजपा को इस नारे से नुकसान का अहसास हुआ और गलतियों को सुधार गया। फिर विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। अखिलेश यादव को यकीन है कि 2027 में जनता उन्हें मुख्यमंत्री चुनेगी। इसलिए अखिलेश अभी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं बल्कि अपने जिलेवार नेताओं को बुलाते हैं,

फीडबैक लेते और जिले के नेताओं को समझा देते हैं कि 2027 में सपा की सरकार बन रही है क्षेत्र में जाओ और मेहनत करो। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल आया कि योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाएगी? क्या इसलिए कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। क्या इसलिए कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई। क्या इसलिए कि माफिया राज समाप्त हुआ है। क्या इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाएं कि गांवों में बिजली आपूर्ति बेहतर हुई है। बेरोजगारी दर कम हुई है। क्या इसलिए योगी को हटाएं कि यूपी में निवेश बढ़ा है। एक्सप्रेस-वे बने हैं, यूपी की सड़क बेहतर हुई हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। क्या योगी को इसलिए हटाएं कि यूपी में चोरी, डकैती, ऑटो लिफ्टिंग, चैन स्नेचिंग, पशु चोरी बंद हुई है। अवैध बूचड़खाने बंद हुए हैं रोड ब्लाक करके लूटपाट जैसे अपराधों पर अंकुश लगा है। आखिर अखिलेश यादव को एक वजह बतानी चाहिए कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को जनता क्यों हटाए और उन्हें सीएम क्यों बनाए? क्या इसलिए अखिलेश को सीएम बनाया जाए कि महिलाओं का घर से निकलना दुश्वार हो जाए। क्या इसलिए अखिलेश को चुने कि बिजली आपूर्ति चौपट हो जाए, पशु चोरी, वाहन चोरी, लूट, डकैती, माफिया राज, गुंडागर्दी, गैंगस्टर राज की स्थापना हो। शायद अखिलेश के राज को कोई दोबारा नहीं देखना चाहेगा। इसका ताजा उदाहरण बिहार और पश्चिम बंगाल का महाजंगल राज है। जहां न तो लालू यादव की पार्टी सत्ता में लौटी और न ही ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बन पाई।

## शिवपाल के साथ दगा हुई

2027 में यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में भी चुनाव होने हैं। यूपी में सपा मुखिया अखिलेश यादव 2022 की तरह एक बार फिर दावा करने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में

2012 में अखिलेश अपने दम पर सीएम नहीं बने थे, बल्कि मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के नाम पर सपा को बहुमत मिला था, सपा के वोट बैंक को यकीन था कि मुलायम सिंह सीएम बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने न सिर्फ वोट बैंक को धोखा दिया बल्कि शिवपाल यादव के साथ भी दगा कर दी और अखिलेश को सीएम बना दिया।



सपा की सरकार बनेगी। इसी तरह का दावा 2017 में भी किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति एसी रूम में पीसी करने और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक सिमट गई है। यही उनकी राजनीति का स्टाइल है, जमीन पर कहां वोट खिसक रहा है, कहां पार्टी के नेता निष्क्रिय हैं, कौन नेता वफादार है, कौन गद्दार है, किस पार्टी नेता को क्या जिम्मेदारी सौंपनी है, किस नेता को क्या टारगेट देना है, इस सब से अखिलेश को कोई लेना देना नहीं है। जिस नेता को विरसत में सत्ता और पार्टी मिलती है वो न तो ठीक से पार्टी संभाल पाता है और न ही सत्ता में लौट पाता है। 2012 में अखिलेश यादव अपने दम पर यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बल्कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था। सपा के वोट बैंक को यकीन था कि मुलायम सिंह सीएम बनेंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने न सिर्फ वोट बैंक को धोखा दिया बल्कि शिवपाल यादव के साथ भी दगा कर दी और अखिलेश को सीएम बना दिया। शिवपाल के लिए ये बड़ा झटका था। शिवपाल का खेमा अखिलेश की ताजपोशी से खुश नहीं था। इसके बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच तनातनी बढ़ती चली गई। यहां तक कि शिवपाल यादव को अलग पार्टी तक बनानी पड़ी।

## चाचा बनेगा विधिषण?

2016 में परिवार के बीच घमासान सबके सामने आ गया। सपा अखिलेश और शिवपाल गुट में बंट गई। बीच में मुलायम भले चुपचाप खड़े थे लेकिन वो खड़े अखिलेश के साथ थे। इसके बाद 2017 के चुनाव में सपा बुरी तरह हार गई और भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। अखिलेश की इस हार के पीछे शिवपाल की बड़ी भूमिका रही थी। 2012 के बाद शिवपाल यादव को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया उसे शायद ही कोई खुद्दर इंसान भूलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक शिवपाल यादव हैं भतीजे अखिलेश को यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे। एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को राजनीति में पैदल किया है उसके बदले में चाचा शिवपाल अपने ही भतीजे को राजनीति के नक्शे से गायब कर देंगे। यही राजनीति है, ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि क्या शिवपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी जैसे नेताओं को मिशन 'अखिलेश निपटाओ' पर लगा दिया है? क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में बात मुंह से निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। भाटी सनातन को टारगेट कर रहे हैं। हाल में भाटी ने जाट और गुर्जर समाज की

जब तक शिवपाल यादव हैं अखिलेश को यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि अखिलेश ने सत्ता के नशे में न सिर्फ शिवपाल को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया था बल्कि पार्टी से भी बेदखल कर दिया था, लिहाजा शिवपाल ने सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी जैसे नेताओं को मिशन 'अखिलेश निपटाओ' पर लगा दिया है ?

महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि 'आदमी तो कई-कई औरत खता है, लेकिन जो औरत कई कई आदमी रखती वो जाट और गुर्जरों की होती है।' इससे पहले भाटी ने हंसते हुए ब्राह्मण समाज को वैश्या से भी बदतर बताते हुए कहा था... 'ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोय, कोई-कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोय।' भाटी ब्राह्मणों को सफाईकर्मी से भी बुरा बता चुके हैं। 5 मई को दिल्ली के जवाहर भवन में पुस्तक विमोचन के दौरान ब्राह्मण समाज को जिस तरह अपमानित किया उससे बवाल होना स्वभाविक था। भाटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो गाजियाबाद भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा ने गाजियाबाद के कविनगर थाने में राजकुमार भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी दी है। भाटी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे लगता है कि चुनाव आने तक भाटी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कहीं का नहीं छोड़ेंगे।

## योगी का स्ट्राइक रेट 90 फीसदी

सपा को हराने के लिए भाजपा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सपा नेता ही हार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाए रहे हैं। जबकि 2024 में काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी, ये बार नहीं चढ़ती। 2027 में अखिलेश यादव का मुकाबला उस योगी आदित्यनाथ से है जो महाराष्ट्र जाते हैं तो भाजपा जीत जाती है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार जाते हैं तो जनता उन पर भरोसा कर भाजपा को वोट देती है। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है जहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। अब अखिलेश का स्ट्राइक रेट देख लीजिए महाराष्ट्र गए कांग्रेस एनसीपी शिवसेना को हरा आए, मध्य प्रदेश गए कांग्रेस को चालू पार्टी बता कर वोट न देने की अपील कर आए और कांग्रेस हार गई। हरियाणा गए कांग्रेस को साफ कर आए। दिल्ली गए केजरीवाल को सत्ता से बेदखल कर आए, बिहार में तेजस्वी यादव की लुटिया डुबो दी, अखिलेश पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला जमीदोज कर आए। यानी अखिलेश इतना अमंगल होने के बाद यूपी में मंगल होने का सपना देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से सत्ता छीनना चाहते हैं।

## सपा का शासन नहीं भूली जनता

अखिलेश यादव ने 2017 का पहला विधानसभा चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा, लेकिन यूपी की जनता ने उन्हें नकार दिया। यानी अखिलेश यादव अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर पाए। फिर 2022 में छोटे दलों को साथ लेकर फिर सत्ता में लौटने की हर संभव कोशिश की, चुनाव के दौरान दावे किए जा रहे थे कि बस अखिलेश यादव यूपी के कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उनकी सरकार के पांच साल की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, माफिया राज वाली छवि और यूपी में योगी आदित्यनाथ की पांच साल की सरकार की कानून व्यवस्था, माफिया राज के अंत की कहानियों और रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई ने पासा पलट दिया। योगी आदित्यनाथ की एक सख्त शासक की छवि ने अखिलेश के सीएम बनने के ख्वाब पर बुलडोजर चला दिया। अब 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है, अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा होनी है, यदि इस बार भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई तो निश्चित मानिए, सपा का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। यही अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का मिशन 2027 है। यानी इतिहास में पढ़ा जाएगा एक थी समाजवादी पार्टी। ●



भाजपा का विशेष फोकस उत्तराखंड की उन हाई रिस्क सीटों पर है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी को बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था अथवा भाजपा की जीत का अंतर मामूली था, इसके लिए भाजपा ने 'बूथ जीतो चुनाव जीतो' का नारा बुलंद किया है, इसी मंत्र के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतिक बिस्सात बिछाई जा रही है।

# अ

उत्तरांचल दीप डेस्क

गले बरस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा हैट्रिक लगाने की जी जान से कोशिश करेगी। इन्हीं कोशिशों को नतीजों में बदलने के लिए भाजपा ने मिशन 2027 का आगाज भी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में तीन दिन तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मैराथन बैठकें की। भाजपा का विशेष फोकस उन हाई रिस्क सीटों पर है, जहां पिछले चुनाव में पार्टी को बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा था अथवा भाजपा की जीत का अंतर मामूली था। इसके लिए भाजपा ने 'बूथ जीतो चुनाव जीतो' का नारा बुलंद किया है। इसी मंत्र के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की रणनीतिक बिस्सात बिछाई जा रही है। हालांकि चुनावी रणनीति वक्त की नजाकत के साथ बदलती भी रहती हैं। फिलहाल तो भाजपा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने की तैयारी में है। पन्ना प्रमुखों को एक्टिव किया जा रहा है। ताकि पिछले दो विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर भाजपा हारी थी उन बूथों पर जीत सुनिश्चित की जा सके। यही टारगेट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इसके लिए हर बूथ पर विशेष रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कोर कमेटी में शामिल पूर्व मुख्यमंत्रियों, सांसदों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रदेश कोर कमेटी के साथ बैठक में इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। बैठक का मुख्य एजेंडा 2027 के विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए जुट जाना था।

चुनाव में सफलता के लिए कोर कमेटी के सदस्यों को हर बूथ पर दो दिन का प्रवास अनिवार्य किया गया है। कोर कमेटी के सदस्यों से कहा गया है कि चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और भूमिका होती है लिहाजा सरकार-संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है।

## विपक्षी भ्रम पैदा करेगा

बैठक में लिए गए निर्णय का सार ये है कि विधानसभा क्षेत्र का एक-एक बूथ जीतने के लिए जून से अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाए। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का मानना है कि उत्तराखंड की सरकार सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचारों की सरकार है, जिसका पूर्ण बहुमत से लौटन बहुत जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड से हमेशा भगवा का संदेश देशभर में फैलता रहा है जो आगे भी फैलता रहना चाहिए। ताकि आने वाले 20 वर्षों में पार्टी मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहे और विकसित भारत का सपना साकार हो सके। इसके लिए संगठन ने तय किया है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा हर हाल में जनता तक पहुंचाना जरूरी है। वर्तमान राज्य सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल और भाजपा सरकार का पिछला 10 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है। लिहाजा सभी विधायक अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों और सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों के पंपलेट या पत्रिका छपवाकर जनता में वितरित कराएं, पंपलेट व पत्रिका को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। ताकि विपक्षी दल पब्लिक के बीच किसी तरह का भ्रम पैदा न कर सकें।

## बीजेपी का प्लान

पहले दिन कोर कमेटी की मीटिंग के बाद दूसरे दिन भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के सभी विधायकों-जनप्रतिनिधियों यानी पार्टी के सभी जिला पंचायत

**भाजपा चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्शन में है, हर विधानसभा सीट की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है, केंद्रीय नेतृत्व ने एक आंतरिक सर्वे कराया है जिसकी रिपोर्ट से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, सर्वे रिपोर्ट में भाजपा के 8 से 10 मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड उम्मीद से ज्यादा कमजोर पाया गया है, जिसके बाद से संबंधित विधायकों की नींद उड़ी हुई है।**

अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में भी उनका मुख्य फोकस 2027 के विधानसभा चुनावों में जीत पर ही था। यानी चुनावी हैट्रिक का लक्ष्य प्रमुखता से रखा गया। यदि बात की जाए बैठकों की तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तीन दिवसीय उत्तराखंड प्रवास का निचोड़ 11 बिंदुओं से समझा जा सकता है। इनमें पदाधिकारी से कार्यकर्ता तक की बूथ स्तर पर सक्रियता आवश्यक की गई है। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूत नेटवर्क तैयार कर ले तो जीत आसान होगी। जन-जन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना भी जीत की गारंटी हो सकती है। गांव स्तर के सभी लाभार्थियों से भाजपा का संपर्क हो इसके लिए अभियान की आवश्यकता है। गांव से लेकर शहर तक संगठन की पहुंच हर हाल में होनी चाहिए। वार्ड, गांव व मोहल्ला स्तर पर छोटे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं यानी छोटी बैठकें की जानी चाहिए। विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार होने से भाजपा को लाभ मिलेगा। बूथ स्तर की समितियों, शक्ति केंद्रों और इंटरनेट मीडिया के जरिए प्रचार का मजबूत तंत्र तैयार किया जा सकता है। निकाय और पंचायत जनप्रतिनिधि योजनाओं के प्रचार का मुख्य चेहरा बन सकते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करकर सकारात्मक माहौल तैयार किया जा सकता है। इससे उत्तराखंड में राष्ट्रवादी विचारों की सरकार की वापसी निश्चित होगी। अब नितिन नवीन के ये टिप्स कितने परवान चढ़ेंगे यह तो मार्च 2027 में ही पता चलेगा। लेकिन यह भी सच है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में भले ही कितने ही मतभेद क्यों न हों, पर चुनाव के समय सारे मतभेद भुलाकर चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोक देते हैं। उत्तराखंड में भी भाजपा नेताओं के बीच मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव में भीतरघात या बगावत करने वाले को राजकुमार ठुकराल बना दिया जाता है। ठुकराल रुद्रपुर से भाजपा के टिकट पर दो बार विधायक बने, लेकिन तीसरी बार टिकट कटा तो वो बगावत पर उतरे और आज वो कांग्रेस की शरण में हैं।

## कामकाज का रिपोर्ट कार्ड

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड के बेलगाम और लापरवाह मंत्रियों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारी के पेंच भी कसे। जो पदाधिकारी या मंत्री विधायक यह सोच रहे थे कि भाजपा हाईकमान उन पर नजर नहीं रखता है, तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। केंद्रीय नेतृत्व की हर नेता की गतिविधियों पर पैनी नजर रहती है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में उत्तराखंड के मंत्रियों, विधायकों और संगठन के तमाम नेताओं के कामकाज की समीक्षा शुरू हुई तो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने सभी नेताओं की 'एक्सरे रिपोर्ट' दिखा दी। यानी अंदर क्या है और बाहर क्या है सब साफ कर दिया। सबके सामने आंकड़ों के साथ उनका रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से तीन बातों पर फोकस किया गया था। पहला नेताओं के कामकाज को लेकर जनता की क्या राय है? दूसरा सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति और सक्रियता कितनी है? तीसरा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के विषय में उन्हें कितनी जानकारी अथवा ज्ञान है? ये तीन बिंदु ऐसे हैं जिनसे उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई, जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है, यानी ये वो सीटें हैं जिन्हें हाई रिस्क जोन में रखा गया है।

## विधायकों के कट सकते हैं टिकट

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अभी से पूरी तरह एक्शन में है। हर विधानसभा सीट की मॉनिटरिंग बारीकी से की जा रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक आंतरिक सर्वे कराया है जिसकी रिपोर्ट से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सर्वे रिपोर्ट में भाजपा के 8 से 10 मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड उम्मीद से ज्यादा कमजोर पाया गया है, जिसके बाद से संबंधित विधायकों की नींद उड़ी हुई है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए अभी से हर सीट का फीडबैक जुटा रहा है। सर्वे में 8 से 10 विधायकों के बेहद खराब प्रदर्शन को देखते हुए संगठन ने उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने और जनता के बीच पकड़ मजबूत करने

- भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में भले ही कितने ही मतभेद क्यों न हों पर चुनाव के समय सारे मतभेद भुलाकर चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोक देते हैं, उत्तराखंड में भी भाजपा नेताओं के बीच मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव में भीतरघात या बगावत करने वाले को राजकुमार ठुकराल बना दिया जाता है।
- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड के बेलगाम और लापरवाह मंत्रियों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारी के पेंच भी कसे, जो पदाधिकारी या मंत्री विधायक यह सोच रहे थे कि भाजपा हाईकमान उन पर नजर नहीं रखता है, तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, केंद्रीय नेतृत्व की हर नेता की गतिविधियों पर पैनी नजर रहती है।

का आखिरी मौका दिया है। माना जा रहा है कि यदि समय रहते इन विधायकों ने अपनी स्थिति और छवि में सुधार नहीं किया, तो आगामी चुनाव में इनके टिकट पर कैंची चलना लगभग पक्का है। भाजपा ऐसे किसी प्रत्याशी के साथ चुनाव में उतरना नहीं चाहेगी जिसकी वजह से उसे नुकसान हो। सर्वे रिपोर्ट और आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट कटने की अटकलों पर भाजपा के कुछ विधायकों का तर्क है कि भाजपा के सर्वे एक सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव अभी काफी दूर हैं और इस तरह के सर्वे समय-समय पर होते रहते हैं। हर एक-दो महीने में अलग-अलग एजेंसियां अपने मानकों और टारगेट क्षेत्रों के हिसाब से सर्वे करती हैं। इसलिए अभी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सर्वे की असली तस्वीर साफ होती जाएगी। फिर टिकट को लेकर अंतिम निर्णय चुनाव से दो-तीन महीने पहले होने वाले फाइनल सर्वे के आधार पर ही लिया जाएगा। उसी सर्वे के आधार पर यह तय होगा कि किन उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया जाए और किन सीटों पर नए चेहरों की जरूरत है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा किसी भी चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेती है। भाजपा नेतृत्व को किसी विधायक या सांसद की रिपोर्ट नकारात्मक मिलती है तो वो टिकट काटने में कोई संकोच नहीं करती। इसलिए जमीनी स्तर पर हर विधायक के कामकाज की कड़ी समीक्षा की जाती है और परीक्षा ली जाती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि डेंजर जोन में आए विधायक अपनी साख कैसे बचा पाते हैं। सर्वे में जिन विधायकों को 'रेड जोन' में रखा गया है, उन पर विशेष नजर रहेगी। ऐसे विधायक जिनके खिलाफ क्षेत्र में नाराजगी, निष्क्रियता या संगठन से दूरी की शिकायतें मिल रही हैं, उनके टिकट पर विचार किया जा सकता है। पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि अब सिर्फ पद या वरिष्ठता के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि प्रदर्शन ही मुख्य पैमाना होगा। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनावी सर्वे पूरी तरह संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति का हिस्सा होते हैं। जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की स्वीकार्यता, कार्यकर्ताओं से समन्वय और सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। आने वाले समय में टिकट वितरण में यही सर्वे अहम भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर, मिशन 2027 में भाजपा ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में चुनावी सफलता को बरकरार रखने के लिए अपने ही विधायकों की कड़ी परीक्षा ली जाएगी। यह प्रक्रिया जहां संगठन को मजबूत करेगी, वहीं विधायकों पर भी जनता के बीच बेहतर काम करने का दबाव बढ़ाएगी। भाजपा के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि यह तो साफ हो गया है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की बारीक नजर सभी नेताओं पर है। पहले 80 के दशक में कैसे चुनाव लड़े जाते थे और अब चुनावों में कितना बदलाव आया है, इस पर विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। एक बार विधायक बनने का मौका अगर मिला है तो फिर दोबारा विधायक बनने के लिए जमीन पर काम करना पड़ेगा। जनता के लिए हर समय मौजूद रहना होगा। ●

# बीसी खंडूड़ी का गौरवशाली सफर

2011 में जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चरम पर था, तब खंडूड़ी ने उत्तराखंड में सरका लोकायुक्त बिल पेश कर अपना इरादा बता दिया था, उत्तराखंड की राजनीति में जब भी ईमानदारी, सादगी और अनुशासन की बात होगी, तो सबसे टॉप पर पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का नाम लिया जाएगा।



## भा

राज्य राजनीति और सैन्य इतिहास में बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान से लेकर सियासत के अखाड़े तक अपनी ईमानदारी और अनुशासन की प्रतिबद्धता का परचम समान रूप से लहराया हो। इनमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (रिटायर्ड) एक ऐसे राजनेता हुए, जिनका जीवन देश की सेवा और सुशासन के लिए समर्पित रहा। खंडूड़ी का जन्म ब्रिटिश काल के भारत में एक अक्टूबर, 1934 को देहरादून में हुआ था, पर उनका पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल का मरगदना गांव है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। बचपन से ही अनुशासन और देश सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रही। भुवन चंद्र खंडूड़ी ने युवावस्था में ही भारतीय सेना को अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना। वह सेना के 'कोर ऑफ इंजीनियर्स' (मद्रास सैपर्स) में शामिल हुए। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों में देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेना में उनके अद्वितीय नेतृत्व और समर्पण के लिए उन्हें 'अति विशिष्ट सेवा पदक' से सम्मानित किया गया था। वह 1990 में मेजर जनरल के प्रतिष्ठित पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद खंडूड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वह पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्वर्णिम चतुर्भुज योजना' को धरातल पर उतारने का मुख्य श्रेय जनरल खंडूड़ी को ही जाता है। उनके कुशल प्रबंधन की वजह से देश के चार महानगरों को जोड़ने वाले हाईवे नेटवर्क का काम रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण भारत



अफजल फौजी  
नैनीताल

की सूरत बदलने में भी उनकी अहम भूमिका रही। केंद्रीय राजनीति में खंडूड़ी को 'सड़क पुरुष' के रूप में एक नई पहचान मिली थी।

### दो बार सीएम रहे खंडूड़ी

सैन्य पृष्ठभूमि से राजनीति में आए भुवन चंद्र खंडूड़ी दो बार (2007 से 2009 तक और फिर 2011 से 2012 तक) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। राज्य के विकास के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम आज भी मील का पत्थर माने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में कड़ा अनुशासन लागू किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश का सबसे मजबूत और पारदर्शी 'लोकायुक्त' विधेयक राज्य विधानसभा से पारित कराया, जिसके दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स को भी लाया गया था। इस कदम की देश भर में सराहना हुई। उनके कार्यकाल में सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कॉपी साथ ले जाने की अनुमति जैसी व्यवस्थाएं शुरू की गईं। एक अमिट विरासत मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का 19 मई 2026 को गोलोक धाम जाना न केवल उत्तराखंड बल्कि राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। राजनीति में शुचिता, सादगी और कड़े नीतिगत फैसलों के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी बेटी ऋतु खंडूरी वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी इस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जनरल खंडूड़ी का अनुशासित और बेदाग जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।

**बीसी खंडूड़ी ईमानदार छवि के नेता थे, इसलिए सीएम रहते हुए उन्होंने सरकारी खर्च में कटौती की, साथ ही सरकार में अनुशासन को प्राथमिकता दी, उन्होंने सीएम बनते ही नेताओं, मंत्रियों और अफसरों से समय का पालन करने की अपील की थी।**

### खंडूड़ी की सार्वजनिक छवि

उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूड़ी को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में लाए थे। ये 1990 का कालखंड था, जब खंडूड़ी सेना से रिटायर हुए थे। भुवन चंद्र खंडूड़ी की गिनती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भरोसेमंदों में होती थी। पहली बार लोकसभा पहुंचने के दो साल के भीतर ही खंडूड़ी को पार्टी का मुख्य सचेतक बना दिया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में खंडूड़ी को हार का सामना करना पड़ा। 1999 में अटल बिहारी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। इस दौर में देश में सड़कों की शक्ति बदलने और हाईवे बनाने का काम हुआ जिसके लिए खंडूड़ी की आज तक प्रशंसा होती है। कहा जाता है कि वाजपेयी का खंडूड़ी पर इतना भरोसा था कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी थी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहते हुए लोकायुक्त विधेयक लाकर बीसी खंडूड़ी ने ऐतिहासिक कदम उठाया था। अपनी दूसरी पारी में 2011 में बीसी खंडूड़ी ने उत्तराखंड में सबसे सख्त लोकायुक्त कानून पास कराया। जिसमें बेइमानी चाहे सीएम करे या मंत्री, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स सभी को जांच के दायरे में आ गए। इस कानून के दायरे में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का नियम रखा गया था। हालांकि ये बात अलग है कि आज उत्तराखंड में लोकायुक्त की हैसियत क्या है? लोकायुक्त कहां है? किसी को शायद पता भी नहीं है। पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के काम करने का अंदाज भी अपने आप में सख्त था। यानी फाइल प्रोसेसिंग में तेजी, जन शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर जोर था। साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर में पारदर्शिता लाने की कोशिशें की। इसके लिए उन्होंने कई सुधार किए। बीसी खंडूड़ी को ई-गवर्नेंस और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए भी जाना जाता है।

### भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा दिया

मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी सैन्य अधिकारी रहे, इसलिए वे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते और करते थे। इसके लिए वे सख्त राजनेता के तौर पर जाने जाते थे। वे किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा भी दिया था। जिससे राज्य के साथ ही देश में उनकी अलग छवि बनी। बीसी खंडूड़ी ईमानदार छवि के नेता थे, इसलिए उन्होंने सरकारी खर्च में कटौती की, साथ ही सरकार में अनुशासन को प्राथमिकता दी। उन्होंने सीएम बनते ही नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से समय का पालन करने की अपील की थी। साथ ही वो खुद परियोजनाओं में फंड या बजट को समय से खर्च करने के पक्षधर थे। खंडूड़ी का योगदान उत्तराखंड के विकास और सुशासन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वे उत्तराखंड के अनुशासित,

कर्मठ और दूरदर्शी नेता भी थे। बीसी खंडूड़ी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास को नई दिशा दी। खंडूड़ी को उनके ऐतिहासिक फैसलों के लिए भी जाना जाता रहेगा। 2011 में जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चरम पर था, तब जनरल खंडूड़ी ने उत्तराखंड में देश का सबसे पहला और सख्त लोकायुक्त बिल पेश कर अपना इरादा बता दिया था। उनकी सादगी, स्पष्टवादिता और कार्यकुशलता सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी। लिहाजा उत्तराखंड की राजनीति में जब भी ईमानदारी, सादगी और अनुशासन की बात होगी, तो सबसे टॉप पर पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का नाम लिया जाएगा।

### खंडूड़ी का सबसे कठिन दौर

उत्तराखंड में 2009 में डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने, 2011 में भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही थी जिसे शांत करने के लिए 11 सितंबर को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम की कुर्सी से हटाकर एक बार फिर बीसी खंडूड़ी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। ताकि उनकी बेदाग छवि का फायदा 2012 के चुनाव में उठाया जा सके। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ रही थी, वैसे भी उत्तराखंड में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही थी, जिसे भाजपा तोड़ना चाहती थी। इसलिए 2012 का विधानसभा चुनाव खंडूड़ी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर साबित हुआ। वो खुद कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, पर उनकी व्यक्तिगत छवि पर कभी दाग नहीं लगा। मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी की सियासी शैली भले ही कठोर मानी जाती रही हो, लेकिन राजनीति में विरोधी दलों के नेता भी उनकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर यह कहा जाता था कि अगर सिस्टम में खंडूड़ी जैसे दो-चार नेता और होते तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ अलग ही होती। यह बात उनकी सार्वजनिक छवि को समझने के लिए बड़े मायने रखती है।

### तीन दिन के राजकीय शोक

आर्मी की पृष्ठभूमि से राजनीति में प्रवेश करने वाले जनरल बीसी खंडूड़ी ने अपने सार्वजनिक कार्यकाल के दौरान सुशासन, पारदर्शिता, विकास, ईमानदारी और अनुशासन की नजीर बन गए थे। समय की पाबंदी और बेबाक संवाद की वजह से उन्हें पर्वतीय राज्य की सियासत में बेदाग छवि वाले नेता के रूप में जाना गया। यानी मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का जीवन संघर्ष, अनुशासन और

- भुवन चंद्र खंडूड़ी ने युवावस्था में ही सेना को अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना, वो सेना के 'कोर ऑफ इंजीनियर्स' (मद्रास सैपर्स) में शामिल हुए, उन्होंने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, सेना में उनके अद्वितीय नेतृत्व के लिए 'अति विशिष्ट सेवा पदक' से सम्मानित किया गया।
- 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बीसी खंडूड़ी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया, इस दौर में देश में सड़कों की शक्ति बदलने और हाईवे बनाने का काम हुआ जिसके लिए खंडूड़ी की आज तक प्रशंसा होती है, कहा जाता है कि वाजपेयी का खंडूड़ी पर इतना भरोसा था कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी थी।

राष्ट्रसेवा को समर्पित रहा। उनका मानना था कि सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए, न कि सुविधा का। यही कारण था कि वह लालबत्ती संस्कृति और अनावश्यक सरकारी तामझाम से दूरी बनाए रखते थे। सचिवालय में आज भी उनके सख्त प्रशासन और तेज निर्णय क्षमता की कहानियां सुनाई जाती हैं। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन के साथ ही उत्तराखंड की राजनीति का वह दौर भी मानो समाप्त हो गया, जिसमें सिद्धांत, सादगी और नैतिकता की मजबूत मौजूदगी दिखाई देती थी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। खंडूड़ी के निधन से उत्तराखंड की राजनीति और सार्वजनिक जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय हमेशा के लिए इतिहास बन गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सेना के जांबाज अधिकारी मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने 91 वर्ष की आयु में देह त्याग दी। हालांकि वो काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद भावुक नजर आए। खंडूड़ी के निधन की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से तत्काल देहरादून लौटे बल्कि 20 मई को हरिद्वार में उनकी अंत्येष्टि में भी शामिल हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रति जनरल खंडूड़ी के योगदान को नमन करते हुए, राज्य में तीन दिन के राजकीय शोक के साथ, एक दिन के अवकाश की घोषणा की। ●



# टीएमसी खत्म हो जाएगी?

टीएमसी के कुछ नेताओं ने तो चुनाव के तुरंत बाद भाजपा में शामिल होने का जुगाड़ भी लगाया, लेकिन भाजपा में फिलहाल नो इंट्री का बोर्ड लगा है, जैसे अब साफ हो गया है कि टीएमसी एक राजनीतिक दल नहीं रहा, वो आई-पेक कंपनी बन गई और जब कोई पार्टी कंपनी बन जाती है तब उसका अस्तित्व पतन की ओर जाता है।

# प



उदयभाज सिंह  
लेखक

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का अब क्या होगा? क्या बंगाल से कांग्रेस व सीपीआई की तरह टीएमसी भी खत्म हो जाएगी? यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन ममता बनर्जी उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी और टीएमसी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के कारण टीएमसी का सांगठनात्मक ढांचा रेत की दीवार के तरह बिखर रहा है। सांगठनात्मक ढांचे की बात करें तो ममता बनर्जी के चुनाव हारने के बाद पार्टी का मध्यम-स्तर का कैडर लगभग बिखर गया है। कई नगर पालिकाओं में 100 से अधिक पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक बनर्जी के गढ़ फालता में रिपोलिंग से पहले यूपी के आईपीएस अधिकारी को धमकी देने वाले टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान ने जिस तरह चुनाव मैदान छोड़ा उसने क्या टीएमसी का भविष्य बता दिया? फिर फालता विधानसभा चुनाव के जैसे परिणाम आए उससे साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का किस तरह दबा कर रखा गया था। भले ही राजनीति के जानकार ये कहें कि टीएमसी के पास महिलाओं व अल्पसंख्यकों का पारंपरिक वोट जीत का आधार था, लेकिन सच ये नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में आम आदमी खासकर हिंदुओं के वोट डालने का अधिकार ममता बनर्जी और उनके भतीजे के गुंडों ने

हाईजैक कर रखा था। इस बार चुनाव आयोग की सख्ती के कारण लोगों ने बेखौफ होकर मतदान किया तो ममता बनर्जी की पार्टी का सूफड़ा साफ हो गया।

## टीएमसी नेताओं से जनता नाराज

अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या जिस तरह पश्चिम बंगाल से कांग्रेस और सीपीआई (एम) समाप्त हो गई है वैसे ही टीएमसी भी खत्म हो जाएगी? क्योंकि चुनाव के बाद पब्लिक की ममता सरकार से नाराज का नजारा रोज बंगाल में देखने को मिल रहा है। टीएमसी के गुंडों को जनता दौड़ा-दौड़ा कर पीट रही है। ममता बनर्जी हों या उनके सांसद और विधायक उन्हें देखते ही जनता चोर-चोर के नारे लगाने लगती है। टीएमसी सांसद सौगत राय को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनका घेराव किया और अंडे फेंककर अपमानित किया। पुलिस ने किसी तरह उनकी इज्जत बचाई। टीएमसी नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। टीएमसी के तमाम नेताओं ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि आई-पेक ने टीएमसी संगठन पर कब्जा कर लिया था। जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। एक और टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बारासात के टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए आई-पेक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक बाहरी कंसल्टेंट्स के फैसले पार्टी पर थोपने से नुकसान हुआ। टीएमसी सरकार में मंत्री रहे मानस भुइयां सबंग विधानसभा सीट से हार गए। इसके बाद उन्होंने आई-पेक की भूमिका की समीक्षा की मांग कर दी। टीएमसी के ही निर्लंबित प्रवक्ता रीजू दत्ता का आरोप है कि आई-पेक ने टीएमसी को हाईजैक कर लिया था। उनके कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी के नाम का इस्तेमाल करके नेताओं व कार्यकर्ताओं को उराते-धमकाते थे। टीएमसी के ही पूर्व विधायक खगेश्वर राय ने पार्टी की हार के लिए आई-

**ममता बनर्जी का 15 वर्षों पुराना किला तिनके की तरह बिखर गया, ममता बनर्जी 88 सीटों पर सिमट गई और भाजपा 207 सीटों की प्रचंड जीत के साथ सत्ता में पहुंच गई, ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट को 1 आम जनता उन्नयन पार्टी को 2 कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (एम) 1 और कांग्रेस 2 सीटें जीत पाई, यही टीएमसी के पतन की शुरुआत है।**

पेक को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि आई-पेक जमीनी कार्यकर्ताओं की राय जाने बिना उम्मीदवारों और चुनाव अभियान का फैसला कर रही थी। ये वो नेता है जिनकी आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन अब वो आवाज बुलंद कर रहे हैं और टीएमसी की हार के कारण बता रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो चुनाव के तुरंत बाद भाजपा में शामिल होने का जुगाड़ भी लगाया, लेकिन भाजपा में फिलहाल नो इंट्री का बोर्ड लगा है। वैसे अब साफ हो गया है कि टीएमसी एक राजनीतिक दल नहीं रहा, वो आई-पेक कंपनी बन गई और जब कोई पार्टी कंपनी बन जाती है तब उसका अस्तित्व पतन की ओर जाता है।

## बंगाल में कांग्रेस व सीपीआई हासिये पर

कांग्रेस ने लगभग 20 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में शासन किया। कांग्रेस का मुख्य शासनकाल आजादी के तुरंत बाद से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक रहा है। इसके बाद सीपीआई (एम) वाम मोर्चे ने 34 वर्षों (1977 से 2011 तक) तक पश्चिम बंगाल पर शासन किया। यह दुनिया की सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकारों में से एक थी। देश की आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सत्ता थी। क्योंकि उस दौर में कांग्रेस के मुकाबले कोई दूसरा दल मजबूत नहीं था। इसलिए देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही। लेकिन 1977 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कमजोर पड़ी। क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया था। स्थानीय नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस पश्चिम बंगाल से समाप्त हो गई। यानी 1977 के बाद कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कभी बहुमत हासिल नहीं हुआ। 1970 के दशक के अंत में वामपंथी दलों ने किसानों और मजदूर वर्ग के बीच मजबूत जनाधार बनाया, जिससे कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक खिसक गया। किंतु औद्योगिकरण की विफल नीतियों, सिंगूर-नंदीग्राम आंदोलनों, जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर की दादागिरी, हिंसा, गुंडागर्दी, लूटपाट, भ्रष्टाचार और राज्य में अराजकता तथा सत्ता के नशे में जनता से बढ़ती दूरी के कारण सीपीआई (एम) का पतन हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम में औद्योगिकरण की जल्दबाजी में वामपंथी सरकार ने उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जिसके खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इन आंदोलनों ने गरीबों और किसानों की पार्टी सीपीआई की छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया।

## सीपीआई के रास्ते चली टीएमसी

सीपीआई (एम) चूक 34 साल तक सत्ता में रही इसलिए उसके निचले स्तर तक फैले पार्टी कार्यकर्ताओं (कैडर) की प्रशासनिक दखलंदाजी से आम जनता परेशान हो चुकी थी। वामपंथी, विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की संस्कृति पर उतर आए। जिससे जनता में बदलाव की भावना जागृत होने लगी थी। तीन दशक के लंबे शासन के बावजूद पश्चिम बंगाल में रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हुए, जिससे युवा वर्ग पार्टी से दूर होता चला गया। बदलते समय के साथ वामपंथी नेतृत्व आम जनता से दूर होता चला गया। तभी ममता बनर्जी का उदय हुआ। 1990 के दशक में कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन कर ममता बनर्जी ने सीपीआई के जनविरोधी मुद्दों को उठाना शुरू किया और परिवर्तन का ऐसा मजबूत विकल्प दिया कि वामपंथी सत्ता से बाहर हो गए। सत्ता में आने के बाद टीएमसी भी सीपीआई के हिंसा, गुंडागर्दी के उसी रास्ते पर चल दी जिससे जनता नाराज थी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर टीएमसी के लगभग हर नेता और कार्यकर्ता ने पश्चिम बंगाल में एक तरह से लूट मचा रखी थी। लिहाजा टीएमसी पर भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के साथ सरकारी नौकरियों में घोटालों, बुनियादी ढांचे के निर्माण में कट-मनी से आम जनता में गहरा रोष पनपने लगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कांड से 2024 में देश भर में आंदोलन हुए। जिससे राज्य की कानून-व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। हालांकि ममता बनर्जी सरकार ने इस केस को दबाने की कोशिश भी की। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन पर कब्जे कर लिए। बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ करने वालों को सरकारी योजनाओं का खुल कर लाभ दिया गया।

## पुराना ममता का किला बिखर गया

घुसपैठियों के आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवा दिए, बैंक में खाते खुलवा दिए। ये घुसपैठिये पश्चिम बंगाल की जनता के हक पर डाका डालने लगे। घुसपैठियों की

**पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम का कहना है कि टीएमसी का जनाधार इस भीषण गर्मी में बर्फ की तरह पिघल रहा है, लिहाजा एक सीट जीतने वाले वामदल को उम्मीद है कि वह जल्द ही टीएमसी को पछाड़कर राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ जाएगा।**

वजह से राज्य में अपराध तेजी से बढ़े, लेकिन अपराध करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। संदेशखाली में महिलाओं का उत्पीड़न कैसे भुलाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 पराना जिले के संदेशखाली में 2024 की शुरुआत में टीएमसी नेता शाहजहां शेख द्वारा बड़े पैमाने पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना और जमीन हड़पने का खुलासा हुआ तो देश हैरान रह गया। संदेशखाली की महिलाओं का कहना था कि टीएमसी नेता और उनके गुर्गे महिलाओं को देर रात पार्टी कार्यालयों में बुलाते थे और उनका यौन शोषण करते थे। विरोध करने पर उनके पतियों और परिवार के पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता था। शाहजहां शेख चीख-चीख कर कहता था कि वो बांग्लादेशी है। शाहजहां शेख को ममता बनर्जी का पूरा संरक्षण था। इसलिए अपराधियों के खिलाफ पुलिस केस तक दर्ज नहीं करती थी। ऐसे तमाम कारणों से 15 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर बनी। जिसका फायदा भाजपा को मिला और ममता बनर्जी का 15 वर्षों पुराना किला तिनके की तरह बिखर गया। ममता बनर्जी 88 सीटों पर सिमट गई और भाजपा 207 सीटों की प्रचंड जीत के साथ सत्ता में पहुंच गई। ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट को 1 आम जनता उन्नयन पार्टी को 2 कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (एम) 1 और कांग्रेस 2 सीटें जीत पाई। यही टीएमसी के पतन की शुरुआत है।

## वामपंथियों को अभी भी उम्मीद

2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की तुलना 2011 के विधानसभा चुनाव से की जाए तो तब सीपीआई (एम) 62 सीटों पर लुढ़क गई थी जबकि ममता बनर्जी ने यूपीए गठबंधन के साथ 227 सीटों के भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाली थी। 2026 में यह पासा पलट गया, यानी भाजपा 207 सीटों के साथ सत्ता में है और टीएमसी 88 सीटों के साथ सीपीआई (एम) की तरह विपक्ष में। केरल की हार के बाद सीपीआई ही नहीं वामपंथी सत्ता का देश से सूफड़ा साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल का इतिहास गवाह है यहां की जनता किसी भी पार्टी को जल्दी से सत्ता से बेदखल नहीं करती और जब सत्ता से बाहर करती है तो फिर राजनीतिक दलों को अस्तित्व तक समाप्त कर देती है। 1977 में कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हुई तो फिर पश्चिम बंगाल की सत्ता का मुंह नहीं देख पाई। जिस तरह 2011 में सीपीआई (एम) को 34 साल के शासन के बाद पश्चिम बंगाल की जनता ने ठुकराया उसे फिर इस राज्य में सत्ता नसीब नहीं हुई। पश्चिम बंगाल का यही इतिहास नहीं है बल्कि एक और इतिहास है वो ये कि जब जनता किसी पार्टी या नेता का समर्थन करती है तो बंपर जीत के साथ करती है। दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल की जनता ने कांग्रेस 20 साल, दिए, सीपीआई को 34 साल दिए, टीएमसी को 15 साल दिए। इस हिस्ट्री को देखकर लगता है कि ममता बनर्जी के लिए कम से कम सत्ता में वापसी के लिए 15 साल तो लगेंगे ही। वो भी तब जब 15 साल तक टीएमसी का अस्तित्व बना रहे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सत्ता से जो भी दल बेदखल हुआ है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। इसलिए पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम का कहना है कि टीएमसी का जनाधार इस भीषण गर्मी में बर्फ की तरह पिघल रहा है। लिहाजा एक सीट जीतने वाले वामदल को उम्मीद है कि वह जल्द ही टीएमसी को पछाड़कर राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ जाएंगे। सलीम का कहना है कि टीएमसी ने पिछले डेढ़ दशक के अपने शासनकाल में पुलिस और बाहुबलियों का जमकर दुरुपयोग किया है। इस दमनकारी नीति की वजह से ही आरएसएस और भाजपा को राज्य के ग्रामीण इलाकों में अपने पैर पसारने का अनुकूल माहौल मिला। सलीम ने कहा कि टीएमसी और भाजपा दोनों ही दल धर्म के नाम पर राजनीति करके वामपंथ को मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब राज्य की जनता विकल्प के तौर पर वाम मोर्चे की ओर देख रही है। ●



# ट्रंप के जाल में फंसा पाक

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसीम मुनीर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाने के लिए खलीफा की भूमिका निभाने चले थे, युद्ध भले ही नहीं रुका हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भले न खुला हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाल में पाकिस्तान के पीएम और फील्ड मार्शल ऐसे फंसे हैं कि आगे कुआ है और पीछे खाई है।

# पा

केके चौहान

किस्तान के फील्ड मार्शल आसीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाने के लिए खलीफा की भूमिका निभाने चले थे। युद्ध भले ही नहीं रुका हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भले ही न खुला हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चाल में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसीम मुनीर ऐसे फंसे हैं कि आगे कुआ है और पीछे खाई है। ट्रंप ने ईरान युद्ध खत्म करने के लिए होने वाले किसी भी समझौते पर पाकिस्तान को इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले 'अब्राहम अर्कोईस' पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रखा है। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर जैसे देशों को 'अब्राहम अर्कोईस' का हिस्सा बनना चाहिए। इस समझौते की शुरुआत 2020 में डॉनल्ड ट्रंप ने ही अपने पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल में की थी। समझौते का नाम अब्राहम यानी पैगंबर इब्राहिम के नाम पर रखा गया था। इब्राहिम को यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों में बेहद

सम्मान दिया जाता है। लिहाजा अमेरिका ने इस नाम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि यह समझौता धार्मिक संघर्ष नहीं बल्कि साझा विरासत और साथ रहने की दिशा में उठाया गया कदम है। मीडिल ईस्ट की राजनीति में पिछले कुछ सालों में अगर किसी एक समझौते ने सबसे बड़ा बदलाव किया, तो वो यही अब्राहम अर्कोईस (अब्राहम समझौता) था। 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इन समझौतों ने दशकों पुरानी अरब वर्ल्ड की सोच को बदल दिया था। जिन अरब देशों ने सालों तक इजरायल को मान्यता नहीं दी थी, वो इस समझौते के बाद इजराइल के साथ दोस्ती, व्यापार और सुरक्षा साझेदारी करने लगे। उस समय इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी विदेशनीति की जीत के तौर पर देखा गया था। अब ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इस समझौते को मिडिल ईस्ट के और देशों तक फैलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किये और यहां तक कि ईरान को भी इस बड़े समझौते का हिस्सा बनने के लिए कहा है। हालांकि गाजा युद्ध, फिलिस्तीन विवाद और ईरान-इजरायल तनाव के बीच ट्रंप का यह सपना पूरा होना फिलहाल काफी मुश्किल माना जा रहा है। किंतु पाकिस्तान में तो बहस छिड़ गई है। कट्टरपंथी किसी कीमत पर इजराइल को मान्यता देने के पक्ष में नहीं हैं। वैसे भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्पष्ट रूप से मुद्रित है कि यह दस्तावेज इजराइल को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी देशों के लिए

**पाकिस्तान सरकार जानती है कि इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, तो देश में धार्मिक पार्टियां, इस्लामी संगठन, दक्षिणपंथी मीडिया और मुख्यधारा के कई राजनीतिक दल और नेता इजराइल को मान्यता देने के फैसले को फिलिस्तीन और पाकिस्तान की विचारधारा के साथ विश्वासघात बताएंगे।**

मान्य है। यानी कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट से इजराइल की यात्रा तक नहीं कर सकता ऐसे में ट्रंप का पाकिस्तान पर दबाव कितना कारगर होगा यह भविष्य में पता चलेगा।

## पाक नहीं मान रहा ट्रंप का आदेश

पाकिस्तान, इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि जब तक फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक इजराइल के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य करना रणनीतिक फैसला कम और दबाव में झुकने जैसा ज्यादा लगेगा। फिलहाल इसका नुकसान ज्यादा और फायदा कम नजर आता है। इसलिए कुछ पाकिस्तानी अधिकारियों ने अमेरिका की इस मांग को खारिज कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उनका इजरायल को मान्यता देने और अब्राहम अर्कोईस में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा- हम इजरायल को लेकर अपनी पुरानी नीति पर कायम हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह बयान अमेरिका प्रवास के दौरान तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से अब्राहम अर्कोईस में शामिल होने के लिए कहा था। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की हमेशा से स्पष्ट नीति रही है। यह नीति फिलिस्तीन को मान्यता देने और देश मानने से जुड़ी है। पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दोहराते हुए कहा कि वे इजराइल के साथ नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान का स्टैंड साफ है कि जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक वह इजरायल को मान्यता नहीं देगा। यानी पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत जुटा ली है कि उसने दुनिया के महाशक्ति देश और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को टुकरा दिया। हालांकि ये बयान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की तरफ से नहीं आए हैं। फिर जिस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ मोहरा हो और सारी ताकत फील्ड मार्शल के पास हो उस देश के मंत्रियों की क्या हैसियत होगी ये पाकिस्तानी अच्छे से जानते हैं। इसका सबूत ये है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ की है। व्हाइट हाउस में एक साथ लंच किया है। जब ट्रंप ने असीम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल कहा तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी। बार-बार तारीफ के अलावा भारत की तुलना में ट्रंप ने पाकिस्तान को ज्यादा महत्व दिया। अब ट्रंप ने पाकिस्तान पर तारीफ की कीमत चुकाने का दबाव बनाया है। लेकिन हैसियत न होते हुए भी पाकिस्तान के दो-दो मंत्रियों ने ट्रंप की बेइज्जती तो कर ही दी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपमानित करना पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ गहरे आर्थिक और सैन्य संबंध हैं जो उसे अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी देश भारत के साथ भू-रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

## पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शनों का खतरा

ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित ही नहीं है बल्कि पूरी तरह चौपट हुई है। युद्ध शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो जाए, लेकिन ईरान युद्ध के साथ ट्रंप की अब्राहम अर्कोईस वाली मांग ने पाकिस्तान को ऐसी मुश्किल स्थिति में डाल दिया है, जहां से निकलना मुश्किल होगा। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानती है कि अगर इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की, तो देश में इसका भारी विरोध हो सकता है। पाकिस्तान की धार्मिक पार्टियां, इस्लामी संगठन, दक्षिणपंथी मीडिया और मुख्यधारा के राजनीतिक दल और नेता इजराइल को मान्यता देने के फैसले को फिलिस्तीन और पाकिस्तान की विचारधारा के साथ विश्वासघात बताएंगे। यदि पाकिस्तान सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है, तो देश में हिंसक प्रदर्शन, अस्थिरता, संसद में सरकार की आलोचना, धार्मिक नेताओं की तरफ से विरोध, कट्टरपंथी मौलानाओं के फतवे और सरकार पर अमेरिका या खाड़ी देशों के दबाव में काम करने के आरोप लगेगा। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अब्राहम अर्कोईस में शामिल होने या नहीं होने के मुद्दे पर लिया गया फैसला देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अब्राहम अर्कोईस में शामिल होने के कुछ फायदे जरूर हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर इन्हें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान को वॉशिंगटन

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वे इजराइल के साथ नहीं बैठ सकते, पाकिस्तान का स्टैंड साफ है कि जब तक 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक वह इजरायल को मान्यता नहीं देगा, यानी पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को टुकरा दिया।

और कुछ खाड़ी देशों से कूटनीतिक समर्थन मिल जाएगा। साथ ही आर्थिक और तकनीकी अवसर भी खुल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बड़े खतरे भी हो सकते हैं। इससे फिलिस्तीन मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ सकती है।

## अरब देश कर चुके हैं समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपना पसंदीदा भी बताया। ट्रंप से बढ़ती नजदीकी की वजह से ही इस समय पाकिस्तान की वैश्विक अहमियत बढ़ी है। लेकिन ईरान युद्ध में मध्यस्थता करने की तुलना में अब्राहम अर्कोईस में शामिल होना पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर ही सितंबर 2020 में सबसे पहले इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ रिश्ते सामान्य करने के समझौते किए थे। इसके बाद मोरक्को और सूडान भी इसमें शामिल हो गए थे। इन समझौतों के बाद दूतावास खुले, सीधी फ्लाइट शुरू हुई, व्यापार और निवेश बढ़ा, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग शुरू हुआ, पर्यटन और रक्षा साझेदारी मजबूत हुई। मिडिल ईस्ट में पहली बार ऐसा माहौल बना कि अरब देश और इजरायल खुलकर साथ काम करने लगे। कुछ ही दिनों में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद प्रमुख का खाड़ी देशों में वीआईपी स्वागत किया गया था, जो इस समझौते से पहले तक असंभव था। लेकिन जिस अब्राहम समझौतों का जोर-शोर से प्रचार किया गया और जिनके तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान सभी ने इजरायल के साथ समझौते किए थे उस पर जमीनी हालात का असर सबसे बड़ा दिखा। इजराइल को लेकर अरब देशों में हिंसा हुई। अरब देशों ने इजरायल के साथ संबंध में किसी भी तरह की गर्मजोशी को रोक दिया था। इससे पहले भी इजरायल ने अरब देशों के साथ शांति समझौते किए थे। मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में, लेकिन ये समझौते युद्ध खत्म करने के लिए किए गए थे। जबकि अब्राहम समझौते के मायने अलग हैं। अब्राहम समझौते में दोस्ती की भाषा थी, आर्थिक साझेदारी, व्यापार, जैसे मुद्दे शामिल थे।

## सऊदी की आड़ में पाकिस्तान

कुल मिलाकर पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होना या न होना इस बात पर निर्भर करेगा कि सऊदी अरब इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। इस्लामाबाद और रियाद के बीच मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध हैं। साथ ही इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक के रूप में सऊदी अरब को अधिकांश पाकिस्तानी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगर सऊदी अरब पहले कदम उठाता है, तो पाकिस्तान के लिए इस मुद्दे पर बात करना आसान हो जाएगा। लेकिन यह उतना सरल नहीं होगा। इस्लामाबाद, रियाद के फैसले का इस्तेमाल खुद को ढकने के लिए कर सकता है। वैसे भी पाकिस्तान आम तौर पर मिडिल ईस्ट से जुड़े फैसले सऊदी अरब और खाड़ी देशों के रुख को देखकर लेता है। फिर भी पाकिस्तान के लिए यह कदम अभी भी बहुत जटिल बना रहेगा। वैसे पाकिस्तान कोई अरब राजशाही देश नहीं है। ये वो देश है जो जकात और उधार पर चलता है। फिर पाकिस्तान की घरेलू राजनीति, धार्मिक दल, मीडिया और फिलिस्तीन के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने को कहीं ज्यादा मुश्किल बना देता है। अगर सऊदी अरब इजरायल को पहले मान्यता दे देता है, तो पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम वैचारिक आपत्तियों के बावजूद इस फैसले को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा न करने पर उस पर कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर अलग-थलग पड़ने का खतरा होगा। यही वजह है कि ट्रंप का हुकूम सऊदी अरब के लिए हुकूम का इक्का साबित हो सकता है। इसलिए ट्रंप इसे ईरान युद्ध से बाहर निकलने का सेफ रास्ता और पूरे क्षेत्र के नए नक्शे के तौर पर पेश कर रहे हैं। ●

# टेंशन में मदरसा संचालक

धामी की सरकार ने जब सर्वे कराया था तब राज्य में 950 मदरसे चिह्नित हुए थे, यानी करीब 300 मदरसे बिना सरकार की अनुमति के अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, लिहाजा इन अवैध मदरसों पर सरकार ने पहले ही ताला जड़ दिया है, हैरानी की बात ये है कि उत्तराखंड के मदरसों में बिहार, असम, यूपी, झारखंड केरल आदि से मुस्लिम बच्चे लाकर पढ़ाए जा रहे थे।

# 3



दिनेश मानसेरा  
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में बड़े बदलाव की बयार चल रही है। बदलती डेमोग्राफी और गली मोहल्लों में खुल चुके मदरसों पर धामी सरकार का चाबुक चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मदरसा बोर्ड खत्म करके उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन और नए शैक्षिक सत्र के लिए, प्राधिकरण और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेने की अनिवार्य शर्त के बाद राज्य में मदरसा शिक्षा व्यवस्था संकट में पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देवभूमि में 'मदरसे खत्म ही हो जाएंगे' इस बारे में चर्चाएं इस लिए तेज हो गईं

है, क्योंकि शायद ही कोई मदरसा प्रबंध समिति उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के नॉर्मस को पूरा कर पाए। हालांकि धामी की कैबिनेट ने कक्षा 8 तक के लिए जिला विद्यालय समिति को मान्यता का अधिकार दे दिया है, यही व्यवस्था पहले भी थी। इंटरमीडिएट की मान्यता के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा बोर्ड में आवेदन करना होगा। बड़ा सवाल ये है कि मस्जिदों और छोटे-छोटे कमरों के निजी भवनों में चलने वाले मदरसों को मान्यता के आवेदन करने से पहले वो दस्तावेज जुटाने होंगे जो नियमानुसार चाहिए होंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में 452 मदरसे पंजीकृत हैं जिनकी मान्यता 30 जून को खत्म हो जाएगी। राज्य में 192 मदरसे ऐसे थे जो केंद्र और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त थे। वक्फ बोर्ड ने 117 मदरसों को अपने यहां पंजीकृत कर रखा है। इन पंजीकृत मदरसों में 46 हजार बच्चे पढ़ रहे थे। लिहाजा अब इन सभी मदरसों को एक जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से संबद्धता और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जब सर्वे कराया था तब राज्य में 950 मदरसे चिह्नित हुए थे। यानी तकरीबन 300 मदरसे बिना सरकार की अनुमति के अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, लिहाजा इन अवैध मदरसों पर सरकार ने पहले ही ताला जड़ दिया है। हैरानी की बात ये है कि उत्तराखंड के मदरसों में बिहार, असम, यूपी, झारखंड केरल आदि राज्यों से मुस्लिम बच्चे लाकर पढ़ाए जा रहे थे। सर्वेक्षण के दौरान इनकी पहचान छिपाने, इनके फर्जी आधार कार्ड बनवाने और अन्य विषय भी सामने आए थे। इनका संज्ञान बाल संरक्षण आयोग ने लिया और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी थी। धामी सरकार ने अब मदरसों में काबिलयाई शिक्षा को रोकने और उसकी जगह उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पढ़ाने का निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को देश में पहली बार उत्तराखंड में लागू किया गया है जिसमें अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी शामिल करते हुए सरकारी सहायता दिए जाने के रास्ते खोल दिया है, जो अभी तक सिर्फ एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समाज को ही मिलती थी।

**अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की मान्यता लेकर बच्चों को पढ़ाई करानी होगी, यदि वो धार्मिक शिक्षा भी देते हैं तो उसके लिए स्लीक्स, प्राधिकरण की शिक्षा समिति तय करेगी, रहा सवाल नॉर्मस का तो वो भी सबके लिए बराबर है जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।**



## कठिन है मदरसों का पंजीकरण

उत्तराखंड में अभी तक जो भी मदरसे संचालित हो रहे हैं, उन्हें अब शिक्षा बोर्ड से मान्यता के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। क्योंकि उत्तराखंड में जो मदरसे चल रहे थे उनके पास नियमानुसार पर्याप्त भूमि नहीं है, जो है भी उसके दस्तावेज नहीं के बराबर हैं। ऐसे मदरसे जो पंजीकृत नहीं हैं जिनके पास बीएड टीचर नहीं है, भवन में नॉर्मस के अनुसार कमरे नहीं हैं, जिनके पास खेल का मैदान नहीं है। उनका पंजीकरण संभव नहीं होगा। इसके साथ ही जो मदरसे पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें नियमानुसार बैंक खातों का विवरण देना होगा, चंदा उगाही और आर्थिक स्रोत का ऑडिट कराना होगा। क्योंकि बहुत से मदरसों के संचालक स्थानीय स्तर पर चंदा उगाही करते हैं। खाड़ी देशों से इस्लामिक शिक्षा के नाम पर फंड हासिल करते हैं। ऐसी भी जानकारी मिलती रही है कि कुछ मदरसा संचालक शिक्षा के नाम पर वसूले गए धन का उपयोग बच्चों की दीनी तालीम पर कम और अपनी ऐशों आराम पर ज्यादा करते रहे हैं।

## सरकार की मंशा

उत्तराखंड अल्पसंख्यक विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते का कहना है कि शिक्षा का अधिकार सबके के लिए समान है। हमारा प्रयास है कि हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिले इसके लिए सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की मान्यता लेकर बच्चों को पढ़ाई करानी होगी। यदि वो धार्मिक शिक्षा भी देते हैं तो उसके लिए स्लीक्स, प्राधिकरण की शिक्षा समिति तय करेगी। रहा सवाल नॉर्मस का तो वो भी सबके लिए बराबर है जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए, उनकी प्रयोग शालाओं के लिए, पुस्तकालयों के लिए सरकार सहयोग देने को तैयार है। डॉ. धकाते का कहना है कि 1-5 कक्षा तक के स्कूलों को प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है। कक्षा 6-8 तक के उच्च प्राथमिक स्कूल की श्रेणी में आएंगे। जबकि कक्षा 1-8 तक के स्कूलों को एक साथ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है। जिला विद्यालय समिति से मान्यता हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्र में कम से कम 2000 वर्ग मीटर यानी 0.5 एकड़. खेल का मैदान होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ या 4000 वर्ग मीटर। पहाड़ी इलाके में 500 वर्ग मीटर तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जमीन की मदरसे या स्कूल के नाम पर रजिस्ट्री होनी चाहिए। इसके साथ 30 साल की लीज भी मान्य होगी। पंजीकरण के लिए बिल्डिंग का नियम भी निर्धारित किया गया है। यानी कक्षा से एक से पांच तक के लिए कम से कम 5 कमरे कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8 कमरे होना अनिवार्य है। हर कमरा कम से कम 20x20 फीट यानी 400 वर्ग फीट का होना चाहिए। इसके साथ ही स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, टॉयलेट, हैंडपंप या पानी की टंकी, किचन शेड, फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। बिल्डिंग तीन मंजिल से ज्यादा नहीं होगी। कक्षा एक से पांच तक के लिए शिक्षक और छात्रों का 1-30 अनुपात होना चाहिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक छात्रों का अनुपात 1-35 निर्धारित है। शिक्षकों की योग्यता का मानक भी निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड के साथ टीईटी पास होना अनिवार्य है। 6-8 के लिए बीएड के साथ टीईटी पास की योग्यता निर्धारित है। जबकि हेडमास्टर कक्षा 1 से 5 के लिए 5 साल अनुभव और कक्षा 6 से 8 के लिए 8 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। मदरसे या शिक्षण संस्थान का रजिस्ट्रेशन 3 साल पुरान और रिन्यू होना चाहिए। भूमि की रजिस्ट्री, नक्शा, भू-उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिल्डिंग प्लान इंजीनियर द्वारा पास होना चाहिए। टीचर व अन्य स्टाफ का वेतन रजिस्टर भी प्रस्तुत करना होगा। वेतन सरकार द्वारा तय सीमा से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब छात्रों को फ्री में शिक्षा देना आवश्यक होगा। 25 प्रतिशत सीटें आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होना जरूरी है। एक शिक्षण संस्थान में कक्षा 1 से 5 तक कम से कम 50 बच्चे होने चाहिए। जबकि कक्षा 6 से 8 तक कम से कम 30 बच्चे होना आवश्यक है। सीबीएसई या आईसीएसई पाठ्यक्रम नहीं चला सकते। सिर्फ

- बहुत से मदरसों के संचालक स्थानीय स्तर पर चंदा उगाही करते हैं, खाड़ी देशों से इस्लामिक शिक्षा के नाम पर फंड हासिल करते हैं, ऐसी भी जानकारी मिलती रही है कि कुछ मदरसा संचालक शिक्षा के नाम पर वसूले गए धन का उपयोग बच्चों की दीनी तालीम पर कम और अपनी ऐशों आराम पर ज्यादा करते रहे हैं।
- उत्तराखंड में जो मदरसे चल रहे हैं उनके पास नियमानुसार पर्याप्त भूमि नहीं है, जो है भी उसके दस्तावेज नहीं के बराबर हैं, ऐसे मदरसे जो पंजीकृत नहीं हैं जिनके पास बीएड टीचर नहीं है, भवन में नॉर्मस के अनुसार कमरे नहीं हैं, जिनके पास खेल का मैदान नहीं है, उनका पंजीकरण संभव नहीं होगा।

एनसीईआरटी और एससीआईआरटी का पाठ्यक्रम ही स्कूल में मान्य होगा।

## नॉर्मस पूरे नहीं तो मान्यता रद्द

नई शिक्षा नीति के तहत बिना टीचर या 30 बच्चों पर 1 टीचर नहीं है तो शिक्षण संस्थान की मान्यता रद्द हो जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक यदि छात्रों की संख्या 50 से कम होती है तो भी मान्यता रद्द हो जाएगी ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं ली तो भी मान्यता नहीं मिलेगी। आरटीई के तहत 25 प्रतिशत बच्चों से फीस नहीं ले सकते, यदि फीस वसूली जाती है तो भी मान्यता रद्द हो सकती है। पंजीकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फॉर्म जमा कराना होगा। फॉर्म जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस से या शिक्षा विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। प्राथमिकविद्यालय के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 10,000 रुपये व 2 लाख सिक्वोरिटी जमा करनी होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 15,000 रुपये पंजीकरण शुल्क और 3 लाख रुपये की सिक्वोरिटी जमा करनी होगी। हर तीन साल में रिन्यू कराने के लिए 55,000 जमा कराने होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी की टीम स्कूल का स्थलीय सत्यापन करने के लिए विजिट करेगी। जमीन, बिल्डिंग, स्टाफ का सत्यापन होगा। यह टीम 1 महीने में रिपोर्ट देगी। जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय समिति की बैठक होगी। इसमें विधायक और जिलाधिकारी का नॉमिनी व अधिभावक प्रतिनिधि होते हैं। अगर सब ठीक है तो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। समिति से पास होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जो 3 साल के लिए वैध होगा। एनओसी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जिसे 3 साल में फिर रिन्यू कराना होगा।

## यूडीआईएसई कोड लेना होगा

अब कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को समग्र शिक्षा के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के संचालित होने वाले स्कूल मदरसे या अन्य शिक्षण संस्थान अवैध होंगे। पंजीकरण होने व मान्यता मिलने के बाद यूडीआईएसई कोड लेना होगा। बिना कोड के बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अब उत्तराखंड स्कूल मान्यता पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है जिसका 30 दिन में निपटारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में अवैध मदरसे बंद करा दिए गए हैं, मदरसा बोर्ड भी खत्म कर दिया गया है, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से शिक्षा लेंगे इसके लिए उन्हें अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता, संबद्धता लेनी होगी। जो नहीं लेगा उस संस्थान पर ताले लगा दिए जाएंगे। ●

# अंग्रेजों की निशानी खतरे में

1947 में देश आजाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब के कांग्रेसियों ने जिमखाना क्लब का उपयोग अपनी ऐश के लिए शुरु कर दिया, क्लब के नाम से सिर्फ इंपीरियल हटा, बाकी जमीन वही रही, किराया वही 1000 रुपये सालाना रहा, बस अंदर बैठने वाले बदल गए. विदेशी साहब की जगह देसी साहब ने ले ली।



अनिल मामगार्डे वरिष्ठ पत्रकार

# भा

रत सरकार अंग्रेजों की एक और निशानी 113 साल पुराने दिल्ली जिमखाना क्लब और कैम्पस को मिटाने का इशारा बना चुकी है। इसके लिए बाकायदा जिमखाना क्लब को नोटिस भेज कर 27.3 एकड़ जमीन खाली करने को कहा गया है। सरकार ने नोटिस में इस कैम्पस को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही तर्क दिया है कि पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए भी जमीन खाली कराना आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार के हर फैसले को लटकाने के उद्देश्य से कोर्ट में घसीट लेती है। लिहाजा लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब की जमीन खाली करने का मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा गया है। नोटिस मिलने के अगले ही दिन क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। क्लब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस की तत्काल सुनवाई की मांग की। क्योंकि जमीन खाली करने की डेडलाइन 5 जून थी। लिहाजा 26 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब की सुनवाई की। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि 5 जून के बाद क्लब परिसर पर कोई जबरन कब्जा नहीं किया जाएगा। बल्कि 5 जून की तारीख सिर्फ स्वेच्छ से परिसर खाली करने की समयसीमा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुलिस क्लब पर कब्जा कर लेगी या जबरन खाली कराया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन के बाद क्लब सदस्यों को थोड़ी राहत अवश्य मिली है। इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी अंतरिम आदेश की जरूरत से इनकार कर दिया। फिलहाल तत्काल बेदखली का खतरा टल गया है। खतरा टला है समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की नजर जब भी किसी अंग्रेजी हुकूमत की पहचान पर पड़ी है उसे हटाकर ही दम लिया है। वैसे भी दिल्ली जिमखाना क्लब की यह जमीन दिल्ली के बीचोंबीच है और प्रधानमंत्री आवास की दीवार से सटी हुई है, जहां एक एकड़ जमीन की कीमत हजारों करोड़ रुपये है। हैशनी की बात ये है कि अरबों खरबों की 27.3 एकड़ जमीन का किराया सिर्फ 1000 रुपये सालाना है। यानी 83-84 रुपये महीना। 84 रुपये महीने के किराये पर तो दिल्ली में रेहड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। 1000 रुपये महीने किराये पर तो दिल्ली में झुग्गी भी नहीं मिलती। जबकि जिमखाना क्लब का वार्षिक किराया एक हजार रुपये है। इस जिमखाना क्लब की सदस्यता आसानी से नहीं मिलती। सिर्फ राहुल गांधी जैसे नेता इस क्लब के सदस्य



बन सकते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स जज और कारपोरेट्स इसके सदस्य बन सकते हैं। यानी 113 वर्षों से 1000 रुपये वार्षिक किराये पर विशिष्ट वर्ग ने 27.3 एकड़ जमीन पर बने जिमखाना क्लब को अपनी जागीर बनाकर रखा है।

राहुल गांधी इस क्लब के सदस्य है जिनका खानदान यानी दादी, पिता खुद राहुल गांधी गरीबी मिटाने की बात करते आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी बताएंगे कि जिमखाना क्लब के सदस्यों में कितने ओबीसी हैं? कितने दलित हैं कितने आदिवासी है और कितने गरीब हैं। राहुल गांधी से ये सवाल इसलिए क्योंकि वो मोदी सरकार से पूछते रहते हैं कि क्रिकेट टीम में कितने ओबीसी, एससी एसटी हैं। पीएम के स्टाफ में कितने ब्यूरोक्रेट्स एससी एसटी और ओबीसी हैं। विपक्षी नेता मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाते हैं, लेकिन जिमखाना क्लब के 1000 रुपये सालाना किराये का मुद्दा नहीं उठाते। कुल मिलाकर क्लब के मुख्य सदस्यों में राहुल गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, भाजपा नेता मेनका गांधी, लेखक खुशवंत सिंह जैसे लोग शामिल थे, यानी जो देश चलाते थे वही यहाँ बैठते थे और जिनके लिए देश चलाया जाता था वो बाहर खड़े रहते थे, यानी आम आदमी।

## अंग्रेजों के जमाने में बना क्लब

बात ब्रिटिश काल की है। ब्रिटिश शासकों ने अपनी ऐश का हर सिस्टम बनाया। इसलिए 1928 में यह 27.3 एकड़ जमीन 1,000 रुपये सालाना किराये पर दे दी गई थी। 1911 में किंग जॉर्ज ने ऐलान किया था कि ब्रिटिश-भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जाएगी। हजारों अंग्रेज अफसर दिल्ली आए। उन्हें एक जगह चाहिए थी, जहां शाम को वो बैठ सकें, पोलो खेल सकें और हिंदुस्तान चलाने के फैसले ले सकें और भी बहुत कुछ कर सकें। तीन जुलाई 1913 को इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब का जन्म हुआ। हालांकि इस जमीन पर इमारत का निर्माण 1930 के दशक में हुआ। इस बिल्डिंग को उसी आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने डिजाइन किया था जिन्होंने कर्नाट प्लेस बनाया था। 1947 में देश आजाद हुआ और अंग्रेज यहाँ से चले गए। तब के कांग्रेसियों ने क्लब का उपयोग अपनी ऐश के लिए शुरू कर दिया। क्लब के नाम से सिर्फ इंपीरियल हटा, बाकी जमीन वही रही, किराया वही 1000 रुपये सालाना रहा,

**क्लब के मुख्य सदस्यों में राहुल गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, भाजपा नेता मेनका गांधी, लेखक खुशवंत सिंह जैसे लोग शामिल थे, यानी जो देश चलाते थे वही यहाँ बैठते थे और जिनके लिए देश चलाया जाता था वो बाहर खड़े रहते थे, यानी आम आदमी।**

बस अंदर बैठने वाले बदल गए. विदेशी साहब की जगह देसी नेताओं व रसूखदारों ने ले ली। आजादी के बाद दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन खेल के नाम मांगी गई थी, लेकिन जिमखाना क्लब कभी खेल का मैदान नहीं रहा। 2014-15 से 2018-19 के बीच क्लब के बजट का खेल पर कुल खर्च सिर्फ 2.77 प्रतिशत था। बाकी पैसा केटरिंग, वाइन, शराब, चखना और सिगरेट पर खर्च किया गया। यानी खेल के नाम पर खेला किया गया। 113 साल बाद अब क्लब की जमीन पर एक नोटिस के जरिये विवाद शुरू हुआ तो, दो ताकतवर पक्ष आमने-सामने आ गए। यह जमीन, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली के अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में यह जिमखाना क्लब परिसर रक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के काम आ सकता है। सुरक्षा मकसदों की वजह से इसे हासिल करना सरकार के लिए जरूरी है।

## मैंबरशिप के लिए 37 सालों का इंतजार

दिल्ली जिमखाना क्लब की सदस्यता लेने के लिए 37 साल तक इंतजार किया गया, लेकिन सदस्यता नहीं मिली। मैंबरशिप के लिए लोग 37 सालों तक वेटिंग लिस्ट में रहे और जो क्लब के पहले से मेंबर थे उनके परिवारवालों को मैंबरशिप दे दी जाती थी। मैंबरशिप के लिए लोगों से 44 करोड़ रुपये से ज्यादा फीस वसूली गई, जो नॉन रिफंडेबल थी। यानी न तो पैसा वापस किया गया और न ही वेटिंग लिस्ट वालों को मैंबरशिप दी गई। मैंबरशिप फीस कॉरपोरेट के लिए 15 से 20 लाख रुपये थी। क्लब में 40-40-20 का नियम था। यानी 40 प्रतिशत सीटें आईएस-आईपीएस अधिकारियों के लिए, 40 प्रतिशत सेना के अफसरों के लिए और 20 प्रतिशत प्रतिष्ठित लोगों (नेताओं) के लिए। आम आदमी के लिए शून्य। क्लब के सदस्यों के बच्चों को ग्रीन कार्ड मिलता था, जिससे वे वेटिंग लिस्ट में रहते हुए भी क्लब का इस्तेमाल कर सकते थे। एक तरह से 37 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहने वाले लाइन में खड़े रहे और अंदर वालों के बच्चे मजे लूटते रहे। 2014 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अक्टूबर 2020 में पहली बार क्लब का बार लाइसेंस रद्द किया गया, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन के दौरान बिना इजाजत के शराब बेची जा रही थी। फिर क्लब के बार में शराब की 50 बोटलें गायब होने का मामला सामने आया, जिसकी नवंबर, 2021 में पुलिस ने जांच की। एक दौर में क्लब के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले अदालत में लंबित थे लेकिन मजदूर बात यह है कि दिल्ली के इतने जज इस क्लब के मेंबर थे कि उन्हें खुद ही केस से अलग होना पड़ता।

## अमीरों के शगल को बचाने के लिए पसीना बहाया

27.3 एकड़ में फैले दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने की तैयारी पूरी है। पीएम

- 113 साल बाद अब क्लब की जमीन पर एक नोटिस के जरिये विवाद शुरू हुआ तो, दो ताकतवर पक्ष आमने-सामने आ गए। जिसकी जमीन है वो आम आदमी अभी भी बाहर खड़ा है। इंतजार में कि कोई उसे बताए कि इस जमीन पर उसे क्या मिलेगा ?
- लोकतंत्र में वैभव पर प्रतिबंध नहीं होता, परंतु वैभव के साथ सामाजिक संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व भी अपेक्षित होता है। यही संतुलन तय करेगा कि भविष्य का भारत विशिष्ट क्लबों को सम्मान की नजर से देखेगा या औपनिवेशिक अवशेष मानकर प्रश्न उठाता रहेगा।

हाउस और हाई लेवल डिफेंस जोन में 1913 से चल रहे जिमखाना क्लब की ओर झांकने की हिम्मत आम आदमी में आजादी के 75 बरस बाद भी नहीं हुई। लुटियन जोन्स का विशिष्ट व अभिजात वर्ग को जैसे ही पता चला कि दिल्ली जिमखाना क्लब खाली कराने की तैयारी है वह फड़फड़ाए लगा। चूँकि राहुल गांधी से लेकर राजनीति और पूंजी के तमाम धुरंधर इस क्लब के सदस्य हैं अतः उच्च स्तर पर भागदौड़ हुई। मई की भीषण गर्मी और हीट वेव में अभिषेक मनु सिंघवी जैसे महंगे वकील ने अमीरों के इस शगल का अधिग्रहण रोकने के लिए पसीना बहाया और दिल्ली हाई कोर्ट से अभिजात वर्ग को तत्काल कुछ राहत भी दिला दी। इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या ऐसे क्लब औपनिवेशिक मानसिकता की निशानी हैं? अंग्रेजों के दौर में बने इन क्लबों का उद्देश्य अभिजात्य वर्ग को आम जनता से अलग रखना था। आज भी इनकी सदस्यता इतनी महंगी और सीमित है कि देश की 99.99 प्रतिशत आबादी वहाँ कदम तक नहीं रख सकती। जब किसी क्लब की सदस्यता या संपत्ति का मूल्य सैकड़ों करोड़ में पहुंच जाए, तब आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह लोकतांत्रिक भारत की भावना के अनुरूप है। क्योंकि भारत जैसा विशाल देश के लोग मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या अरबों रुपये की संपत्ति और अत्यधिक विशिष्ट वर्ग के सदस्यों वाले पॉश क्लबों की वास्तव में आवश्यकता है? आलोचक कह रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में जमीन की भारी कमी है। ऐसे में हजारों करोड़ मूल्य की सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कुछ हजार लोगों के मनोरंजन के लिए फैले आलीशान क्लब सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से उचित नहीं लगते। कई बार इन क्लबों में वीआईपी संस्कृति, राजनीतिक रसूख और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली लॉबींग के आरोप भी लगते रहे हैं। इससे आम नागरिक के भीतर यह भावना पैदा होती है कि देश में अब भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कायम है। दूसरी ओर समर्थकों का तर्क है कि दुनिया के लगभग हर बड़े देश में ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक क्लब होते हैं। ये केवल मौज-मस्ती के केंद्र नहीं बल्कि नेटवर्किंग, खेल, कला, साहित्य और सामाजिक संवाद के मंच भी होते हैं। कई क्लबों ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखा है। यदि कोई संस्था अपने संसाधनों से चल रही है और कानून का पालन कर रही है, तो केवल उसके महंगे होने के आधार पर उसे अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। लेकिन असल सवाल क्लबों के अस्तित्व का नहीं बल्कि उनकी जवाबदेही और सामाजिक उपयोगिता का है। यदि ऐसे संस्थान केवल सत्ता, धन और पहुंच वाले लोगों की बंद दुनिया बन जाएं, तो लोकतांत्रिक समाज में उनकी आलोचना स्वाभाविक है। लेकिन यदि वे खेल, संस्कृति, सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामाजिक सेवा में व्यापक योगदान दें, तो उनकी उपयोगिता सिद्ध की जानी चाहिए। मौजमस्ती और शराबखोरी के अड्डे बनाने के लिए ऐसे क्लबों की जरूरत नहीं है। भारत को शायद ऐसे क्लबों से अधिक उस सोच को बदलने की जरूरत है जिसमें विशेषाधिकार और आम जनता के बीच बहुत गहरी खाई दिखाई देती है। लोकतंत्र में वैभव पर प्रतिबंध नहीं होता, परंतु वैभव के साथ सामाजिक संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व भी अपेक्षित होता है। यही संतुलन तय करेगा कि भविष्य का भारत विशिष्ट क्लबों को सम्मान की नजर से देखेगा या औपनिवेशिक अवशेष मानकर प्रश्न उठाता रहेगा। ●

# राहुल का मुस्लिम कार्ड



राहुल गांधी किसी वेणुगोपाल को केरलम का सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन इंडियन यूनिवर्स मुस्लिम लीग वीडो सतीशन को सीएम बनाना चाहती थी, सतीशन, प्रियंका के भी प्रिय हैं, लिहाजा राहुल गांधी को एआईयूएमएल के सामने सरेंडर करना पड़ा और इंडियन यूनिवर्स मुस्लिम लीग की पसंद के वीडो सतीशन को सीएम बनाना पड़ा।

## लौ

कृष्ण कुमार चौहान

कसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या भाजपा के पोस्टर ब्याय हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं भाजपा को हरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मीडिया हो या भाजपा नेता सभी राहुल की छोटी हरकतों पर रिप्लेट करते हैं। ताकि वो मीडिया की सुर्खियों में रहे। कांग्रेस नेता ये तक नहीं जानते ही उनकी (राहुल) विचारधारा क्या है? उनकी पार्टी का मकसद क्या है? पार्टी को परिवार के लिए काम करना चाहिए या राष्ट्र के लिए? चुनाव के संवेदनशील समय क्या बोलना चाहिए और क्या कहने से बचना चाहिए? क्योंकि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। राहुल गांधी एक सत्ताधारी परिवार में पैदा हुए हैं। इसलिए उनके मन मस्तिष्क में एक बात है कि उनके दादा देश के प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही और पिता भी देश की सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन जब उनका नंबर आया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से नफरत है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को नकारात्मक राजनीति और विदेशी ताकतों का पोस्टर ब्याय बताया। यानी जब तक राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे भाजपा को सत्ता से हिला नहीं पाएंगे। भाजपा नेता मानते हैं कि भाजपा की लगातार जीत में राहुल गांधी का बड़ा योगदान है, इसलिए शायद केंद्र सरकार भी उन पर मेहरबान है। क्योंकि

जितने केस गांधी परिवार पर हैं उससे तो मां-बेटे को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ इनके खिलाफ विवेचना ही करती रहती है। क्योंकि भाजपा को पता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी को जेल भेजने से भाजपा को नुकसान हो सकता है। गांधी परिवार कांग्रेस को सीआईए, चीन और जॉर्ज सोरोस से फंडिंग होती है। ऐसा आरोप भाजपा लगाती रही है। भाजपा का दावा करती है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 'एशिया-पैसिफिक में डेमोक्रेटिक लीडर्स फोरम' (एफउडीएल-एपी) से जुड़ी थीं, जिसे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन फंड करती है। इस तरह के सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, कार्रवाई कोई नहीं की जाती है।

### राहुल कम्प्रोमाइज्ड लीडर

राहुल गांधी वक्त बे वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम्प्रोमाइज्ड पीएम बताते रहते हैं, नरेंद्र सरेंडर का नारा लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो खुद सरेंडर भी करते हैं और घोषित रूप से कम्प्रोमाइज्ड लीडर भी हैं। हाल ही में केरलम सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। राहुल गांधी अपने वफादार सांसद केसी वेणुगोपाल को केरलम का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कांग्रेस के कुछ विधायक भी उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन इंडियन यूनिवर्स मुस्लिम लीग (एआईयूएमएल) ने केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाने का विरोध किया और छठीं बार विधायक बने वीडो सतीशन का समर्थन किया। प्रियंका गांधी भी वीडो सतीशन का समर्थन कर रही थीं क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से सतीशन जीते हैं वो प्रियंका गांधी वाड़ा की लोकसभा क्षेत्र वायनाड की विधानसभा है। लिहाजा राहुल गांधी को एआईयूएमएल के सामने सरेंडर करना पड़ा और इंडियन यूनिवर्स मुस्लिम लीग की पसंद के वीडो सतीशन को केरलम का सीएम बनाना पड़ा। केरलम की इंडियन यूनिवर्स मुस्लिम लीग की जड़े आज भी भारत के टुकड़े करने वाले जिन्ना की मुस्लिम लीग से जुड़ी हैं और विचारधारा भी जिन्ना वाली ही है। जिसे राहुल गांधी सेक्युलर पार्टी का सर्टिफिकेट देते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह मुस्लिम लीग के सामने सरेंडर किया वो कम्प्रोमाइज्ड वाली राजनीति का ताजा उदाहरण है।

राहुल गांधी एक सत्ताधारी परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए उनके मन मस्तिष्क में एक बात तो है कि उनके दादा देश के प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही और पिता भी देश की सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन जब उनका नंबर आया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी से नफरत है।

### कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए उसे 'मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस' (एमएमसी) कहते रहे हैं। पीएम मोदी कहते रहे हैं कि कांग्रेस अब 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' नहीं रही, बल्कि कट्टरपंथी और तुष्टिकरण की राजनीति की ओर बढ़ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर अब राहुल गांधी ने खुद ही मोहर लगा दी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं से साफ कहा है कि उन्हें अपने समुदाय से जुड़े मुद्दों को खुलकर उठाना चाहिए और कांग्रेस में मुस्लिम समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में राहुल गांधी ने यह संदेश दिया। राहुल का कहना था कि अगर किसी मुस्लिम के साथ अन्याय होता है तो उसकी आवाज केवल 'माइनॉरिटी' कहकर नहीं बल्कि 'मुस्लिम' पहचान के साथ उठाई जानी चाहिए। राहुल का कहना था कि कांग्रेस को मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करने से बचना नहीं चाहिए। अगर दलित, ओबीसी या सामान्य वर्ग के लोगों पर हमला होता है तो उनकी पहचान के साथ मुद्दा उठाया जाए। यानी राहुल गांधी बहुसंख्यकों में दलित, ओबीसी और सामान्य में बंटवार कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को फिरको में बांटने से बच रहे हैं। लगातार हार से निराश राहुल गांधी अब खुल कर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। इससे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में भी चिंता है। क्योंकि भाजपा को छोड़कर बाकी सभी दलों को मुस्लिम वोट बैंक का ही सहारा है। अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो बाकी दल क्या करेंगे?

### मुस्लिम कार्ड से कांग्रेस को फायदा

हालांकि 2014 के बाद राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, सांस्कृतिक पहचान के नाम पर राजनीति करने वालों का भ्रम टूट रहा है। इसके लिए किसी एक राजनीतिक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सभी दल राजनीति वोटों की दलदल में फंसे हैं। आम तौर पर भाजपा विपक्षी दलों पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती है। जबकि विपक्षी दल भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति का आरोप मंडते हैं। खैर राजनीति है इसमें आरोप-प्रत्यारोप न हो तो फिर राजनीति ही क्या? भाजपा विरोधी कुछ राजनीतिक दल खुद को घोषित अथवा अघोषित रूप से मुसलमानों की पार्टी बता चुके हैं। कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि अब वो मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर मंथन भी हुआ। क्योंकि असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुल 19 विधायक चुने गए। इनमें से 18 मुस्लिम विधायक हैं। यानी 99 प्रतिशत मुस्लिम प्रत्याशी जीते। जबकि असम के सीएम का फेस बनाए गए, गौरव गोगोई तक अपने गढ़ में चुनाव हार गए। इसी तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दो विधायक चुने गए दोनों ही मुस्लिम हैं। यानी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम प्रत्याशियों का स्ट्राइक रेट 100 प्रतिशत रहा। जबकि बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी अपने गढ़ में चुनाव हार गए। बहरामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के सुब्रत मैत्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी को 7485 वोटों से हराया। केरलम में भी कांग्रेस के 8 विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शायद इसलिए हिंदुत्व को समाप्त करने की ताल ठोकते हैं। कांग्रेसी सनातन का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यानी कांग्रेस अब खुल कर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है।

### कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे

ममता बनर्जी की टीएमसी बूथ कैप्चरिंग, घुसपैठियों और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे 15 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही। ममता बनर्जी ने मान लिया था कि उनकी सत्ता को कोई हिला तक नहीं सकता, लेकिन जब तानाशाही बढ़ जाती है तब बदलाव का उबाल आता है। जो पश्चिम बंगाल में आया और ममता सत्ता से बेदखल हो गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी की समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी दोनों मुस्लिम वोट बैंक के सहारे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बसपा और सपा की बीच लटकती हुई है। कांग्रेस दोनों ही दलों से गठबंधन

- असम में कांग्रेस के 19 विधायक चुने गए, इनमें से 18 मुस्लिम हैं, यानी 99 प्रतिशत मुस्लिम प्रत्याशी जीते, जबकि असम के सीएम का फेस, गौरव गोगोई अपने गढ़ में चुनाव हार गए, इसी तरह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दो विधायक चुने गए दोनों ही मुस्लिम हैं, यानी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम प्रत्याशियों का स्ट्राइक रेट 100 प्रतिशत रहा।
- भाजपा नेता मानते हैं कि उसकी जीत में राहुल का बड़ा योगदान है, इसलिए शायद केंद्र सरकार उन पर मेहरबान है, क्योंकि जितने केस गांधी परिवार पर हैं उससे तो मां-बेटे को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ इनके जांच कराती रहती है, भाजपा को पता है कि राहुल या सोनिया को जेल भेजने से भाजपा को नुकसान होगा।

कर उनके कोर वोट के सहारे विधानसभा में अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। राहुल गांधी को लगता है कि जिस तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार होकर सफलता मिली है उसका विधानसभा में भी एक्सपेरिमेंट किया जाए।

### मुसलमान भाजपा नहीं हरा सकता?

बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में लोकसभा की 249 सीटें हैं। लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10 फीसदी से ज्यादा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को बिना किसी सहारे के इन पांच राज्यों में सफलता मिलना कठिन है। शायद इसलिए भी राहुल गांधी ने अब मुस्लिम वोट बैंक की तरफ फोकस किया है। लेकिन अब जाति संप्रदायों में बांटने वाली राजनीति का अंत हो रहा है। मुस्लिम समाज अब किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहा है। जो समुदाय किसी को सत्ता तक नहीं पहुंचा सकता वो किसी दूसरे दल को सत्ता से बेदखल कैसे कर सकता है? खुद मौलाना हाफिज गुलाम सरवर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस, सपा और बसपा को ललकार रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि देश भर में मदरसों, मजारों और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, सपा, कांग्रेस, बसपा, आरजेडी, टीएमसी कहाँ है? सवाल तो बनता है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ धरना हुआ, राहुल, अखिलेश, ममता बनर्जी, तेजस्वी, मायावती क्या धरने में आए? नहीं क्योंकि ये सब मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। गुलाम सरवर दावा करते हैं कि ये सभी पार्टियाँ मुर्दा हो चुकी है। ये विपक्ष में रहने लायक भी नहीं रही हैं। ऐसी पार्टियों को अब मुसलमान सहारा नहीं देगा। सोशल मीडिया पर गुलाम सरवर दावा कर रहे हैं कि जो मुसलमान 2014 के बाद भाजपा को जिता नहीं पाया वो हरा कैसे सकता है? गुलाम सरवर समझा रहे हैं कि मुसलमानों को अब भाजपा को जिताना पड़ेगा। क्योंकि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सपा, बसपा, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और मुसलमान मिलकर भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं, ये साबित हो चुका है। मौलाना साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी जैसे दलों ने मुसलमानों को डराने का काम किया है। लेकिन जिस भाजपा को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया। सभी को पात्रता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, आवास दिया, रसाई गैस कनेक्शन दिया, इज्जत घर दिया, राशन दिया, आयुष्मान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि दी, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक और हलाला जैसी जिल्लत की जिंदगी से मुक्त कराया। हर घर में नल से जल दिया, मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, मुस्लिम महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, फिर भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता। बल्कि भाजपा को हारने वाली पार्टी को वोट देता है। ये परंपरा आज नहीं तो कल जरूर बदलेगी। हाफिज गुलाम सरवर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, इसलिए वो जहां चाहेगा वहां मतदान करेगा। ●

# एनकाउंटर पर विपक्षी मातम

पिछले नौ वर्षों में यूपी में जो कानून का राज कायम हुआ उससे हर धर्म, जाति और वर्ग ने सुरक्षा का अहसास किया है, भले ही सपा नेता मुस्लिमों को प्रताड़ित साबित करने की कोशिश करें, लेकिन यूपी का मुसलमान भी योगी की कानून व्यवस्था से संतुष्ट है, पर राजनीति करने वाले असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट ही रहेंगे।

# 3



अतुल सिन्हा  
टीवी जर्नलिस्ट

उत्तर प्रदेश में अगले बस विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुठभेड़ को लेकर सियासी हल्ला तब और ज्यादा हुआ जब बकरा ईद के दिन गाजियाबाद के खेड़ा में सूर्या प्रताप चौहान (17) को उसके दोस्त असद ने बुलाया और फिर उससे पूछा कि क्या बकरा हलाल होते देखा है। यानी बकरा कटते देखा है, सूर्या के ना करने पर असद और उसके दोस्तों ने मिलकर सूर्या के पेट में चाकू घोंपा और फिर उसे तब तक घुमाते रहे जब तक सूर्या की मौत नहीं हो गई। 28 मई को सूर्या की हत्या हुई और 31 मई को दिन निकलने पर खबर आई की सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम था। एनकाउंटर में असद की मौत पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले छत्ती पीटने लगे। डंका पीटने लगे कि पुलिस जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर कर रही है। एक खास वर्ग को टारगेट कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। खास वर्ग का मतलब साफ है मुस्लिम, लेकिन मुसलमान नाम लेने से नेता बचते हैं। इससे पहले 26 मई को जौनपुर में दूल्हे आजाद बिंद के हत्यारोपी रवि यादव के एनकाउंटर पर भी सियासत हुई थी। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि 'जिस एनकाउंटर के पीछे चले मर्जी वो है फर्जी।' अखिलेश यादव ने कहा था कि फेक एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जा रहे हैं। सरकार पीडीए (पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों) वालों का फर्जी एनकाउंटर करा रही है। हैरानी की बात ये है कि अखिलेश यादव एनकाउंटर पर मातम मनाते हैं, कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर से परिवार का सोशल एनकाउंटर होता है। फर्जी एनकाउंटर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस समाज में मेलजोल की संस्कृति होती थी, आज वहां नफरत फैलाने के लिए मुठभेड़ की संस्कृति पैदा की जा रही है। यूपी में इस तरह जंगल राज कायम हो रहा है, लेकिन जनता को यह जंगल राज बहुत पसंद आ रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव गाजियाबाद के सूर्या चौहान की कूरता से की गई हत्या पर एक शब्द तक नहीं बोलते हैं और न ही जौनपुर के दूल्हे आजाद बिंद की हत्या पर मुंह खोलते हैं। उन्हें सिर्फ एनकाउंटर में मारे जाने वाले इनामी अपराधियों की मौत पर मातम मनाना आता है। फिर जब चुनाव में जनता सपा का विरोध

करती है तो कहा जाता है कि भाजपा ने वोट चोरी किए हैं। इस स्टोरी के जरिये अपराधियों के मुठभेड़ में मारे जाने पर मातम मनाने वाले अखिलेश यादव सहित मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं के नैरेटिव का पोस्टमार्टम करते हैं।

## सुकून है उत्तर प्रदेश में

मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और यूपी में माफिया राज था। अखिलेश के राज में एक खास वर्ग के युवाओं ने हिंदू लड़कियों का स्कूल जाना मुश्किल कर रखा था। महिलाओं का राह चलते छेड़ा जाता था। कोई ऐसा अपराध नहीं था जो यूपी में नहीं होता था, कानून व्यवस्था पुलिस के बजाये अखिलेश के समर्थकों के हाथ में थी। थानों में सपा नेता बैठ कर फैसला करते थे कि किसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी किसकी नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में सख्त कदम उठाया। योगी ने पुलिस को सारे बंधनों से आजाद किया और परिणाम मांगे, अखिलेश यादव की सरकार में जो पुलिस माफिया से कांपती थी वही पुलिस योगी आदित्यनाथ की सरकार में माफिया को सड़क पर घसीटते हुए नजर आई। पहले जो पुलिस माफिया को देखकर आगे-आगे भागती थी उसी पुलिस को देखकर माफिया भागने लगे। पिछले नौ वर्षों में जो कानून का राज कायम हुआ उससे हर धर्म, जाति और वर्ग ने सुरक्षा का अहसास किया है। भले ही सपा नेता मुस्लिमों को प्रताड़ित साबित करने की कोशिश करें, लेकिन यूपी का मुसलमान भी योगी की कानून व्यवस्था से संतुष्ट है, लेकिन राजनीति करने वाले असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट ही रहेंगे। क्योंकि

**अखिलेश यादव एनकाउंटर पर मातम मनाते हैं, यूपी में जंगल राज बताते हैं, लेकिन जनता को यह जंगल राज पसंद आ रहा है, अखिलेश यादव सूर्या चौहान की हत्या पर एक शब्द नहीं बोलते और न ही जौनपुर के दूल्हे आजाद बिंद की हत्या पर मुंह खोलते हैं, फिर जब चुनाव में जनता सपा का विरोध करती है तो कहा जाता है कि भाजपा ने वोट चोरी किए हैं।**



अखिलेश यादव के शासनकाल में दिन ढलते ही लुटेरे सड़कों पर आ जाते थे और मेहनत मजदूरी कर लौट रहे गरीब तबके तक को लूट लेते थे। किसानों को अपने नलकूप की खवानी करनी पड़ती थी कि कहीं चोर बिजली की मोटर खोलकर न ले जाएं। लेकिन पिछले नौ साल से यूपी में सुकून है।

## मुठभेड़ में हिंदू ज्यादा मारे गए

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुठभेड़ में शांति अपराधियों के एनकाउंटर में मारे जाने को मुद्दा बनाना चाहते हैं, विपक्ष के नेता हैं उन्हें बनाना भी चाहिए। लेकिन क्या ये मुद्दा उनके लिए विधानसभा चुनाव में जीत दिला सकेगा? जरा साचिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में 2017 से मई 2026 तक 17,044 पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) हुई हैं। यानी औसतन 5 मुठभेड़ रोजाना हुई हैं। इन एनकाउंटर के दौरान 34,253 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए। 290 इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान मारे गए। जबकि 11, 834 अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में ऐसा नहीं है कि बदमाश ही मारे गए अथवा घायल हुए। 18 पुलिसकर्मी भी कुख्यात बदमाशों की गोली से शहीद हुए हैं। जबकि 1053 पुलिसकर्मी एनकाउंटर में अपाधियों की गोली से घायल हुए हैं। पुलिस रिकार्ड के अनुसार पिछले नौ वर्षों में अपराधियों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ 68 मुस्लिम अपराधी ढेर हुए। जबकि ब्राह्मण समाज के 20 शांति अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। क्षत्रिय समाज के 19 अपराधी पुलिस के साथ एनकाउंटर में हमेशा के लिए सो गए। 18 जाट और गूर्जर इनामी बदमाश भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। इसी तरह एसी 14 एसटी 3 ओबीसी 8 व अन्य धर्मों के 42 अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस लिहाज से जो नेता और कट्टरपंथी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ यूपी में साजिश हो रही है, या मुठभेड़ में सिर्फ मुसलमानों को मारा जा रहा है तो उन्हें ये आंकड़े देख लेने चाहिए। आंकड़े गवाह हैं कि 68 मुस्लिमों के मुकाबले 177 हिंदू पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं। 2017 में हुई मुठभेड़ में 15 मुस्लिम 12 हिंदू इनामी अपराधी मारे गए थे। 2018 में 15 मुस्लिम व 26 हिंदू, 2019 में 23 मुस्लिम व 21 हिंदू, 2020 में 6 मुस्लिम व 20 हिंदू, 2021 में 5 मुस्लिम और 21 हिंदू, 2022 में 1 मुस्लिम तथा 12 हिंदू, 2023 में 10 मुस्लिम व 16 हिंदू, 2024 में 4 मुस्लिम व 21 हिंदू, 2025 में 14 मुस्लिम और 28 हिंदू

- उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं, यहां पुलिस 4,813 एनकाउंटर में 8,921 अपराधी गिरफ्तार किए, 3,513 इनामी अपराधी घायल हुए और 97 कुख्यात अपराधियों की मुठभेड़ में मौत हो गई, मेरठ जोन में हुई मुठभेड़ों में 477 पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए।
- योगी की सरत कानून व्यवस्था को कोर्ट तक में चुनौती दी गई, लेकिन योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति को देश के बड़े-बड़े वकील रोक नहीं पाए, वो चाहे योगी का बुल्डोजर मॉडल हो या फिर एनकाउंटर मॉडल, ये दोनों मॉडल अपनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, जिससे अपराधियों में खौफ है और जनता बेखौफ है।

अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं।

## मेरठ एनकाउंटर में टॉप पर

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एनकाउंटर मेरठ जोन में दर्ज हुए हैं। यहां पुलिस 4,813 एनकाउंटर में 8,921 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि 3,513 इनामी अपराधी घायल हुए और 97 कुख्यात अपराधियों की मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। मेरठ जोन में हुई मुठभेड़ों के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए तथा दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एनकाउंटर में पूरे प्रदेश में मेरठ जोन पहले स्थान पर रहा है। इसी तरह वाराणसी जोन में 1,292 मुठभेड़ हुईं, जिनमें 2,426 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 29 कुख्यात इनामी अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया। अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान जहां 907 अपराधी घायल हुए वहीं 104 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। पूरे प्रदेश में वाराणसी जोन एनकाउंटर कार्रवाई में दूसरे स्थान पर है। एनकाउंटर में आगरा जोन प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। यहां 2,494 एनकाउंटर हुए जिनमें 5,845 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान 968 शांति अपराधी घायल हुए जबकि 24 अपराधी मुठभेड़ में पुलिस की गोली से मारे गए। मुठभेड़ों के दौरान 62 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बरेली जोन की पुलिस के साथ 2,222 मुठभेड़ हुईं। दोनों तरफ से चली गोलियों के बीच 21 दुर्दांत इनामी अपराधी मारे गए। लखनऊ जोन में 971 अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें 20 अपराधी मारे गए। गाजियाबाद कमिश्नरी में 7,89 मुठभेड़ों में 19 अपराधी मारे गए। उत्तर प्रदेश की सभी कमिश्नरी में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। कानपुर जोन में 791 मुठभेड़ों में 12 अपराधी मारे गए। प्रयागराज जोन में 643 मुठभेड़ों में 11 अपराधियों को मारा गया। गौतमबुद्ध नगर में 1,144 मुठभेड़ों में 9 अपराधी मारे गए। गोरखपुर जोन में 699 मुठभेड़ों में 8 अपराधी मारे गए।

## यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में यूपी पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति को धरातल पर उतारा है। इससे अपराधियों में भय और आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। यही वजह है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने संगठित अपराध, माफिया और अवैध वसूली पर सख्त प्रहार किया। एनकाउंटर के साथ ही संपत्ति कुर्की, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और एनएसए जैसे कानूनों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया है। पुलिस की त्वरित, कठोर और साहसिक कार्रवाई ने अपराधियों को प्रदेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जब हिस्ट्रीशीटर अथवा कुख्यात अपराधी थानों में खुद सरेंडर करने पहुंचे और अपराध से दूरी बनाने की कसमें तक खाई है। योगी की इस सख्ती को कोर्ट तक में चुनौती दी गई, लेकिन योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति को देश के बड़े बड़े वकील रोक नहीं पाए। वो चाहे योगी का बुल्डोजर मॉडल हो या फिर एनकाउंटर मॉडल। ये दोनों मॉडल अपनी स्पीड से दौड़ रहे हैं। जिससे अपराधियों में खौफ है और जनता बेखौफ है।●

# अछूता दूरिस्ट प्लेस खिरसू

प्रकृति प्रेमियों के लिए खिरसू गांव स्वर्ग के समान है, इस गांव में सेब, आड़ू और बेर के हरे-भरे बगीचों में सैर सपाटा कर सकते हैं, ताजे फलों का स्वाद चख सकते हैं, ये बगीचे विशेष रूप से फल लगने के मौसम में रंगों की एक अद्भुत छटा बिखेरते हैं, सैलानी इन बागों में इत्मीनान से टहल भी सकते हैं।

# 3



कमल कपूर  
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यानी हरी-भरी घाटियों, नदियों और झरनों, फूलों की घाटी, चारधाम, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैम्पिंग, पैराग्लाइडिंग, संस्कृति और खान पान के लिए काफी मशहूर है। उत्तराखंड में घूमने के लिए एक से एक सुंदर जगह है। पहाड़ी राज्य की पहचान न सिर्फ हिल स्टेशनों से है बल्कि अपने अनोखे, लुभावने और सांस्कृतिक स्वरूप से समृद्ध गांवों की वजह से भी है। कई दूरिस्ट ऐसे होंगे जिन्हें फेमस डेस्टिनेशन घूमने के बजाए, ऑफबीट जगहों पर घूमना सबसे ज्यादा पसंद होता है। कुछ दूरिस्ट तो ऐसे भी होंगे, जिन्हें पहाड़ी गांवों की शांत संस्कृति अच्छी लगती होगी। अगर आप इन गर्मियों में किसी ऑफबीट जगह पर घूमना चाहते हैं, तो इस बार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की शांत पहाड़ियों में बसा खिरसू गांव का प्लान कर सकते हैं। यह एक सुरम्य और शांत गांव है, जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक ताजगी भरा अहसास करता है। 1,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शांत खिरसू गांव देवदार और बलूत के पेड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे प्रकृति की गोद में एकांत चाहने वाले यात्रियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। पौड़ी गढ़वाल से मात्र 15 किलोमीटर दूर खिरसू गांव एक अनछुआ दूरिस्ट प्लेस है, जिसमें आज भी एक अछूते डेस्टिनेशन का आकर्षण बरकरार है। यह छिपा हुआ स्वर्ग उन लोगों के लिए एकदम सही है जो भीड़-भाड़ से दूर उत्तराखंड के आम पर्यटक स्थलों से हटकर एक ताजगी भरी छुट्टी बिताना चाहते हैं। हालांकि खिरसू गांव अब धीरे-धीरे पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसने अपना शांत वातावरण बरकरार रखा है, जो इसे प्रकृति की गोद में सुकून भरी छुट्टी की तलाश करने वालों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। चाहे प्रकृति प्रेमी हों, फोटोग्राफर हों या बस कुछ समय के लिए आराम करना चाहते हों, खिरसू गांव एक ऐसा अनुभव देता है जो आपको तरोताजा कर देगा और सीधे प्रकृति से जोड़ देगा।

## खूबसूरती व शांति का अनूठा संगम

खिरसू गांव में खूबसूरती और शांति का अनूठा संगम है। हरे-भरे नजारों से घिरा यह गांव बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियों के मनोरम दृश्य का करीब से दर्शन करता है, जो एक ऐसी शांति का अनुभव देता है जिसकी तुलना कुछ अन्य हिल स्टेशनों से ही की जा सकती है। लहरदार पहाड़ियां, देवदार और बलूत के घने जंगल और विशाल खुले



मैदान शांत प्रकृति की सैर या शांति का आनंद लेते हुए किताब पढ़ने के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। यह गांव अपेक्षाकृत अनछुआ ही है, जो इसे उत्तराखंड के अन्य प्रसिद्ध पहाड़ी दूरिस्ट प्लेस पर उमड़ने वाली पर्यटकों की भीड़ से दूर शांतिपूर्ण आराम चाहने वालों के लिए एक परफेक्ट स्थान बनाता है। स्वच्छ हवा, कम शोर और शांत वातावरण आधुनिक जीवन की भागदौड़ से मुक्ति दिलाते हैं, जिससे आप सचमुच आराम कर सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए खिरसू गांव स्वर्ग के समान है। इस गांव में सेब, आड़ू और बेर के हरे-भरे बगीचों में सैर सपाटा किया जा सकता है। ताजे फलों का स्वाद चखा जा सकता है। ये बगीचे विशेष रूप से फल लगने के मौसम में रंगों की एक अद्भुत छटा बिखेरते हैं। सैलानी इन बागों में इत्मीनान से टहल भी सकते हैं, खिलते फलों की मीठी सुगंध का आनंद ले सकते हैं और ठंडी पहाड़ी हवा का लुफ्त उठा सकते हैं। इस क्षेत्र की सुंदरता मौसम के साथ बदलती रहती है। गर्मियों में हरे-भरे नजारे, वसंत में जीवंत बाग और सर्दियों में बर्फ की चादर, जो हर यात्रा को एक अनूठा अनुभव कराती है। गांव के जंगल प्रकृति की सैर और ट्रेकिंग के लिए बेहतरीन अवसर यहां मौजूद हैं। ताजगी भरी हरी-भरी हरियाली शांतिपूर्ण पैदल यात्रा के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां सैलानी पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट का आनंद ले सकते हैं। खिरसू गांव का दूरस्थ स्थान यह सुनिश्चित करता है कि यह कम से कम अशांत रहे, ताकि सैलानी वास्तव में प्रकृति को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव कर सकें।

खिरसू के प्रमुख आकर्षणों में से एक गांव का घडियाल देवता मंदिर भी है, घडियाल को समर्पित मंदिर पहाड़ों की शांत और निर्मल गोद में आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है, घडियाल देवता मंदिर का स्थानीय लोग बहुत सम्मान करते हैं, यहां भगवान घडियाल देवता की विशेष पूजा-अर्चना के साथ हर साल मेला आयोजित होता है।

## आध्यात्मिक शांति का केंद्र

पौड़ी गढ़वाल में खिरसू गांव के प्रमुख आकर्षणों में से एक घडियाल देवता मंदिर भी है, जो गांव के निकट है। घडियाल को समर्पित मंदिर पहाड़ों की शांत और निर्मल गोद में आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। घडियाल देवता मंदिर का स्थानीय लोग बहुत सम्मान करते हैं। यहां भगवान घडियाल देवता की विशेष पूजा-अर्चना के साथ हर साल मेला आयोजित होता है। मेला बारी-बारी से कोठगी व ग्वाड़ गांव में आयोजित होता है। जिसमें काठ का एक पुतला बाबला घास से तैयार रस्सी के सहारे 450 से 500 मीटर फिसलता है। जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। यहां घडियाल देवता के पशु अवतरित होते हैं। मेले में ग्रामीण व प्रवासी ग्रामीण बड़-चढ़कर प्रतिभाग करते हैं। लोकमान्यता के अनुसार घडियाल देवता को अभिमन्यु का अवतार मान कर पूजा की जाती है। इसके अलावा ज्वालपा देवी मंदिर में नवरात्रों के दौरान विशेष अनुष्ठान और मेले आयोजित किए जाते हैं, जहां आसपास के सभी गांवों के लोग एकत्रित होकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। गांव के निवासी हरेला (पर्यावरण से जुड़ा पर्व) और बसंत पंचमी जैसे त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इन अवसरों पर पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और लोकगीतों के जरिए अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है।

## खिरसू गांव की खतरनाक परंपरा

खिरसू गांव की एक अनोखी परंपरा है। यहां पर कठबद्धी मेले का आयोजन भी होता है। माना जाता है कि इस परंपरा को निभाने से क्षेत्र में उन्नति होती है और किसी भी तरह की आपदा से गांववासी प्रभावित नहीं होते। इस अनोखी एवं खतरनाक परंपरा को निभाने के लिए लकड़ी के एक गोड़े के बीचों बीच एक छेद कर उससे आर पार एक रस्सा बांध कर टांगा जाता था। फिर ऊंची जगह से उस पर बड़ा या बड़ी जाति के पुरुष को बैठा कर छोड़ा जाता था। लकड़ी का गोड़ा अपने सवार समेत सरपट नीचे जाता था, जिसमें कभी-कभी गोड़े पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। हालांकि अब इसमें मनुष्य की जगह लकड़ी के पुतले का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की

खिरसू गांव की संस्कृति में अतिथियों को भगवान तुल्य माना जाता है, गांव में बहुत कम परिवार रहते हैं उनके जीवन जीने का तरीका इतना विनम्र और सरल है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, यहां गढ़वाली संस्कृति, पहाड़ी जीवन शैली, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन यापन करने का तरीका का अनुभव मिलेगा।

परंपरा को गांववासी अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह समाज इतना निरंकुश था कि एक गरीब बुढ़ी जाति के व्यक्ति को 10 सेंटीमीटर मोटी व 400 मीटर लम्बी रस्सी में एक लकड़ी की गोड़ी पर बैठाकर उसके दोनों पांवों में 450 ग्राम मिट्टी या रेत के थैले बांधकर एक गरीब के माध्यम से ऊंची चोटी से नीचे खेतों या गांव तक फिसलने को मजबूर करता था। अगर वह फिसल कर सुरक्षित बच भी जाए तो भी उस व्यक्ति को मार दिया जाता था या गिरकर घायल हो जाए तब भी मार दिया जाता था। क्योंकि ऐसा करने से क्षेत्र की समस्त आपदाएं टल जाती थी जैसे अतिवृष्टि होना, ओलों से फसल चौपट होना, अत्याधिक हिमपात होना, अकाल पड़ना, महामारी आना, खेतों में खड़े अन्न की बालों में अन्न न आना, भंडारण अन्न को चूहों द्वारा नुकसान पहुंचाना, बाघ, भालू, बंदरों व जंगली सुअरों द्वारा गांव और घर में आतंक मचाना, हल जोतते समय हल की फाल पर सर्प लिपटना, अत्याधिक सर्पों का निकलना, गाय के स्तन से खून निकलना, पशुधन की हानि होना। भूकंप से भयंकर तबाही मचना, नदियों में बाढ़ आना व उपजाऊ जमीन बहना। जनधन, मानव हानि होना, देवदोष लगना। परियों द्वारा उत्पात मचाना इत्यादि। इस सबसे समाज को मुक्ति दिलाने वाली एक जाति गंधर्भ इस देवभूमि में आदिकाल से निवास करती रही है। आदिपर्व 669, 288 में इस जाति का हिमालयी क्षेत्र में निवास बताया जाता रहा है व इस जाति के मनुष्यों की संख्या तब 88000 के लगभग आंकी गई थी। गंधर्भ या बुढ़ी शिभक्त होते हैं जो मध्य हिमालय में निवास करते हैं व नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं। गढ़वाल हिमालय में इन्हें साक्षात् शिव इसलिए माना गया है क्योंकि जब भी समाज पर विपत्ति पड़ी इस बुढ़ी समाज ने अपना बलिदान देकर संपूर्ण समाज की रक्षा की है।

## ऋषियों का विश्राम स्थल

घने जंगलों के बीच स्थित ये मंदिर आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के मनोरम दृश्यों का दर्शन करते हैं, जो इसे ध्यान और चिंतन के लिए एक शांत स्थान बनाता है। मंदिर का शांत और एकांत स्थान इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है, जिससे आगंतुकों को ऐसी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। ये मंदिर और इसके आसपास का इलाका उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर शांति और ईश्वर से जुड़ाव की तलाश में हैं। इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता इसे प्रकृति और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों के लिए एक देखने योग्य तीर्थस्थान बनाती है। खिरसू गांव उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बसा प्राचीन हिमालयी गांव बताया जाता है। हालांकि ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका व्यापक उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी अपनी शांति और आध्यात्मिक वातावरण के कारण यह गांव लंबे समय से संतों और ऋषियों का विश्राम स्थल रहा है। यह क्षेत्र पर्यटन की चकाचौंध से दूर, चुपचाप गढ़वाली परंपराओं का संरक्षक बना हुआ है। खिरसू गांव पहुंच कर आप चाहे घने जंगलों की सैर करें, घडियाल देवता मंदिर के दर्शन करें या बस मनोरम दृश्यों का आनंद लें, खिरसू आपको जीवन भर कभी न भूलने वाली यादें देगा। क्योंकि गांव की स्थानीय संस्कृति में अतिथियों को भगवान तुल्य माना जाता है। इस गांव में बहुत कम परिवार रहते हैं और उनके जीवन जीने का तरीका इतना विनम्र और सरल है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कुल मिलाकर यहां गढ़वाली संस्कृति, पहाड़ी जीवन शैली, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन यापन करने का तरीका और कई अन्य प्राकृतिक चीजें देखने का अनुभव मिलेगा। यहां पारंपरिक होम-स्टे में पर्यटकों को पारंपरिक चूल्हे पर बना शुद्ध पहाड़ी भोजन परोसा जाता है। भोजन जमीन पर बैठकर करना होता है और स्थानीय मंडुआ, झंगोरा का प्रयोग यहां के मुख्य पकवानों में शामिल है। स्थानीय ग्रामीण सेब के अलावा पारंपरिक फसलों दालें और हरी सब्जियां उगाते हैं। ●

# ग्रीन गोल्ड बना बांस

बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे कई पहाड़ी जिलों में किसान अब बड़े पैमाने पर पीले बांस की खेती की ओर बढ़ रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि एक बार लगाने के बाद कई साल तक इससे फायदा मिलता रहता है, यही वजह है कि अब लोग इसे पहाड़ों का 'ग्रीन गोल्ड' और भविष्य की खेती मानने लगे हैं।



बाबू सिंह  
वरिष्ठ पत्रकार

शहर में बांस की खेती इन दिनों तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि बांस की खेती के लिए सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। बांस की खेती करके किसान 60 से 80 लाख रुपये की कमाई भी कर सकते हैं। बांस का बाजार मूल्य भी अच्छा मिल जाता है। ऐसे में बांस की खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो रही है। उत्तराखंड में पहले बांस की खेती कुछ क्षेत्रों में सीमित थी। लेकिन अब इसके आर्थिक और पर्यावरणीय फायदों ने इसे पहाड़ के किसान की पसंद बना दिया है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में भी बड़ी संख्या में किसान बांस की खेती को अपनाकर लाखों रुपये की आय कर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो बांस की खेती कम लागत, कम जोखिम और ज्यादा मुनाफा देने वाला मॉडल है, जिसे हर प्रकार की मिट्टी और जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। बांस एक ऐसी फसल है जिसे न अधिक खाद की आवश्यकता होती है, न ही अधिक सिंचाई की। यह मौसम की मार झेलने में भी सक्षम होती है और बंजर जमीन में भी आसानी से उगाई जा सकती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बांस के पौधों को पूरी तरह परिपक्व होने में 3 से 5 साल का समय लगता है, लेकिन एक बार तैयार

होने के बाद यह कई सालों तक लगातार पैदावार देता रहता है। वैसे तो विश्व में बांस की करीब 1500 प्रजाति है जबकि अपने देश भारत में करीब 130 प्रजातियां मिलती हैं। उत्तराखंड में केवल पीला बांस ही नहीं बल्कि काला बांसा, सॉलिड बैम्बू और रिंगाल जैसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अलग-अलग ऊंचाई और जलवायु के अनुसार इन प्रजातियों की खेती की जाती है। रिंगाल खासतौर पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होता है, इससे सुंदर हस्तशिल्प उत्पाद बनाए जाते हैं। वहीं सॉलिड बैम्बू मजबूत निर्माण कार्यों में उपयोगी माना जाता है। राज्य में बांस की विविध प्रजातियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं।

## भूस्खलन रोकेगा बांस

पहाड़ों में तेजी से सूखते जल स्रोत, बढ़ता भूस्खलन और बंजर होती जमीन अब लोगों की बड़ी चिंता बन चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड का पीला बांस उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। यह सिर्फ हरियाली बढ़ाने वाला पौधा नहीं है, बल्कि मिट्टी बचाने, पानी रोकने और ग्रामीणों की कमाई बढ़ाने का मजबूत जरिया भी बन रहा है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे कई पहाड़ी जिलों में किसान अब बड़े पैमाने पर पीले बांस की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि एक बार लगाने के बाद कई साल तक इससे फायदा मिलता रहता है। यही वजह है कि अब लोग इसे पहाड़ों का 'ग्रीन गोल्ड' और भविष्य की खेती मानने लगे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पीला बांस पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है। इसकी मजबूत और गहरी जड़ें पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं, जिससे बारिश के दौरान होने वाले भूस्खलन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। मानसून के दिनों में जहां पहाड़ों में लगातार कटाव बढ़ रहा है, वहां बांस की खेती प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम कर रही है। यही वजह है कि इसे ग्रीन शील्ड भी कहा जा रहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगने से बांस से बने उत्पादों का नया मार्केट बनकर उभर रहा है, अब बांस की क्रॉकरी का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है, यानी प्लास्टिक और कांच तथा स्टील जैसी अन्य सामग्रियों का सबसे टिकाऊ विकल्प बांस बन रहा है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है।

## पहाड़ का भविष्य है बांस

बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों में ग्रामीण अब खेतों की मेड़ों और खाली ढलानों पर पीला बांस लगाने लगे हैं। इससे मिट्टी संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। पर्यावरणविदों का कहना है कि पीला बांस तेजी से बढ़ने वाले पौधों में शामिल है, यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में सोखने की क्षमता रखता है। बांस जलवायु परिवर्तन से लड़ने में काफी मददगार साबित हो सकता है। यह अन्य कई पेड़ों की तुलना में कम समय में अधिक हरियाली देता है। पहाड़ों में बढ़ते तापमान और जंगलों की कटाई के बीच बांस को पर्यावरण संरक्षण का मजबूत विकल्प माना जा रहा है। बांस के बड़े झुरमुट आसपास के वातावरण को ठंडा और स्वच्छ बनाए रखने में भी मदद करते हैं, जिससे जैव विविधता को लाभ मिलता है। पीला बांस पहाड़ों में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। जहां एक ओर यह मिट्टी, पानी और हरियाली को बचाता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की आय बढ़ाने में मदद करता है। तेजी से बदलते मौसम और बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के दौर में बांस की खेती को सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प माना जा रहा है। स्थानीय किसानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। यानी अब बांस को उत्तराखंड के पहाड़ों का भविष्य कहा जाने लगा है।

## बंजर जमीन में बांस की खेती

उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बंजर और खाली पड़ी जमीन अब पीले बांस की वजह से दोबारा उपयोग में लाई जा रही है। बांस कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से उग जाता है। धीरे-धीरे मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। इसकी पत्तियां जमीन पर गिरकर प्राकृतिक खाद का काम करती हैं, जिससे मिट्टी में जैविक तत्व बढ़ते हैं। पहाड़ के किसान अब उन खेतों में भी बांस लगाने लगे हैं, जहां पारंपरिक फसलें अच्छी नहीं हो पा रही हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिल रहा है। साथ ही खाली जमीन हरियाली में बदल रही है। आने वाले समय में बांस पहाड़ों की बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने का बड़ा माध्यम बन सकता है। पीला बांस उत्तराखंड के ग्रामीणों के लिए रोजगार का मजबूत साधन भी बनता जा रहा है। बांस से बनी टोकरीयां, डलिया, फर्नीचर, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं बाजार में अच्छी कीमत पर बिक रही हैं। खासकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को इससे काफी लाभ मिल रहा है। बागेश्वर और अल्मोड़ा क्षेत्रों में कई परिवार अब बांस आधारित हस्तशिल्प से अपनी आय बढ़ा रहे हैं।

## बांस एक खनिज अनेक

पर्यटन क्षेत्र में भी बांस के उत्पादों की मांग लगातार

बढ़ रही है। ग्रामीण कारीगर पारंपरिक कला को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़कर नए उत्पाद तैयार कर रहे हैं। जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ रहा है, पलायन रोकने में भी मदद मिल रही है। बांस की पत्तियों में ओरिएंटिन, विटैक्सिन, आइसोओरिएंटिन, ल्यूटोलिन जैसे कई फ्लेवोनोइड्स के साथ फेनोलिक एसिड, क्लोरोफिल, कोलीन और पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। ये सिलिकॉन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे खनिजों का भी समृद्ध स्रोत हैं। इसके अलावा, बांस की पत्तियों में विटामिन सी और विटामिन बी भी मौजूद होते हैं। एक बार पौधे लगाने के बाद लंबे समय तक इससे उत्पादन मिलता रहता है। इसकी देखभाल में अन्य फसलों की तुलना में कम खर्च आता है। यही कारण है कि पहाड़ी किसान अब इसे नकदी फसल के रूप में अपनाने लगे हैं। बाजार में बांस की लगातार बढ़ती मांग किसानों को बेहतर कमाई का अवसर दे रही है। निर्माण कार्यों, फर्नीचर उद्योग और हस्तशिल्प में इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो बांस किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर बैम्बू बोर्ड का प्रस्ताव बेहद अहम होने जा रहा है। दावा है कि इस प्रस्ताव पर पूरी तरह से काम हुआ तो करीब 2 लाख किलोग्राम कार्बन के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। फिलहाल पहली बार उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही इस पर बोर्ड को शासन से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

## प्लास्टिक का विकल्प

सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगने से बांस से बने उत्पादों का नया मार्केट बनकर उभर रहा है। अब बांस की क्रॉकरी का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है, यानी प्लास्टिक और कांच तथा स्टील जैसी अन्य सामग्रियों का सबसे टिकाऊ विकल्प



पर्यावरणविदों का मानना है कि पीला बांस तेजी से बढ़ने वाले पौधों में शामिल है, यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में सोखने की क्षमता रखता है, बांस जलवायु परिवर्तन से लड़ने में काफी मददगार साबित होता है, अन्य पेड़ों की तुलना में कम समय में अधिक हरियाली देता है।

बांस बन रहा है। जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। उधर, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन ने भी नई योजनाएं तैयार की हैं। बांस से 50,000 से अधिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। स्पष्ट है कि घरेलू सामान और निर्माण कार्यों के लिए बांस एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है। बांस से बने उत्पादों में टोकरीयां, चम्मच, स्पैटुला, ट्रे, कोस्टर, कटोरे आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं स्वाद को अवशोषित नहीं करतीं, दाग-धब्बों से सुरक्षित रहती हैं, जीवाणुनाशक होती हैं और लकड़ी के अधिकांश समकक्ष उत्पादों की तुलना में हल्की और अधिक मजबूत होती हैं। देश में बैम्बू इंडिया और अलमिन्ना सस्टेनेबल्स जैसी कई कंपनियां बांस से बने टूथब्रशों की अपनी रेंज के साथ यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आपका दिन धरती के संरक्षण में अपना योगदान देते हुए शुरू हो। ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बायोडिग्रेडेबल हैं और अपनी बेहतरीन फिनिश और सर्विस के साथ जल्द ही आपको अपने प्लास्टिक के टूथब्रशों को अलविदा कहने पर मजबूर कर देंगे। टूथ ब्रश कार्बनयुक्त होते हैं, जिससे वे पानी प्रतिरोधी बन जाते हैं और सामान्य उपयोग के दौरान किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या फफूंद को पनपने से रोकते हैं। इस उत्पाद का उपयोग वयस्क और बच्चे दोनों कर सकते हैं।



# घुसपैठियों में भागदड़ मची

जिन घुसपैठियों के पास फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड हैं वो बांग्लादेश भाग रहे हैं क्योंकि जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही इन घुसपैठियों को किसी की कोई परवाह नहीं थी, किंतु अब पकड़े जाने और होल्डिंग सेंटर में जाने का डर है, बांग्लादेश सीमा पर लगी भीड़ विपक्षी दलों के घुसपैठिया प्रेम के सवालियों का जिंदा जवाब हैं।

# न



डा.वीरेंद्र पुष्पक  
वरिष्ठ पत्रकार

क्सलवाद के सफाये के बाद मोदी सरकार का मिशन 'घुसपैठियों का सफाया' लॉन्च हो गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए घुसपैठ करने का सबसे सुरक्षित और आसान रास्ता पश्चिम बंगाल था। यानी भारत में घुसपैठ की सबसे बड़ी समस्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी जो अब सत्ता से बेदखल हो चुकी हैं और भाजपा की सरकार बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में बांग्लादेश सीमा को सील करने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर कर दी है। घुसपैठियों को चेतावनी दे दी है कि वो खुद पश्चिम बंगाल छोड़ दे वरना पुलिस ने

गिरफ्तार किया तो उन्हें जेल में नहीं बल्कि होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। इससे पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी में खलबली मची हुई है। गिरफ्तारी और होल्डिंग सेंटर में जाने के डर से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या खुद अपना सामान समेट कर भारत से भागना चाहते हैं। क्योंकि शुभेंदु सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद में होल्डिंग सेंटर बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए रखना शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी के पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं कि बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों को न तो रोका जाए न जेल भेजा जाए न ही होल्डिंग सेंटर भेजे बल्कि उन्हें बीएसएफ के हवाले कर दें। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के हवाले करेगी। शुभेंदु सरकार कानूनी पचड़े में पड़कर घुसपैठियों को मुफ्त में माछ-भात खिलाने के मूड में नहीं हैं। शायद इसी खौफ से उत्तरी 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वाले घुसपैठियों की भीड़ लग गई। बंगाल से जो घुसपैठिए खुद-ब-खुद अपने देश लौटना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन जो घुसपैठिए छिपने की कोशिश में हैं, उन्हें खोज-खोज कर होल्डिंग सेंटर भेजने का काम चल रहा है। ये हालत सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही नहीं है, बल्कि जो बांग्लादेशी कई साल पहले अवैध तरीके से भारत में घुसे और देश के हर कोने में जाकर बस गए, वो बंगाल बॉर्डर पहुंच कर जल्द से जल्द बांग्लादेश पहुंचना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश वो घुसपैठिये हैं जिनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड हैं, लेकिन सब फर्जी हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रही इन घुसपैठियों को किसी की कोई परवाह नहीं थी, अब पकड़े जाने और होल्डिंग सेंटर में जाने का डर है। बांग्लादेश सीमा पर लगी घुसपैठियों की भीड़ विपक्षी दलों के घुसपैठिया प्रेम के सवालियों का जिंदा जवाब हैं। यह बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद देखा जा रहा है।

## डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन करेगी समिति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल यानी 15 अगस्त, 2025 को लालकिले के प्राचीर से कहा था कि डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के अध्ययन करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। इस वादे को अब पूरा किया जा रहा है। गृह

बम फेंकने और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले टीएमसी नेता शमीम अहमद और आकाश सिंह को शुभेंदु की पुलिस ने गिरफ्तार कर कच्चा बनियान में सड़क पर परेड कराकर लोगों की दिल और दीमाग से शमीम और आकाश की दहशत निकाल दी।

मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ की वजह से देश की डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है। जो घुसपैठ के कारण देश में अप्राकृतिक रूप से डेमोग्राफी में हुए बदलाव का अध्ययन करेगी। समिति में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस समिति के पदेन सचिव होंगे। समिति में भारत के जनगणना आयुक्त को भी शामिल किया गया है। ये समिति बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से भारत में होने वाली घुसपैठ के कारण और निवारण का अध्ययन कर एक साल में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही मिशन 'घुसपैठियों का सफाया' के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों का दौरा भी शुरू कर दिया है। वह सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों और अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। गृह मंत्री भारत की सीमाओं को इतना सुरक्षित करना चाहते हैं कि कोई कॉकरोच भारत में घुस न पाए और जो कॉकरोच घुसे हैं उन्हें भारत से खदेड़ा जा सके।

## ममता घुसपैठ में बाधा थी

गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमारी सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन-चुन कर निकाला जाएगा। अमित शाह पहले तो कोई कमेंट करते नहीं हैं और कमेंट करते हैं तो डेफिनिटी पूरा करते हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि भारत से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन भी दी थी। कमेंट किया था लिहाजा देश से नक्सलवाद को खत्म भी कर दिखाया। अब घुसपैठियों को खदेड़ने का कमेंट पूरा करने की बारी है। अभी तक मिशन घुसपैठियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार मिशन में बाधा थी। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से बाड़बंदी के लिए 142.79 एकड़ जमीन मांग रही थी, लेकिन ममता ने सत्ता में रहते हुए यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। लेकिन सत्ता बदलते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी और सुरक्षा चौकियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी। अब बंगाल के 9 जिलों की सीमाएं सील होंगी, सुरक्षित होंगी और घुसपैठ तथा गौवंश तस्करी पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही एक्शन शुरू हो गया। राजनीतिक बदलाव का असर दिखाई देने लगा है।

## शुभेंदु अधिकारी का खौफ

भाजपा की सरकार और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने का इतना खौफ है कि जो घुसपैठिए दशकों पहले भारत में अवैध तरीके से घुसे थे उन्हें अब खतरा नजर आने लगा है। उत्तरी 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगी तो मीडिया भी कवरेज के लिए पहुंच गया। यहाँ मीडिया ने बांग्लादेश जाने वाले घुसपैठियों से बात की तो कुछ घुसपैठियों ने टूटी-फूटी हिंदी में बताया कि वो ममता सरकार के हटने से खुश नहीं है। ममता बनर्जी के राज में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी बल्कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता था। उनकी जिंदगी आसान थी। काम धंधा भी मिल जाता था, रहने के लिए सरकारी जमीन मिल गई थी। जिसका जहां मन हुआ वहां घर बना लिया था, लेकिन भाजपा की शुभेंदु सरकार ने तो एक महीने में ही जीना दुश्वार कर दिया, इसलिए अपने देश लौटने में ही भलाई है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या ममता बनर्जी भारत के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा थीं? क्योंकि विदेशी मुस्लिम भारत में अवैध रूप से घुस कर मुफ्त का राशन खा रहे थे। मुफ्त में जमीन पर कब्जा कर लिया था। सरकारी योजनाओं को भरपूर लाभ उठाते रहे। पश्चिम बंगाल की दशा तो ये थी कि भले भी पश्चिम बंगाल के मूल निवासी को सरकारी योजना का लाभ न मिला हो, लेकिन कोई घुसपैठिया योजना से वंचित नहीं रहा होगा। यानी विदेशी ताकतों ने गजबा-ए-हिंद के लिए भारत के संसाधनों और भूमि पर कब्जा कर लिया था। ये घुसपैठिये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी भारतीयों के टैक्स पर घुसपैठियों को क्यों पाल रही थी? क्या ममता गजबा-ए-हिंद का हिस्सा थी?

## बंगाल के बाहुबलियों का इजाल

पश्चिम बंगाल में जब तक ममता रही कानून व्यवस्था पुलिस के बजाये टीएमसी के गुंडों के हाथ में रही, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल में टोलेबाजों, कटमनी, घोटालेबाजों, सिंडिकेट चलाने वालों और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों से लेकर टीएमसी के एक-एक बाहुबलि और माफिया का इलाज शुभेंदु सरकार कर रही है।

- मिशन 'घुसपैठियों का सफाया' के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है, वह सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों और अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं, गृह मंत्री भारत की सीमाओं को इतना सुरक्षित करना चाहते हैं कि कोई कॉकरोच भारत में घुस न पाए और जो कॉकरोच घुसे हैं उन्हें भारत से खदेड़ा जा सके।
- गृह मंत्री अमित शाह पहले तो कोई कमेंट करते नहीं हैं और कमेंट करते हैं तो डेफिनिटी पूरा करते हैं, उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने का कमेंट किया था, लिहाजा देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया, अब घुसपैठियों को खदेड़ने का कमेंट पूरा करना है, अभी तक घुसपैठ के खिलाफ कोई ठोस एक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार मिशन में बाधा थी।

बादरिया नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य को जांच के बाद 24 मई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस और जांच एजेंसियों ने एक खेत में खुदाई कर नोटों से भरे बैग और बोरियां बरामद की। जिनमें 2.24 करोड़ की मोटी रकम थी। पुलिस ने कैश जब्त कर लिया है। इससे पहले उसके दफ्तर से भी 40 लाख रुपये बरामद हुए थे। नगर पालिका भतीं घोटाले में ममता सरकार के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बोस पर पैसों के बदले अवैध नियुक्तियों और ओएमआर शीट में हेरफेर का आरोप है। ममता सरकार में जिस सोना पप्पू उर्फ पप्पू डॉन उर्फ विश्वजीत पोद्दार का खौफ था उसे भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात पप्पू डॉन उर्फ सोना पप्पू विवादित जमीनों पर कब्जा करने, अवैध वसूली (कटमनी) और मनी लॉन्ड्रिंग का संगठित गैंग चलाता था। ममता राज में सोना पप्पू को अफसर तक सलाम ठोकते थे। विधाननगर में स्थानीय पार्श्व दुशोभन मंडल उर्फ माइकल और उसके करीबी अभिजीत पोल्ले को अवैध वसूली करने और सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? हावड़ा के शिवपुर इलाके में बम फेंकने और फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले टीएमसी नेता कुख्यात शमीम अहमद और आकाश सिंह को शुभेंदु की पुलिस ने जिस समय गिरफ्तार किया वो अर्धनग्न हालत में थे, पुलिस ने दोनों कुख्यात अपराधियों को कपड़े पहनने तक का मौका नहीं दिया। बल्कि शमीम और आकाश की दहशत दूर करने के लिए दोनों टीएमसी नेताओं को अर्धनग्न (कच्छ और बनियान पहने) हालत में सड़कों पर घुमाया। पुलिस का इस मामले में कहना था कि दोनों कुख्यात अपराधियों को पैदल सड़क पर घुमाना क्राइम रिकॉस्ट्रक्शन करना और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क को जांच का हिस्सा था। आकाश सिंह पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली सहित 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों के सिर मुंडन और अर्धनग्न अवस्था में परेड कराने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पुलिस के इस तरीके ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसकी तुलना उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई से की जा रही है। यही नहीं ममता बनर्जी के राज में संदेशखाली में महिला उत्पीड़न करने, हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने वाले टीएमसी नेता श्रीदाम हाउली अब कानून के शिकंजे में है। बांकुड़ा में टीएमसी छात्र उपाध्यक्ष सूरज बक्स को डकैती की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता, विधाननगर, हावड़ा, हुगली आदि से टीएमसी के करीब 70 से ज्यादा नेताओं और जनप्रतिनिधियों को पुलिस व अन्य एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का यह सिलसिला अभी शुरू हुआ है कहां जाकर रुकेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह तो तय है कि शुभेंदु अधिकारी के राज में भ्रष्टाचारी, अवैध वसूली, चुनाव बाद हिंसा करने वालों, संगठित होकर अपराध करने वालों, डराने धमकाने वालों की खैर नहीं है। पश्चिम बंगाल में अब अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए शुभेंदु सरकार ने कदम उठा लिया है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्राथमिकता के आधार पर शुरू की गई है। सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक हस्तियों से पृच्छाछ की जा रही है और कुछ मामलों में नकदी की बरामदगी के बाद गिरफ्तारियां की गई हैं। ●

# भारत-नेपाल संबंध सुधरेंगे ?

नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में भारत से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क और कड़े नियम लागू करने के कारण इस ऐतिहासिक रिश्ते पर असर पड़ रहा है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि के कारण बिना पासपोर्ट व वीजा के आवाजाही, पढ़ाई, और नौकरी की सुविधा है।



# प



सुहैल जैदी  
वरिष्ठ पत्रकार

डोसी मुल्क नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ क्या भारत नेपाल रिश्ते और बेहतर होने वाले हैं? हालांकि भारत और नेपाल के आपसी संबंधों का जिक्र आते ही कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है। यानी भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में शादियां आम बात हैं। भारत की बेटियां नेपाल के घरों की बहू बनती हैं तो नेपाल की बेटियां भारत में दुल्हन बनकर आती हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक निर्भरता है। नेपाल के लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं, जिससे रोजी-रोटी का गहरा संबंध बनता है। दोनों देशों के बीच न केवल खुली सीमा है, बल्कि दोनों देशों में एक जैसी भाषा (मैथिली, भोजपुरी, नेपाली), संस्कृति, और त्योहार (छठ व दीपावली) भी पारंपरिक रूप से मनाए जाते हैं। लेकिन नेपाल सरकार द्वारा हाल ही में भारत से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क और कड़े नियम लागू करने के कारण इस ऐतिहासिक रिश्ते पर असर पड़ रहा है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि के कारण बिना पासपोर्ट व वीजा के आवाजाही, पढ़ाई, और नौकरी की सुविधा है। लेकिन भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल द्वारा कड़े चेक प्वाइंट बनाने और सख्ती बरते जाने से अब रोटी-बेटी के इस अनूठे रिश्ते पर ग्रहण लगने की बात कही जा रही है, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए दैनिक आवाजाही चुनौतीपूर्ण हो गई है।

## बालेन के सामने चुनौती

बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल की नई सरकार को सत्ता में आए हुए अभी दो

महीने ही हुए थे कि बालेन शाह सरकार के सामने एक के बाद एक घरेलू और वैश्विक समस्या आने लगी हैं। बालेन सरकार को अपने छोटे से कार्यकाल में दो प्रमुख मंत्रियों के इस्तीफे के कारण अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। गृह मंत्री सुदन गुरुंग को वित्तीय लेन-देन और निवेश से संबंधित आरोपों के कारण मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। श्रम मंत्री दीपक कुमार साह को अपनी ही पत्नी को सरकारी बोर्ड में नियुक्ति देने की वजह से मंत्री पद गवांन पड़ा। यह हालात इसलिए चिंताजनक है, क्योंकि बालेन शाह का सत्ता में आना युवाओं के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रेरित था। ऐसे में उनके मंत्रिमंडल में कदाचार के किसी भी आरोप से उनके सुधार एजेंडे की विश्वसनीयता को बट्टा लगेगा। सरकार की बढ़ती अस्थिरता के कारण नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विशेष कारणों का हवाला देते हुए संसद के दोनों सदनों का 30 अप्रैल को होने वाला सत्र स्थगित कर दिया था। यह नई सरकार के नेतृत्व के शुरुआती कार्यकाल में ही सबसे बड़े सियासी संकट होने के संकेत देता है। वैश्विक तनावों, खासकर मिडिल ईस्ट संकट ने कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति को बाधित किया है, जिससे नेपाल में डीजल व पेट्रोल के मूल्यों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। वैसे भी नेपाल दक्षिण एशिया का वो देश है, जहां डीजल व पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है। लिहाजा ट्रांसपोर्ट अपने आप में महंगी होगी तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं का महंगा होना स्वाभाविक ही है। महंगाई के साथ ही सेवा की लागत में भी वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ी है। इस मुश्किल घड़ी में नेपाल ऊर्जा आपूर्ति के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। डीजल और पेट्रोल की किल्लत होने पर कई बार स्थिति अति संवेदनशील हो जाती है। लिहाजा आलोचना का सामना

नेपाल ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है, डीजल और पेट्रोल की कमी होने पर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है, नेपाल सरकार ने ईंधन की खपत कम करने के लिए 2 दिन का वीकेंड लागू किया है। बालेन का यह एक्शन दैनिक जीवन व आर्थिक गतिविधि पर पड़ने वाले असर को दर्शाता है।

करती बालेन सरकार को ईंधन की खपत कम करने के लिए दो दिन के वीकेंड जैसे उपाय लागू करने पड़े। सरकार का यह एक्शन ऊर्जा संकट की गंभीरता, दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर को दर्शाते हैं। नेपाल में पेट्रोल और डीजल महंगा होने से नेपाली वाहन चालक भारत आकर डीजल पेट्रोल ले रहे हैं।

## नेपाली जनता में आक्रोश

वैश्विक संकट की वजह से भारत भी कच्चे तेल के संकट से अछूता नहीं है, फिर भी मुश्किल समय में पड़ोसी नेपाल और उसके लोगों की मदद की जा रही है। यह भारत की 'नेबर फर्स्ट' की नीति के अनुरूप ही है, जिसका सबूत कोरोना संकट के समय भी देखने को मिला था। हाल ही में बालेन शाह सरकार ने 100 रुपये से ज्यादा के मूल्य पर कोई सामान विदेश से लाने पर टैक्स लगा दिया था। किंतु भारत-नेपाल की सीमा खुली होने से हजारों नेपाली रोजाना अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए भारतीय सीमा के आसपास के बाजारों से खरीदारी करते हैं। क्योंकि नेपाली जनता पहले से ही महंगाई और महंगे पेट्रोल से परेशान थी। अब इस नए टैक्स ने लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा कर दिया है। क्योंकि नेपाल ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं सहित अपनी जरूरत के सामान का एक बड़ा हिस्सा भारत से इंपोर्ट करता है, लिहाजा नई शुल्क संरचनाएं खुदरा कीमतों को प्रभावित करती हैं। भारत पर अत्याधिक आर्थिक निर्भरता से नेपाल में छोटे से बदलाव का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा नेपाल की घरेलू उत्पादन क्षमता की कमी इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। नेपाल की नई सरकार अपने बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं, खासकर चीन से जुड़ी परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। इनमें से कई परियोजनाएं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से जुड़ी हैं, जिनमें सड़कें, जलविद्युत संयंत्र और व्यापार गलियारे शामिल हैं।

## चीन व भारत संबंधों में संतुलन का प्रयास

बालेन शाह सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है, इसलिए मौजूदा समझौतों की गहन समीक्षा हो रही है। खासकर ऋण स्थिरता, परियोजना की व्यवहारिकता और दीर्घकालिक आर्थिक लाभों को लेकर चिंता जताई गई है। कुछ परियोजनाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि वे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों और वित्तीय बोझ न डालें। बेशक चीन और भारत के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाने का प्रयास भी नेपाल कर रहा है। चीन जहां नेपाल में निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास की पेशकश करता है, वहीं भारत नेपाल का प्रमुख आर्थिक साझेदार बना हुआ है। यह नाजुक संतुलन नेपाल की विदेश नीति का केंद्र बिंदु भी है। नेपाल-चीन परियोजनाओं की नई सरकार द्वारा समीक्षा करना विकास के व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत देती है। ऐसा दृष्टिकोण जो आर्थिक व्यवहारिकता, पारदर्शिता और भू-राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता देता है। 10 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरीशस के पोर्ट लुइस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत उच्च स्तरीय सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया था। दोनों ने सहयोग बढ़ाने और साझेदारी की गति को बनाए रखने पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में विदेश सचिव विक्रम मिसरी के रई में उच्च स्तरीय वार्ता के लिए नेपाल जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि वह आधिकारिक तौर पर बालेन शाह के भारत आने का प्रधानमंत्री का न्योता भी लेकर जाएंगे।

## भारत के साथ संबंध

भारत और नेपाल सदियों से न सिर्फ एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक-दूसरे की सहायता से दक्षिण एशिया में सहयोग-भागीदारी की नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। लीक से हटकर एक स्वतंत्र नेता की अपनी छवि के बावजूद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की इच्छा जताई है, जो कूटनीति के प्रति उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत है। यह भी तथ्य है कि भारत दौरे के लिए औपचारिक तौर पर उन्होंने हामी भर दी है, जो

- डेढ़-दो दशकों में नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ भारत से रिश्ते भी बदलते रहे हैं, पर बालेन शाह की सरकार के सत्ता में आने के महीने भर में किए गए फैसलों ने इन रिश्तों में कड़वाहट बढ़ा दी है, ऐसे में घरेलू और विदेश नीति के मोर्चे पर जूझ रहे पीएम बालेन शाह के सामने पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध कायम रखने की चुनौती है।
- नेपाल को अपने आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ करने होंगे, भारत तथा नेपाल के बीच दशकों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, इन दोनों देशों के बीच संबंध इतने मजबूत हैं कि भारतीय सेना के मौजूदा प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी जाती है।

मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने की उनकी सरकार की उच्च प्राथमिकता को दर्शाती है। नई दिल्ली हालांकि अभी 'वेट एंड वाच' का नजरिया अपना रही है, लेकिन नए सिरे से सहयोग और विकास को लेकर वह भी आशावादी है। भारी बहुमत वाली बालेन शाह सरकार के लिए यह ऐतिहासिक अवसर है कि वह भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।

## प्रधानमंत्री बालेन शाह के सामने चुनौती

वैश्विक संघर्षों के युग में शांति और सहयोग दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। नेपाल को अपने आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए भारत के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ करने होंगे। भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच संबंध इतने मजबूत हैं कि भारतीय सेना के मौजूदा प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि दी जाती है और नेपाली सेना के प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का मानद पद दिया जाता है। दार्जिलिंग के एक कालेज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर ने भारत-नेपाल रिश्तों को करीब से देखा है। वह कहते हैं, बीते खासकर डेढ़-दो दशकों के दौरान नेपाल में सरकार बदलने के साथ ही इन देशों के आपसी रिश्ते भी बदलते रहे हैं। लेकिन बालेन शाह की सरकार के सत्ता में आने के महीने भर के भीतर किए गए फैसलों ने इन रिश्तों में कड़वाहट बढ़ा दी है। ऐसे में घरेलू और विदेश नीति के मोर्चे पर जूझ रहे प्रधानमंत्री बालेन शाह के सामने पड़ोसी देशों के साथ संतुलित संबंध कायम रखने की गंभीर चुनौती है। इसमें वो कितना कामयाब रहते हैं, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपसी संबंधों में मजबूती भारत और नेपाल दोनों के हित में है।

## केदार और पशुपतिनाथ का संबंध

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थिति 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम का सीधा संबंध नेपाल से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, महाभारत काल में युद्ध जीतने के बाद पांडव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। पांडव स्वर्गारोहणी की तलाश में उत्तराखंड के हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। तब भगवान शंकर केदारघाटी में तपस्यारत थे, जहां पांडवों ने उन्हें देख लिया। पांडवों से नाराज भगवान शंकर उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों ने उन्हें इस रूप में भी पहचान लिया। जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शंकर जमीन में समा गए। हालांकि भैंसे का कूल्हा वाला भाग केदारनाथ में रह गया और सिर वाला भाग पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जिसकी मान्यता केदारनाथ की ही तरह है। ●

# रजिया गुंडों में फंस गईं

होर्मुज भाई की रुदाली से ऐसा लगा कि आज की तारीख में होर्मुज उर्फ तंगगेह ए होरमोज से सही सलामत जहाज निकालना ऐसा है जैसे जॉइंट फैमिली में एक पति अपनी वाली को देने के लिए बाजार से कुछ लाए और पूरे परिवार की सीसीटीवी नुमा आंखों में धूल झाँकते हुए सही सलामत वो सामान बीवी के हवाले कर पाए।

# रा



प्रदीप भट्ट  
व्यंग्यकार, मेरठ

त के डेढ़ बजे के करीब चल दूरभाष यंत्रम घनघना उठा। हमने एक-दूसरे से चिपटी अपनी टांगों को बेड से नीचे उतारा और साइड पर रखे स्टूल से चल दूरभाष यंत्रम (मोबाइल) पर मन ही मन बड़बड़ाते झपटा मारा कि ये कौन ससुर है जो इती रात में हमारी नींद में खलल डालने की जुरत दिखा रहा है। जय राम जी करके पूछा आप कौन साब हैं... जो इती रात में हमें खटखटा दिए हो भाई। उधर से सपाट स्वर उभरा 'आईएम होर्मुज, आई टॉक बिहेल्फ ईरान' एक सेकेंड को तो हमारी डिबरी भी टाइट हो गई। लगा कोई पिशाच है जो खाली टाइम में हमारी खाली-पीली फिरकी ले रहा है...इसलिए हमने अपनी आवाज में चाटुकारिता का मकखन और मलाई लपेटते हुए, हद के अंदर रहकर मिमियाते हुए पूछा...कौन होर्मुज जी। शायद होर्मुज को ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसलिए थोड़ा तल्लू लिए हुई आवाज आई बेटा हम ओमन और ईरान के मध्य मात्र 33 किलोमीटर लम्बे समुद्री गलियारे हैं। फारस की खाड़ी से ओमन की खाड़ी को जोड़ते हैं। ये जो तुम अपनी स्कूटीयानम (स्कूटी) चलाते हो न इसमें डलने

वाला तेल हमारी छाती के ऊपर से गुजर कर तुम तक पहुंचता है और हां सुनो रे ये गैस एलएनजी और एलपीजी भी हमारी छाती के ऊपर से होकर तुम तक जाती है, समझे या और समझाऊं। हम कुछ कहते कि फिर से आवाज आई जस्थुस्त्र धर्म (विश्व के अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक) जानते हो अहुरा मजदा हमारे देवता हैं। उन्हीं से हमने नाम झटक लिया है, लल्ला दुनिया का 20 से 30 प्रतिशत और एक करोड़ बैरल रोजाना तेल हमारी छाती चीरकर तुम सब तक पहुंचता है। और हां आखिरी बात फारसी में तंगेह-ए-होरमोज कहलाते हैं हम।

इजराइल का उल्लू सीधा

हमने अपने नैनयों को अच्छी तरह खोलते हुए पूछा महाराज, जे तो बताइए आप हमसे चाहते क्या हो? होर्मुज महाराज की हूँ की आवाज आई फिर बोले देखो प्रदीप बाबू 'भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान' हो रहा है पूरी दुनिया में हा...हाकार...मचा है। यो सिरफिरा ट्रंप तो अमेरिका की ईज्जत की पूरी बेइज्जती का फलूदा बनाकर ही मानेगा। जहां तक सवाल इजरायल का है तो उसने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया। जहां तक सवाल ईरान का है तो इतने सारे नेताओं के मरने के बाद भी वो युद्ध...युद्ध...खेलने का मजा ले रहा है। उसे तो अपनी आवाम की चिंता कतई ना है। अब सब कुछ गंवाकर होश में आएगा भी तो क्या ही उखाड़ लेगा? लेकिन...लेकिन इन सब की गुंडई का खामियाजा तो मुझ अकेले को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप तो सिरफिरा है और नेतन्याहू शातिर लोमड़ी के दिमाग वाला और ईरान, उसे तो आग की भयावता का अंदाजा है, मगर वो अपनी बेवकूफाना हरकतों से आग को आग से बुझाने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी मजे लेने के लिए पूछ ही लिया और पाकिस्तान वो जो शांति शांति का रूख लगा रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? भाई जी कुछ तो स्पेशल टिप्पणी कीजिए। होर्मुज झुंझलाहट से बोला 'बुझा मरे या जवान इसको हत्या से काम।' फिर एक गहरी स्वांस लेकर होर्मुज बोले हमने इसलिए फोन किया कि तुम पहली फुर्सत में

नेतन्याहू ने खीसे निपोरते हुए कहा तुम भी न बुढ़ापे में सठिया गए हो ट्रंप बाबू, देखो तुमने जो जून में ईरान को पेला था वो तो ट्रेलर था, अच्छा एक बात बताओ तुमने सेकेंड वर्ल्डवार के बाद कुल जमा कितनी लड़ाई जीती है? वियतनाम, कोरिया, इराक, अफगानिस्तान अबे सारी की सारी लड़ाई तो हारी है, लेकिन हारकर भी तुम जीतते हो सोचो भला क्यों?

कल ही हमारे ऊपर एक व्यंग्य में हास्य का तड़का लगाते हुए एक आलेख लिख मारो नई तो बाकी का तो पता नहीं पर तुम्हारे पेट की गैस का इलाज हम परमानेंट कर देंगे। ये तो सीधे सीधे लॉरेंस विश्नोई की धमकी सी लगी सो सपना देख रही आंखें एक झटके में खुल गईं। हमने राम जी का नाम लिया और होर्मुज की चेतावनी को सीरियसली लेते हुए अगले दिन अपने जहन में विस्तार से व्यंग्य का खाका खींचना आरम्भ कर दिया। अब इती प्यारी सी धमकी के बाद नींद तो आने से रही न महाराज। लेकिन होर्मुज भाई साहब की रुदाली से ऐसा लगा कि आज की तारीख में होर्मुज उर्फ तंगगेह ए होरमोज से सही सलामत जहाज निकालना ऐसा ही है जैसे जॉइंट फैमिली में एक पति अपनी वाली को देने के लिए बाजार से कुछ लाए और पूरे परिवार की सीसीटीवी नुमा बनी आंखों में धूल झाँकते हुए सही सलामत वो सामान बीवी के हवाले कर पाए।

ट्रंप की चौधराहट का चक्कर

अब मसला इस प्रकार है कि इजरायल और यूएई ने मिलकर अमेरिका को चने के पेड़ पर चढ़ा दिया कि भैया यो जो ईरान है न 92 धड़ी (460 किलो) यूरेनियम संवर्धन करके बैठा है। क्या पता कब परमाणु-परमाणु खेलने लगे इसलिए अगर तुम्हें अपनी चौधराहट सलामत रखनी है तो पहली फुर्सत में इसको पेल दो नई तो भविष्य में ये तुम्हे रगड़ देगा। ट्रंप जो भयंकर वाले अनप्रेडिक्टेबल हैं ने घूरकर नेतन्याहू को देखा फिर आधे गुस्से और आधी हंसी हंस्तते हुए कहा अरे अभी जून में ही तो पेला था टंडा पड़ा होगा, काहे मरे हुए को मरवाते हो रे। नेतन्याहू ने खीसे निपोरते हुए कहा तुम भी न बुढ़ापे में सठिया गए हो ट्रंप बाबू। देखो ऐसा है तुमने जो जून में ईरान को पेला था वो तो ट्रेलर मात्र था...। अच्छा एक बात बताओ तुमने सेकेंड वर्ल्डवार के बाद कुल जमा कितनी लड़ाई जीती है? वियतनाम, कोरिया, इराक, अफगानिस्तान अबे सारी की सारी लड़ाई तो तुमने हारी है, लेकिन हारकर भी तुम जीतते हो सोचो भला क्यों? सोचो...सोचो...महाराज। देखो हर लड़ाई हारने के बाद अमेरिका का रक्षा उद्योग आगे पीछे की सारी कसर पूरी कर लेता है। यानी तुम्हारा और दुश्मन देश का पुराना गोला बारूद मिसाइल सब खत्म फिर नया उत्पादन, और भय्या अमेरिका नया माल बेचकर अगली पिछली सारी कसर निकाल लेता है, तो फिर से सोचो अर्जुन रूपी ट्रंप...चलो ईरान रूपी दुर्योधन का नाम ओ निशान मिटा देते हैं। फिर मैं तो हूँ न एक तरफ से तुम और दूसरी तरफ से मैं, भइया मिल जुल कर ईरान का कीमा बना डालेंगे। ट्रंप ने आखिरी प्रश्न दागा ठीक है। हमला तो कर दूंगा, लेकिन कोई कारण भी तो चाहिए। नेतन्याहू शातिराना मुस्कान बिखेरते बोले 'डिल बेबी डिल' और बस ट्रंप ने कह दिया यलगार हो...यलगार हो और लो जो 28 फरवरी इतिहास में दर्ज हो गई।

मीडिल ईस्ट में दे दना दन...

बिना विचारों जो करै, सो पाछे पछिताय।

काम बिगारै आपनो, जग में होत हंसाय।।

जग में होत हंसाय, चित्त में चैन न पावै।

खान पान सन्मान, राग रंग मनहिं न भावै।।

गिरिधर कविराय की प्रसिद्ध पंक्तियां तो कभी ना कभी तो सुनी ही होंगी। अब उधर से अमेरिका ने और इधर से इजरायल ने ईरान का बारूदी बैड बजाना शुरू कर दिया। सभी को लगा हफते भर की जंग में ईरान हांफते हुए अमेरिका और इजरायल के आगे लम लेट हो जाएगा, लेकिन...लेकिन...लेकिन ईरान तो बड़ा वाला निकला, उसने जब पेलना शुरू किया तो ईरान से 2300 किलोमीटर दूर इजरायल को अपनी गलती का अहसास होने लगा कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है, लेकिन बाजी तो हाथ से निकल चुकी थी सो मरता क्या न करता उसने ईरान की नाजायज औलाद हिजबुल्ला को उधेड़ना शुरू कर दिया। यानी हिजबुल्लाह जिसने लेबनान पर कब्जा जमा रखा है। अब हिजबुल्लाह की जान तो ईरानी तोते में है सो जाहिर सी बात है ईरान सकपकाया और बौखलाया। फिर क्या था उसने मीडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर दे दना दन चालू कर दिया। ईरान ने इजरायल से ज्यादा अमेरिका की छाती पर वाल किया। इजरायल का भी पजामा गीला कर दिया। सब कुछ गंवाने के बाद लावारिस से हुए ईरान को जल्दी

- हफते भर की जंग में ईरान हांफते हुए अमेरिका और इजरायल के आगे लम लेट हो जाएगा, लेकिन...लेकिन ईरान तो बड़ा वाला निकला, उसने जब पेलना शुरू किया तो ईरान से 2300 किलोमीटर दूर इजरायल को अपनी गलती का अहसास होने लगा कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है।
- अर्जुन रूपी ट्रंप चलो ईरान रूपी दुर्योधन का नाम निशान मिटाते हैं, एक तरफ से तुम और दूसरी तरफ से मैं, भय्या मिल जुल कर ईरान का कीमा बनके हैं, ट्रंप ने आखिरी प्रश्न दागा ठीक है, हमला तो कर दूंगा, लेकिन कोई कारण तो चाहिए, नेतन्याहू शातिराना मुस्कान बिखेरते बोले 'डिल बेबी डिल,' बस ट्रंप ने कह दिया यलगार हो...यलगार हो...।

समझ आ गई कि इजरायल और अमेरिका को निपटाना इतना आसान नहीं है, लिहाजा उसने एक्सिस ऑफ रिसिस्टेंस के तहत बिना किसी चेतावनी के अमेरिका के सैन्य ठिकानों, जो बहरीन, ओमन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक व सीरिया में थे पर दीपावली का धूम धड़का शुरू कर दिया। बस यही बात अमेरिका को खल गई कि मारना है तो इजरायल को मारो मेरे अट्टे पर बमबारी क्यों?

ईरान ने जबरदस्त ठोका

युद्ध में सब कुछ जायज है ये ईरान ने अमेरिका को अच्छी तरह से समझा दिया। वैसे भी ईरानी तो बीस बरसों से अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि अमेरिका खुशफात जरूर करेगा सो उसने अमेरिका को वहां-वहां ठोका जहां-जहां अमेरिका की नस दबी हुई थी। जिस स्पीड से जंग लड़ी जा रही थी उससे ज्यादा स्पीड से ट्रंप की जबान चल रही थी वो तो रोज जीत के नए दावे कर रहे थे। जैसे ही दावा होता ईरान की नेवी खत्म, हथियार खत्म, एयरफोर्स खत्म, अगले ही पल ईरान अमेरिका को ऐसी ऐसी जगह मारता कि ट्रंप बताते भी नहीं थे। ट्रंप बोलते रहे और ईरान ठोकता रहा। अब युद्ध अमेरिका बनाम ईरान हो गया। इजरायल की बल्ले-बल्ले हो गई क्योंकि हींग लगी न फिटकरी और रंग आ गया चोखा, जय हो नेतन्याहू बाबा की। युद्ध की शुरुआत ईरानी रिजीम चेंज करने और परमाणु प्रोग्राम रोकने के लिए की थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सबकी समझ में आ गया कि ये तो सिर्फ तेल का खेल है। फिर तेल के चक्कर में अमेरिका का कुछ ज्यादा ही तेल निकलने लगा तो ट्रंप बाबा आएं-बाएं-शाएं बोलते हुए कभी युद्ध जीत गए, कभी अमेरिका ने अपना टारगेट अचीव कर लिया कभी होर्मुज से हमारा तेल नहीं आता है जिसका आता है वो देश खुलवा ले। मतलब कुछ भी यूरोप को भदी भदी गालियां और अंत में आखिरी पासा पहले ईरान होर्मुज खोले तब समझौता होगा, फिर एक तरफा सीज फायर करने ट्रंप बाबा ने अपनी बची-खुची इमेज भी खराब कर ली।

सबसे अजीब हालत तो पाकिस्तान ने पैदा की, होर्मुज...होर्मुज...खेलते ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का ठेका ले लिया। नंबर वन का आतंकवादी और विश्वासघाती भीखमंगा देश पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर बिचौलिया बन रहा था, उसे पता था कि वो बलि का बकरा बन रहा है, पर खजाना भरने लिए तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। मजबूरी है भाई खुद का खर्चा चलाने की, सो इसी बहाने अमेरिका कुछ डॉलर उसके कटोरे में डाल देगा। लेकिन होर्मुज बेचारा क्या करे? अच्छा खासे 100 जहाज रोज उसे सलाम करके निकल रहे थे लेकिन अब सलाम तो छोड़ो अब तो उसकी छाती पर कभी गोला गिर रहा है तो कभी मिसाइल। इस चक्कर में कभी इसका जहाज कभी उसका जहाज उसके पेट में समाए जा रहा है। खैर इस युद्ध के चक्कर में महाशक्ति ट्रंप बाबा की रेटिंग शेयर मार्केट की तरह नीचे गोते लगा रही है। सुना है ट्रंप पर किसी ने हमला कर दिया है। भाई यो कैसा चाचा चौधरी है जो अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहा और दूसरों की रिजीम चेंज करने की हुंकार भर रहा है। ●

# पर्यावरणीय पर्यटन की दरकार

उत्तराखंड में श्रद्धा और आस्था को पर्यटन के रूप में पेश किया जा रहा है, राज्य सरकार की नीतियां और प्रचार-प्रसार पर्यावरण अथवा आध्यात्मिकता की तुलना में राजस्व पर अधिक जोर देता है, सरकार का ध्यान पर्यावरण-पर्यटन से हटकर अहंकार-पर्यटन की तरफ चला गया है, लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ में हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

# हि



डॉ. हरीश चंद्र अंडोला  
दून यूनिवर्सिटी

मालय की गोद में बसे उत्तराखंड जिसे श्रद्धा आस्था और प्रेम से देवभूमि कहा जाता है। इसी हिमालय क्षेत्र को चार धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनात्री जैसे पवित्र तीर्थस्थल देवताओं की भूमि होने का दर्जा देते हैं। उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम को पांचवें धाम का दर्जा दिया जाता है। यहां प्राचीन मंदिर, प्राकृतिक सौंदर्य सदियों से आध्यात्मिक जीवन्तता प्रदान कर रहे हैं। यहां एक ही स्थान पर छोटे-बड़े 224 मंदिर हैं। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिवपूजन की परंपरा शुरू हुई। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपोस्थली भी माना जाता है। इसे आठवें ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। शास्त्रों के अनुसार जागेश्वर धाम को ही शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना गया है। इस धाम का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। यानी देवभूमि का बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक साधकों के लिए स्वर्ग के समान है। सदियों से तीर्थयात्री बर्फ, बारिश और थकान का सामना करते हुए, दुर्गम और कठिन रास्तों पर कई दिनों तक पैदल चलकर इन पवित्र धर्मस्थलों तक पहुंचते हैं। पहाड़ों की शांति और नदियों की पवित्रता के साथ प्रकृति के निकट होने का अनोखा अनुभव करता है। यानी यात्रियों का हर कदम उनका एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है लेकिन पर्यटन में वृद्धि, प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों ने प्रगति के साथ तीर्थयात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। आज श्रद्धा और आस्था को पर्यटन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार की नीतियां और प्रचार-प्रसार पर्यावरण अथवा आध्यात्मिकता की तुलना में राजस्व पर अधिक जोर देता है। सरकार का ध्यान पर्यावरण-पर्यटन से हटकर अहंकार-पर्यटन की तरफ चला गया है। लाखों पर्यटकों को आकर्षित करने की होड़ में हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।



## तीर्थटन में विलासिता बढ़ी

वैसे तो उत्तराखंड के किसी भी कोने में आप जाएं तो प्रकृति के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे लेकिन कुछ स्थान बहुत ही रमणीक और दर्शनीय हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। चौकोरी, पिथौरागढ़ जिले में एक ऐसा ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है जो हिमालय के तमाम ऊंचे पर्वतों से घिरा है। ये सीमांत क्षेत्र है जिसके उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल की सीमा है। यहां से हिमालय की बर्फ से आच्छादित पर्वत श्रृंखला पर सुबह को सूर्य की किरणें सुनहरा रंग बिखेरती हैं तो वो छटा देखते ही बनती है। यहां से पाताल भुवनेश्वर, कौसानी, बागेश्वर और अल्मोड़ा भी पास में ही हैं। लेकिन चार धाम यात्रा का पैमाना चौंका देने वाला है। कभी लाखों तीर्थयात्री यहां आते थे, लेकिन अब एक ही मौसम में करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं। बड़े-बड़े विज्ञापन और सरकारी अभियान उत्तराखंड को एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। संकरे रास्तों की जगह चौड़े राजमार्ग बन गए हैं, भूस्खलन की आशंका वाली घाटियों में भी होटल खुल रहे हैं और हेलीकॉप्टर प्रतिदिन हजारों लोगों को उन मंदिरों तक ले जाते हैं जहां कभी कई दिनों की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी तीर्थयात्रियों की तेजी से बढ़ती संख्या के बावजूद हिमालय की अपनी एक क्षमता है। जिसे हम बहुत पहले ही पार कर चुके हैं। जो तीर्थयात्रा धीमी, विनम्रतापूर्ण और आध्यात्मिक होनी चाहिए थी, वह अब एक जल्दबाजी वाली कार्यसूची में बदल गई है।

## भूस्खलन का बढ़ता खतरा

हिमालय दुनिया के सबसे युवा और सबसे अस्थिर पर्वतों में से एक है। चार धाम परियोजना के लिए लगातार किए जा रहे विस्फोट, सड़कों के चौड़ीकरण और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने पर्वतीय ढलानों को अस्थिर कर दिया है, परिणामस्वरूप बार-बार भूस्खलन होते हैं। हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं, मलबा ढालने से नदियां अवरुद्ध हो गई हैं। हमेशा निर्मल रहने वाली नदियां अब प्रदूषित हो रही हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियों के पवित्र स्रोत हिमनद पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन एक

भूस्खलन वाली घाटियों में होटल खुल रहे हैं, हेलीकॉप्टर रोजाना हजारों लोगों को उन मंदिरों तक ले जाते हैं जहां कई दिन पैदल चलना पड़ता था, तीर्थयात्रियों की तेजी से बढ़ती संख्या के बावजूद हिमालय की अपनी क्षमता है, जिसे हम पहले ही पार कर चुके हैं, जो तीर्थयात्रा धीमी, विनम्रतापूर्ण व आध्यात्मिक होनी चाहिए वो अब एक जल्दबाजी में हो रही है।

बड़ा कारण है, लेकिन वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और भारी संख्या में पर्यटकों के आने से उत्पन्न कार्बन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। विडंबना यह है कि गंगोत्री में गंगा की पूजा करने के लिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्री अनजाने में ही इसके मूल स्रोत को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। नदियां भी खतरे में हैं। होटलों से निकलने वाला गंदा पानी, नदी किनारों पर अनियोजित निर्माण और कंक्रीटीकरण ने उन जल स्रोतों को प्रदूषित कर दिया है जिन्हें कभी शुद्ध माना जाता था। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों के तो शव आज तक नहीं मिले हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि यह अधाधुंध निर्माण और पर्यावरणीय चेतावनियों की अनदेखी के खिलाफ एक चेतावनी थी। किंतु दुख की बात ये है कि सरकार ने 2013 की आपदा से भी कोई सबक नहीं लिया।

## खोखली होती आस्था

पर्यटन से निस्संदेह स्थानीय निवासियों की कुछ समृद्धि हुई है, लेकिन इसकी लागत बढ़ती जा रही है। मुद्रास्फीति परिवारों के बजट पर भारी पड़ रही है, पानी की कमी बढ़ती जा रही है और सड़कों व पनबिजली परियोजनाओं के लिए गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। चारागाह सिकुड़ रहे हैं, चरागाह भूमि गायब भी हो रही है। पारंपरिक जीवन की लय बिगड़ रही है। तीर्थयात्रा का सांस्कृतिक सार भी तेजी से लुप्त हो रहा है। जहां कभी श्रद्धालु स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए, परंपराओं को आत्मसात करते हुए और पर्यावरण का सम्मान करते हुए धीरे-धीरे चलते थे, वहीं आज बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर और आलीशान आवासों को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारी भीड़ उस शांत भक्ति को धूमिल कर देती है जो कभी तीर्थयात्रा का प्रतीक थी। आस्था खोखली होती जा रही है, एक जल्दबाजी भरे तमाशे में सिमटती जा रही है। उत्तराखंड को अपनी आध्यात्मिक विरासत और पारिस्थितिक स्वास्थ्य दोनों को संरक्षित रखने के लिए एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। आस्था का संबंध भीड़ से नहीं होता। हिंदू धर्मग्रंथ स्वयं हमें याद दिलाते हैं कि नदियां, वन और पर्वत पवित्र हैं। गंगा कोई पर्यटन स्थल नहीं है वह मां हैं। हिमालय कोई मस्ती करने का मैदान नहीं है वह देवताओं का दिव्य निवास स्थान है। उनकी रक्षा करना विकास विरोधी नहीं, बल्कि आस्था को व्यवहारिक बनाना है।

## सतत विकास को प्राथमिकता मिले

केंद्रीकृत पर्यटन मॉडल, वहन क्षमता सिद्धांतों की अनदेखी और भयावह अपशिष्ट उत्पादन जारी नहीं रह सकते। यथास्थिति बनाए रखना राज्य और यहां की जनता के लिए अब और बर्दाश्त करने योग्य विलासिता नहीं है। बुनियादी ढांचे पर दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण सड़कों, पाकिंग सुविधाओं, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों और सार्वजनिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। यह दबाव स्थानीय निवासियों पर भी पड़ रहा है, जिससे उनके दैनिक जीवन और समग्र कल्याण पर

2013 की केदारनाथ त्रासदी में हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों के तो शव आज तक नहीं मिले हैं, ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि यह अधाधुंध निर्माण और पर्यावरणीय चेतावनियों की अनदेखी के खिलाफ एक चेतावनी थी, किंतु दुख की बात ये है कि सरकार ने 2013 की आपदा से भी कोई सबक नहीं लिया।

असर पड़ा है। सतत विकास के लिए पर्यटकों की बढ़ती संख्या और स्थानीय निवासियों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पर्यटन नियोजन और प्रबंधन में स्थानीय निवासियों को शामिल करना सतत सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय निवासियों को सशक्त बनाना, समुदाय-आधारित पर्यटन पहलों का समर्थन करना और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वामित्व की भावना को बढ़ावा दे सकता है। उत्तराखंड का भविष्य पर्यटन के प्रति उसके दृष्टिकोण में बदलाव पर निर्भर करता है। राज्य को अल्पकालिक लाभों के बजाय सतत विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और जिम्मेदार विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को समाहित करने वाली एक समग्र रणनीति अपनानी चाहिए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसके लिए सरकारी निकायों, स्थानीय व्यवसायों और पर्यटकों के सहयोग की आवश्यकता है।

## ईश्वर की तरह प्रकृति का सम्मान करें

जब धार्मिक पर्यटन केवल भीड़ या संख्या और उपभोक्तावाद से प्रेरित होता है, तो यह धीरे-धीरे पवित्र भूमि और तीर्थस्थलों की आत्मा को नष्ट कर देता है। हिमनद पिघलते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं, पहाड़ ढहने लगते हैं और स्थानीय निवासी संघर्ष करने लगते हैं। यह सब विकास और भक्ति के नाम पर होता है। यदि यह सिलसिला जारी रहा, तो पवित्र तीर्थस्थलों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है, जिससे पवित्र भूमि आपदाग्रस्त क्षेत्र बन सकती है। आज की सबसे बड़ी जरूरत सोच में बदलाव की है। संख्या बढ़ाने वाले अहंकारी पर्यटन से हटकर ऐसे पर्यावरण-पर्यटन की ओर बढ़ना जो आस्था और नाजुक हिमालय दोनों की रक्षा करे। तीर्थयात्रा को एक पवित्र और विनम्रतापूर्ण यात्रा के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसी यात्रा जो प्रकृति का उत्तना ही सम्मान करे जितना ईश्वर का हिमालय की रक्षा करना भी पूजा करने से अलग नहीं है बल्कि यह अपने आप में पूजा है। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि उत्तराखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए देवभूमि बना रहे, तो राजस्व की जगह श्रद्धा को प्राथमिकता देनी होगी और लाभ पर संरक्षण को विजय सुनिश्चित करनी होगी। ●



# मंदिर में विष्णु के दस अवतार

कासनी गांव में मुख्य आकर्षण का केंद्र 9 वीं सदी के मध्य में बना भगवान विष्णु का भव्य मंदिर है, इस मंदिर को पिथौरागढ़ जिले का सबसे बड़ा दस अवतारी भगवान विष्णु का भव्य दरबार कहा जाता है, मुख्य मंदिर के गर्भ ग्रह में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा विराजमान है।



हरीश भट्ट रामनगर

वभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ का कासनी गांव अपनी आलौकिक संस्कृति, जैव विविधता व ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। कासनी गांव का इतिहास अपने आप में आलौकिक है। गांव के मध्य से हिमालय के नंदा कोट पर्वत की चोटी दिखाई पड़ती है। यह गांव चारों तरफ से खेतों व मंदिरों से घिरा हुआ है। इस गांव में तीन जल स्रोत भी हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में

नोले या बावड़ी कहा जाता है, साथ ही एक तरफ तुलीगाड व दूसरी तरफ इस गांव की सीमा पर रंधोला नाम की नदी बहती है। इसी नदी के तट से लगा महाकाल का प्राचीन मंदिर है जो मुंगरु देवता के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की अपनी विशेष कहानियां हैं। इसलिए स्थानीय ग्रामीणों की मुंगरु देवता में गहरी आस्था है। इसे पिथौरागढ़ जिले के एक मात्र महाकाल मंदिर की मान्यता मिली हुई है। यहीं दो नदियों के संगम पर सेरादेवल मंदिर है जहां पर देवल समेत बाबा की आराधना की जाती है। यहीं शिवरात्रि के दिन देवल समेत बाबा का डोला निकाला जाता है। डोले में बैठकर देवता अवतरित होते हैं। इसका वर्णन स्कंदपुराण में भी है। भगवान शिव का मंदिर भी इसी भूमि पर विराजमान है। कासनी के कसनियालो परिवार मुंगरु देवता, सेरादेवल और विष्णु के पुजारी हैं। इनका इतिहास अपने आप में अतुल्य है। कुछ इतिहासकारों का मनना है कि इस गांव में प्रागैतिहासिक काल से ही कसनियालो परिवार निवास कर रहे हैं। इस का साक्ष्य कप मार्क्स जिसे औखल के नाम से भी जाना जाता है, में है। ये पिथौरागढ़ के कुछ ही गांवों में पाए गए हैं। इतिहासकार डॉ राम सिंह ने अपनी पुस्तक (सोर का इतिहास) में इस गांव के प्रागैतिहासिक होने के बारे में लिखा है। क्योंकि कासनी गांव पिथौरागढ़ के सबसे पुराने गांवों में से एक है। गांव का मुख्य परिवार कसनियालो का है इसके अलावा भट्ट, कापड़ी, पांडेय, थवाल व शर्मा इनके मित्र थे जिन्हें कसनियालो परिवार अपने साथ ही यहां लेकर आए थे। नाथ, गिरी, गोस्वामी बाद में यहां बसाये गए जिनको कोस्टाक, जामढ़ व लम्पाटा तोक में स्थान दिया गया। गांव की मुख्य आजीविका का श्रोत खेती था परंतु 70 के दशक में जब यहां आर्मी आई तो यहां के लोगों ने अपनी काफ़ी भूमि सेना को दे दी। वर्तमान में गांव के लोग अपने अलग अलग व्यवसाय में हैं कोई कृषि से आज भी जुड़ा है तो कोई भारतीय सेना में देश की सेवा कर रहा है।

कुमाऊं में जिस समय कत्यूरी शासनकाल अपने चरम पर था तब उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य के आगमन के साथ ही वैष्णव परंपरा का आगमन हुआ और विष्णु मंदिर बनने लगे, कत्यूरी शासकों ने मंदिर निर्माण में विशेष रुचि ली थी, मंदिर स्थानीय ग्रैनाईट प्रस्तर खंडों का बना है।

## 9 वीं सदी के मध्य का विष्णु मंदिर

कासनी गांव में मुख्य आकर्षण का केंद्र 9 वीं सदी के मध्य में बना भगवान विष्णु का भव्य मंदिर है। इस मंदिर को जिले का सबसे बड़ा दस अवतारी भगवान विष्णु का भव्य दरबार कहा जाता है। मुख्य मंदिर के गर्भ ग्रह में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा विराजमान है। स्थानीय ग्रामीण इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर में नारायण भगवान के दस अवतारों का विशेष समूह है। जिसमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार शामिल हैं। पुरातात्विक ईकाई के अनुसार उत्तराखंड में यह अकेला विष्णु मंदिर है जिसमें एक साथ दस अवतार विराजमान हैं। मुख्य प्रतिमा विष्णु की है जिनके हाथों में शंख, कमल, गदा, चक्र है। स्थानीय परिवार अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत इस मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही करते हैं। मान्यता है कि सच्चे दिल से इस मंदिर में मांगी गई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कासनी गांव के विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना व देख-रेख के लिए कसनियालों के पूर्वजों को कत्यूरी राजवंश द्वारा काशी से लाया गया था। यह काशी के विशेष ब्राह्मणों में से थे। हालांकि मंदिर में प्रत्येक दिन और विशेष अवसरों पर पूजा-पाठ होता ही है लेकिन अश्विन महीने की पंचमी के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। गांव वाले अपनी नई फसल को सबसे पहले मंदिर में चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने प्रयोग में लाते हैं। दिवाली के दिन भी ग्रामीणों द्वारा सबसे पहले इसी लक्ष्मी-नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं।

## कत्यूरीकाल में बने विष्णु मंदिर

कुमाऊं में जिस समय कत्यूरी शासनकाल अपने चरम पर था तब उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य के आगमन के साथ ही वैष्णव परंपरा का आगमन हुआ और विष्णु मंदिर बनने लगे। कत्यूरी शासकों ने मंदिर निर्माण में विशेष रुचि ली थी। मंदिर स्थानीय ग्रैनाईट प्रस्तर खंडों का बना है। यहां नागर शैली में स्तंभ हितरेखा प्रसाद श्रेणी के देवालयों की तलखंड योजना में दो भागों का विधान किया गया है। गर्भग्रह, अंतराल योजना में वेदीबंध त्रैश्रय विन्यास की जंघा निर्मित है। जिससे मंदिर शिखर का क्रम बनाया गया है, वैदिक आश्रमों की पुष्टभूमि एवं पावन यात्रा पथ के समीप निर्मित इन देवालय परिसरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला देवकुल दूसरा आश्रम व तीसरा पंचायतन। देवकुल परिसर में मुख्य देव मंदिर के समीप ही संपूर्ण देव परिवार अथवा अन्य देवों के लिए लघु देवालय परिसर में निर्मित है। मंदिर के गर्भग्रह में विशाल विष्णु की प्रतिमा, गुप्तकाल में भगवत धर्म में अवतारवाद का वृहत प्रचलन हुआ। वैष्णव साहित्य में पूर्णवतार, अंशावतार एवं आवेशावतार का उल्लेख है मुख्यतः दस अवतार इस देवालय में विष्णु के दस अवतारों की प्रतिमाओं की श्रंखला है व इसके अलावा दुर्गा, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी की प्रतिमा हैं। इसी गांव के मध्य में महिषासुर मर्दिनि का मंदिर भी है, यह मंदिर नेपाल में त्रिपुरा सुंदरी भगवती का मंदिर के समान मान्यता रखता है, क्योंकि महिषासुर मर्दिनि को ही यहां स्थापित किया गया था। कुमाऊं में कई और जगह भी महिषासुर मर्दिनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर में अन्य प्रतिमाएं भी हैं जिसमें उमा महेश की मूर्ति मंदिर की शोभा बढ़ाती है। भवानी देवी का मंदिर भी गांव के ऊंचे स्थान पर है जो अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है। इस स्थान में से घाटी का दृश्य मंदिर में चार चांद लगाता है। पुरात्व विभाग की प्रस्तावित धरोहर में होने के बावजूद स्थानीय ग्रामीण आपस में धन एकत्र कर मंदिर का रख-रखाव करते हैं। इस प्राचीन मंदिर को अंतरराष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र कसनियाल व बीडी कसनियाल के नेतृत्व में मंदिर के रख-रखाव के लिए व कासनी गांव को विशेष पर्यटन स्थल के रूप में आम जन-मानस तक पहुंचाने के लिए शासन व प्रशासन से मांग की है।

## कासनी गांव का पर्वतारोही

कासनी गांव के मनीष कसनियाल पिथौरागढ़ जनपद के युवा पर्वतारोही हैं जिन्होंने 2021 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8848.86 मीटर चोटी को फतह कर पिथौरागढ़ जिले का गौरव बढ़ाया है। मनीष के द्वारा भारतीय पर्वतारोहण दल का नेतृत्व किया गया भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले वह अब तक देश में

- कासनी गांव का इतिहास अपने आप में आलौकिक है, गांव के मध्य से हिमालय के नंदा कोट पर्वत की चोटी दिखाई पड़ती है, यह गांव चारों तरफ से खेतों व मंदिरों से घिरा हुआ है, इस गांव में तीन जल स्रोत हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में नोले या बावड़ी कहा जाता है।
- पुरातात्विक ईकाई के अनुसार उत्तराखंड में यह अकेला विष्णु मंदिर है जिसमें एक साथ दस अवतार विराजमान हैं, मुख्य प्रतिमा विष्णु की है जिनके हाथों में शंख, कमल, गदा, चक्र है, स्थानीय परिवार अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत इस मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ही करते हैं।

सबसे छोटे पर्वतारोही हैं। अब तक मनीष कसनियाल द्वारा 11 विश्व रिकॉर्ड साहसिक खेलों में अपने नाम दर्ज कराए हैं साथ ही 2013 की आपदा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2017 में राज्य स्वच्छता पुरस्कार, 2020 में समाजिक कार्य के लिए पुनः राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया इसके बाद 2023 में पिथौरागढ़ में विश्व की प्रथम रिले मैराथन का आयोजन कर उसको सफल करने में पुनः राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही दर्जनों रिकॉर्ड इनके नाम हैं। उत्तराखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इनका नाम आता रहा है।

## कासनी के आसपास जन्त

पिथौरागढ़ के कासनी गांव के आसपास कई और शानदार दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं। यहां के प्रमुख आकर्षणों में सुरम्य घाटियां, प्राचीन मंदिर और नदियां शामिल हैं। उत्तराखंड शासन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पिथौरागढ़ जिले के सभी पर्यटक स्थलों की संपूर्ण जानकारी ली जा सकता है। कासनी गांव के पास मोस्टामानु मंदिर है। यह मंदिर स्थानीय देवता को समर्पित पूजनीय है। जो कासनी गांव के पास ही है। यहां से पूरी सौर घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर कासनी गांव के करीब चूना पत्थर की रहस्यमयी गुफा में है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तीर्थाटन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह बेहतरीन स्थान है। कासनी गांव के करीब ही लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर चंडाक हिल्स है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यहां से हिमालय के नजारे देखे जा सकते हैं और एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह पैराग्लाइडिंग का एक प्रमुख केंद्र है। कासनी गांव घूमने वालों को पिथौरागढ़ किला भी देखना चाहिए। इसे स्थानीय लोग लंदन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। शहर के मध्य में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित यह ऐतिहासिक किला गोरखों और ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। यहां से घाटी का नजारा बहुत लुभावना लगता है। कासनी और गंगोलीहाट के पास पाताल भुवनेश्वर गुफा है। यह भूमिगत गुफा बेहद चमत्कारी और रहस्यमयी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है। गंगोलीहाट में हाट कालिका मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शक्तिपीठ है। इसे आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, जो जवानों और स्थानीय निवासियों का रक्षक भी माना जाता है। यदि थोड़ा समय निकालकर दूर जाना चाहते हैं, तो पंचाचूली चोटियों के नजारों और ट्रेकिंग (जैसे खलिया टॉप) के लिए मुनस्यारी जरूर जाएं। मुनस्यारी पिथौरागढ़ का विश्वप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां सेलानी देश विदेश से नैसर्गिक सौंदर्य को देखने पहुंचते हैं। गर्मियों के मौसम में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगती है। मुनस्यारी हिमालय की गोद में बसा है और यहां से पंचाचूली पर्वत का विहंगम नजारा हमेशा देखा जा सकता है। मुनस्यारी में ही ट्रेकिंग के लिए मशहूर खलिया टॉप है, जहां से विभिन्न हिमालय श्रंखला देखी जा सकती हैं। इसके अलावा मुनस्यारी में ही मिलम ग्लेशियर मौजूद है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए उपयुक्त स्थान है। मुनस्यारी पहुंचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन कागोदाम हल्द्वानी में पड़ता है। इसके बाद आप टैक्सी की मदद से मुनस्यारी आसानी से पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी से इसकी दूरी 280 किलोमीटर है।

# आप ही है सीजेपी

सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को भले ही विदेशी फॉलोअर मिल गए हैं, भले ही विपक्षी दल सीजेपी का समर्थन कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाले कैम्पेयन से सत्ता हासिल नहीं होती, वैसे भी जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए हैं वो लगातार कुछ न कुछ खुराफात करते ही रहते हैं।



डा.भारत भूषण  
आईएफटीएम

# भा

राजनीति में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोशल मीडिया पर कमाल कर दिया है। आम आदमी पार्टी के समर्थक और भाजपा विरोधी अभिजीत दीपके की सीजेपी ने चार-पांच दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी भाजपा को इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ दिया है। हालांकि सीजेपी के फॉलोअर्स में भारत विरोधी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा है। कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद सिर्फ केजरीवाल की तरह भारत के जेन-जी को भड़काना है। इसका प्रमाण ये है कि नीट पेपर लीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक ने सोशल मीडिया पर जेन-जी का सड़क पर उतरने का आह्वान किया था। लेकिन एक भी जेन-जी केजरीवाल के झांसे में नहीं आया। क्योंकि देश का जेन-जी केजरीवाल के भ्रष्टाचार से परिचित है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने जेन-जी को भड़काने के लिए अपने गुणों को काम पर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की 'कॉकरोच' वाली टिप्पणी के बाद अमेरिका में बैठे आम आदमी पार्टी से जुड़े अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम के पेज बनाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सीजेपी से जुड़ने की अपील की। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट भी बनाई गई है, जिस पर थोड़े से ही वक्त में एक लाख लोग जुड़ गए थे। वेबसाइट पर पार्टी ने अपना एक ऐंथम भी डाला है। मोदी सरकार को टारगेट करने वाले वीडियो अपलोड किए। कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर इसे 'आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज' बताया गया है।

## मनीष सिसोदिया के अभिजीत संबंध

भारत में मोदी विरोधी नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के नाम बदल कर कॉकरोच जनता पार्टी रख लिया। आम आदमी पार्टी के ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वीडियो बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। आप के पूर्व नेता



व सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद सहित कुछ चर्चित राजनीतिक चेहरों ने कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा और सीजेपी में मुकाबले का दावा कर दिया। पूर्व आप नेता व प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने वालों की खिंचाई करते हुए कहा कि मोदी विरोधी गैंग की दिमागी हालात इतनी खराब हो गई है कि खुद कीड़े मकोड़े (कॉकरोच) बन गए। इन मानसिक रोगियों को कौन समझाए कि जो मोदी दुनियाभर में लोकप्रिय हैं उस मोदी को केजरीवाल जैसे कॉकरोच और उनके कीड़े मकोड़े क्या हरा पाएंगे? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके का आम आदमी पार्टी से रिश्ता सामने आया तो सारा नैरेटिव धड़ाम हो गया। अभिजीत दीपके की आप के नेताओं के साथ बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। इनमें एक तस्वीर में वह दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अभिजीत दीपके ने लिखा, 'धन्यवाद मनीष सिसोदिया सर। आपके साथ काम करने के दौरान आपने मुझे जो भी अवसर दिए उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ।' अभिजीत ने आगे लिखा कि 'वह बोस्टन (अमेरिका) के लिए रवाना हो रहा है और इसमें मनीष सिसोदिया का आशीर्वाद उन्हें मिला है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के लिए उनके समर्पण को कोई भी दूरी कम नहीं कर सकती है।' इस पोस्ट ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया।

## 'आप' का नया अवतार है सीजेपी

अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैं। उन्होंने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़ गए। दीपके ने केजरीवाल की पार्टी के लिए डिजिटल कैम्पेयन, मीम नैरेटिव और ऑनलाइन

पूर्व आप नेता व कवि कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने वालों की खिंचाई करते हुए कहा कि मोदी विरोधी गैंग की दिमागी हालात इतनी खराब हो गई है कि खुद कीड़े मकोड़े (कॉकरोच) बन गए, इन मानसिक रोगियों को कौन समझाए कि जो मोदी दुनियाभर में लोकप्रिय हैं उस मोदी को केजरीवाल जैसे कॉकरोच क्या हरा पाएंगे?



राजनीतिक प्रचार के लिए काम किया। फिलहाल वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य सूत्रधार अभिजीत दीपके पेशे से एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वह सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक माहौल को समझते हैं और उसके हिसाब से नैरेटिव तैयार करते हैं। उन्होंने अब तक कई जगहों पर काम किया है और उनकी पुरानी पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वह आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिका में बैठकर अभिजीत दीपके ने फिर आम आदमी पार्टी के लिए काम शुरू कर दिया है इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके, भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर हैं। भाजपा समर्थकों ने अभिजीत को देश के खिलाफ साजिश करने और युवाओं को भ्रमित करने वाला बताया है। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर किया है उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी भी कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश कर रही है। जिस तरह की खबरें और फोटो आ रहे हैं उससे लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का नया अवतार है? क्या ये केजरीवाल एंड कंपनी की नई सोशल मीडिया टीम है। क्या आम आदमी पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य में विलय हो जाएगा? इन सवालों का जवाब खुद अभिजीत ने दिया है। उन्होंने आज तक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 2020 से 2023 के बीच थोड़े समय के लिए आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था। वह उनके स्वास्थ्य मॉडल से प्रभावित थे। अभिजीत ने कहा कि इसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया और अपनी हायर एजुकेशन के लिए काम शुरू कर दिया। उन्होंने कई विदेशी कॉलेजों में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। उन्हें बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। इसके बाद से वह अमेरिका में ही हैं। एक सवाल के जवाब में अभिजीत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को वह कभी भूल नहीं पाएंगे।

## केजरीवाल का न्यायपालिका से टकराव

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दुनिया में सोशल मीडिया की ताकत क्या है, इसका सबसे ताजा नमूना 'कॉकरोच जनता पार्टी' को बताया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई, 2026 देश के कुछ चुनिंदा बेरोजगार युवाओं की हरकतों पर कॉकरोच और परजीवी वाली टिप्पणी की थी, जो खुद की मेहनत पर प्रोफेशनल जगत में अपनी जगह नहीं बना सकते। सीजेआई ने कॉकरोच वाली टिप्पणी

भाजपा समर्थकों ने अभिजीत को देश के खिलाफ साजिश करने और युवाओं को भ्रमित करने वाला बताया है तो कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर किया है उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी भी कांग्रेस को कमजोर करने की एक कोशिश कर रही है।

क्या की, आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे अभिजीत ने कॉकरोच को सोशल मीडिया पर हथियार बना लिया। इसलिए केजरीवाल से ऐसी ही टिप्पणी की उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि वो आजकल न्यायपालिका से भी टकरा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें निचली अदालत ने बरी किया तो आम आदमी पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताया, लेकिन जैसे ही निचली अदालत के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से टकरा गए। उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने लगे। अंत केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट का ही बहिष्कार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को केजरीवाल के शराब घोटाले वाले केस से अलग कर लिया और उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा भी कर दिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच शराब घोटाले की सुनवाई कर रही है, लेकिन पहली ही तारीख पर केजरीवाल कोर्ट नहीं पहुंचे। केजरीवाल दिखाना चाहते हैं कि वो न्यायपालिका से भी ऊपर हैं और जब तक उनकी पसंद का कोई जज उनका मुकदमा नहीं सुनेगा वो कोर्ट का बहिष्कार करते रहेंगे। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जनता के वोट से आम आदमी से नेता बने केजरीवाल को कोर्ट अपनी संवैधानिक शक्तियों का अहसास कराएगा? क्योंकि अब माना जा रहा है कि बड़े लोगों के लिए कानून की किताब अलग है और आम आदमी को खास बनाने वाली जनता व गरीब के लिए कानून की किताब अलग है। आम आदमी को न्याय पाने के लिए जूते धिसने पड़ते हैं जबकि खास लोग कोर्ट का ही बहिष्कार कर देते हैं पर न्यायधीश कुछ नहीं कर पाते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच जैसी टिप्पणी की तो केजरीवाल ने अपने गुणों से कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर भारत की न्याय व्यवस्था से लेकर पूरे सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी है। अभिजीत दीपके ने सीजेआई की टिप्पणी को खारिज तो नहीं किया पर एक व्यंग्यात्मक ग्रुप में बदलने की कोशिश अवश्य की है।

## कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो

सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। एक भी असली वोटर का नाम कटा तो चुनाव आयोग पर कार्रवाई होगी और यूएपीए के तहत गिरफ्तारी भी की जाएगी, क्योंकि मताधिकार छीनना आतंकवाद की कार्रवाई है। महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। प्रभावशाली बिजनेसमैन से जुड़े मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द होंगे। एमएलए या एमपी के पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर अयोग्य ठहराया जाएगा और चुनाव लड़ने व सार्वजनिक पद हासिल करने पर 20 साल के लिए रोक लगेगी। वेबसाइट पर कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने के मानदंड भी बताए गए हैं। पार्टी में वही शामिल हो सकता है जो जबरन, पसंद से या सैद्धांतिक तौर पर निश्चित रूप से बेरोजगार हो। शारीरिक तौर पर शिथिल, लेकिन मन अस्थिर हो। हमेशा ऑनलाइन रहे, कम से कम 11 घंटे, यहां तक कि बाथरूम में भी। पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने में माहिर हो, बशर्ते वह तीखी और खरी हो और ऐसे मुद्दे उठाए जो सचमुच में मायने रखते हों। खैर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को भले ही विदेशी फॉलोअर मिल गए हैं, भले ही विपक्षी दल कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाले कैम्पेयन से सत्ता हासिल नहीं होती। वैसे भी जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए हैं वो लगातार कुछ न कुछ खुराफात करते ही रहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को समझना अभी केजरीवाल के लिए मुश्किल है। क्योंकि जिस दिल्ली ने केजरीवाल को आसमान पर चढ़ाया था उसी जनता ने आसमान से धक्का दे दिया जिससे किसी की भी रीढ़ टूटना स्वभाविक है। केजरीवाल की पार्टी के सात सांसदों का भाजपा में शामिल होना रीढ़ टूटने से कम नहीं है। ●

# फूलों का संसार



1980 में भारत सरकार ने फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान बनाया था, बाद में 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, यह खूबसूरत घाटी लगभग 8-10 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसकी तुलना किसी और से करना बहुत मुश्किल कहा जा सकता है, इस खूबसूरत घाटी में 500 प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं।

# हु



राकेश मंडोला  
देहरादून

नियामें फूल शायद सुंदरता के सबसे पुराने प्रतीक हैं। सभ्यता के किसी बहुत प्राचीन आंगन में जंगल और झाड़ियों के बीच उगे हुए फूल ही होंगे जो इंसान को खासे मुश्किल वक्त में राहत देते होंगे। इन फूलों से पहली बार उसने रंग पहचाने होंगे। खुशबू को जाना होगा। पहली बार सौंदर्य का अहसास किया होगा। फूलों की अपनी दुनिया है। वो याद दिलाते हैं कि पर्यावरण के असंतुलन से लगातार धुंधली, काली पड़ती, गरम होती इस दुनिया में फूलों को बचाए रखना जरूरी है। उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय ट्रेक में से एक फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर है। जो भारत के सबसे लोकप्रिय व सबसे पुराने ट्रेक में से एक है। जो लोग कभी हिमालय की तरफ नहीं गए उन लोगों ने भी इस ट्रेक का नाम जरूर सुना होगा। वैली ऑफ फ्लावर ट्रेक धरती पर स्वर्ग का अहसास कराता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में सबसे अधिक खोजे जाने वाले स्थानों में से ये एक है। यह प्राकृतिक सुंदरता, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, पुष्पावती नदी, फोटोग्राफी, अल्पाइन के फूलों आदि के लिए प्रसिद्ध है। 1980 में भारत सरकार ने फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान बनाया था। बाद में 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। यह खूबसूरत घाटी लगभग 8-10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी तुलना किसी और से करना बहुत मुश्किल कहा जा सकता है। इस खूबसूरत घाटी में आपको 500 प्रकार के फूल व हर तरफ खूबसूरत चोटियों के नजारे दिखाई देंगे, जो कुछ बर्फ से ढके हुए होते हैं, तो कुछ हरी घास के मैदान भी शामिल हैं। बीच में बहती एक खूबसूरत नदी, पुष्पावती नदी,

जिसका नजारा ज्यादातर ट्रेकर्स मिस कर देते हैं। पुष्पावती नदी इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगाती है। विश्व धरोहर स्थल, नंदा देवी अभयारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। हिमालय क्षेत्र पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी (नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान) का जन्म पिंडर से हुआ है जिसे पिंडर घाटी भी कहते हैं। पिंडर घाटी यानी पिंडर का अर्थ हिम और घाटी का अर्थ पहाड़ों का क्षेत्र जहां महादेव भगवान शिव का निवास होता है, जो मुख्य रूप से चमोली जिले के पिंडर घाटी के ही क्षेत्र में स्थित है। पिंडर घाटी देवी देवताओं का निवास स्थान है आज भी पिंडर घाटी में भगवान शिव के गण और देवताओं के वंशज निवास करते हैं व हर वर्ष माता पार्वती नंदा देवी को हिमालय तक भगवान शिव की तपोस्थली तक पहुंचाते हैं जिसे वर्तमान में नंदा देवी राजजात यात्रा या भगवती भेंट से भी जाना जाता है।

## ब्रिटिश के फ्रैंक एस स्मिथ ने की खोज

इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी आरएल होल्डसवर्थ ने लगाया था, जो संयोग से 1931 में अपने कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे और रास्ता भटकने के बाद 16700 फीट ऊंचे दर्रे को पार कर भ्यूंडर घाटी में पहुंचे। उन्होंने यहां मौजूद फूलों की इस घाटी को देखा। यहां मौजूद असंख्य प्रजातियों के फूलों की सुंदरता को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। फूलों की इस घाटी का आकर्षण फ्रैंक स्मिथ को दोबारा 1937 में यहां खींच लाया और उन्होंने यहां के फूलों पर गहन अध्ययन व शोध किया। 300 से अधिक फूलों की प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्रित की, जिसके बाद फ्रैंक स्मिथ की 1938 में फूलों की घाटी में मौजूद फूलों पर 'वैली ऑफ फ्लावर्स' नाम की एक किताब प्रकाशित हुई। इसके बाद दुनिया ने पहली बार फूलों की इस घाटी के बारे में जाना था। उसके बाद से आज तक इस घाटी के फूलों का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर खींचता है। फ्रैंक स्मिथ इस फूलों की घाटी से कई किस्म के फूलों के बीज अपने देश भी ले गए थे। 1938 में विश्व के मानचित्र पर फूलों की घाटी के छ जाने के बाद

**फूलों की घाटी में आम तौर पर पाए जाने वाले फूलों के पौधों में हिमालयी नीला पोस्त, बछनाग, डेलफिनियम, रानुनकुलस, इन्डुला, कम्पानुला, मोरिना, इम्पेटिनस, लोबिलिया, एक्युलेगिया, एनीमोन, जर्मनियम, मार्श, गेंदा, प्रिभुला, तारक, लिलियम, सैक्सिफागा व स्ट्राबेरी इत्यादि प्रमुख हैं।**

1939 में क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन की और से जॉन मागरिट लैगी, जिनका जन्म 21 फरवरी 1885 में हुआ था, 54 वर्ष की उम्र में इस घाटी में मौजूद 500 से अधिक प्रजाति के फूलों का अध्ययन करने के लिए आई थीं। इसी दौरान अध्ययन करते समय दुर्भाग्यवश फूलों को चुनते हुए 4 जुलाई 1939 को एक खड़ी पहाड़ी से गिरने से उनकी मौत हो गई और फूलों की इस घाटी में वह सदा सदा के लिए चिरनिंद्रा में सो गई। जोन माग्रेट लैगी की याद में यहां पर एक स्मारक बनाया गया है जो बरबस ही घाटी में घुमने पर लैगी की याद दिलाती है। जो भी पर्यटक यहां घूमने आता है वह लैगी के स्मारक पर फूलों के श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धाजलि देना नहीं भूलता है।

## कई विषैले फूल भी हैं इस घाटी में

हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ और फूलों की विभिन्न प्रजातियों से सजा यह क्षेत्र बागवानी विशेषज्ञों व फूल प्रेमियों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन गया। फूलों की घाटी ग्रीष्मकाल में छह माह तक पर्यटकों के लिए खोली जाती है। घाटी के दीदार के लिए जुलाई, अगस्त व सितंबर सबसे उपयुक्त महीने माने जाते हैं। इस दौरान घाटी में सबसे ज्यादा फूल खिलते हैं। सितंबर में यहां ब्रह्मकमल खिलते हैं। फूलों की घाटी जैव विविधता से भरी है। यहां कई प्रजाति के फूल और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कई दुर्लभ प्रजाति के फूल भी हैं। इनमें सबसे मनमोहक फूल मोरिना लॉगिफोलिया है। यह दूर-दूर तक अपनी महक छोड़ता है। इसके अलावा घाटी में विलुप्त प्राय श्रेणी में रखे गए कोरीडालिस कॉर्नुटा फूल भी खिलते हैं। इस फूलों की घाटी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। घाटी में उगने वाले फूलों से दवाई भी बनाई जाती है। नवंबर से मई के बीच घाटी सामान्यतः हिमाच्छादित रहती है। जुलाई एवं अगस्त के दौरान अल्पाइन जड़ी की छाल की पंखुडियों में रंग छिपे रहते हैं। यहां आम तौर पर पाए जाने वाले फूलों के पौधों में हिमालयी नीला पोस्त, बछनाग, डेलफिनियम, रानुनकुलस, इन्डुला, कम्पानुला, मोरिना, इम्पेटिनस, लोबिलिया, एक्युलेगिया, एनीमोन, जर्मनियम, मार्श, गेंदा, प्रिभुला, तारक, लिलियम, सैक्सिफागा व स्ट्राबेरी इत्यादि प्रमुख हैं। फूलों की घाटी से हेमकुंड साहिब तक जगह-जगह ब्रह्मकमल खिलते हैं। कोरोना संक्रमण काल में मानवीय आवाजाही कम होने से यहां ब्रह्मकमल बहुत बड़ी संख्या में खिले थे, जो अपने आप में रिकार्ड है। इस खूबसूरत वादियों के बीच कई जहरीले फूल भी खिलते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। वन विभाग पर्यटकों को बिना पुख्ता जानकारी के किसी भी फूल या वनस्पति से छेड़छाड़ करने से मना करता है। वन विभाग ने घाटी में दो ऐसे फूलों, एकोनिटम बालफोरी और सेनेसियो ग्रेसिलिफ्लोरस को चिह्नित किया है, जो विषैले हैं। लिहाजा पर्यटकों को घाटी में प्रवेश करने पर सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी

- 1939 में क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन की और से जॉन मागरिट लैगी 54 वर्ष की उम्र में इस घाटी में मौजूद 500 से अधिक प्रजाति के फूलों का अध्ययन करने के लिए आई थीं, अध्ययन करते समय दुर्भाग्यवश फूलों को चुनते हुए 4 जुलाई 1939 को एक खड़ी पहाड़ी से गिरने से उनकी मौत हो गई और फूलों की इस घाटी में वह सदा के लिए चिरनिंद्रा में सो गई।
- ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की उन्होंने यहां के फूलों पर गहन अध्ययन व शोध किया, 300 से अधिक फूलों की प्रजातियों के बारे में जानकारी की, जिसके बाद फ्रैंक स्मिथ की 1938 में फूलों की घाटी में मौजूद फूलों पर 'वैली ऑफ फ्लावर्स' नाम की किताब प्रकाशित हुई इसके बाद दुनिया ने पहली बार फूलों की इस घाटी के बारे में जाना था।

वनस्पति को छूने या तोड़ने से बचना चाहिए। सेनेसियो एक दुर्लभ प्रजाति का फूल भी है, जो लंबे समय बाद घाटी में खिलता है। किसी ने यदि यह फूल तोड़ लिया या इसको मुंह में रख लिया तो यह जानलेवा हो सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार फूलों की घाटी में परियां निवास करती हैं। परियों का निवास स्थान होने की वजह से लंबे समय तक यहां लोग जाने से कतराते थे। वन विभाग ने भी शाम को फूलों की घाटी में जाने पर पाबंदी लगा रखी है।

## 'फूलों की घाटी' दिलचस्प इतिहास

उत्तराखंड के चमोली में स्थित फूलों की घाटी अपनी मनमोहक सुंदरता और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। इस घाटी को देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए इस क्षेत्र का हिंदू धर्म में खास महत्व है। फूलों की घाटी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक नंदनकानन से संबंधित है। इस घाटी का निर्माण तब हुआ जब देवताओं ने आशीर्वाद के रूप में पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की। हिंदू पौराणिक कथाओं में नंदन को एक दिव्य उद्यान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका संबंध भगवान इंद्र से होता है। पृथ्वी की सुंदरता से प्रेरित होकर, देवताओं ने घाटी को रंग-बिरंगे फूलों से भर दिया था, जिससे यह धरती पर स्वर्ग बन गई। यहां भोटिया जनजाति निवास करती है। उत्तराखंड के चमोली जोशीमठ में स्थित फूलों की घाटी जमीन पर जन्म की तरह है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं। यहां आने के लिए पर्यटकों को गोविंद घाट से 16 किलोमीटर लंबे ट्रेक को पैदल पार करना होता है। क्योंकि गोविंद घाट से आगे गाड़ी नहीं जाती। जहां एक ओर इस घाटी में पाए जाने वाली फूलों की प्रजातियां सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, वहीं इसकी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। फूलों की घाटी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इसी घाटी से भगवान हनुमान जी, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। यहां के स्थानीय निवासी इस घाटी को परियों और देवताओं का निवास मानते हैं। इस फूलों की घाटी तक जाने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। अगर आप ट्रेन से इस घाटी तक जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। यहां से गोविंद घाट तक गाड़ी से और उसके बाद 16 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप फूलों की घाटी तक पहुंच जाएंगे। इसके पास ही स्थित अन्य आकर्षणों में हेमकुंड साहिब भी शामिल है, जो सिखों का एक तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने 10 सालों तक यहां ध्यान किया था। इसके बाद जोशीमठ का पवित्र शहर है। जहां बद्रीनाथ मंदिर से भगवान बद्री को सर्दियों के लिए लाया जाता है। फूलों की इस घाटी को 2022 में फिर से खोला गया था। तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जून 2022 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पर फूलों की घाटी की खूबसूरत तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, दुर्लभ वनस्पतियों से समृद्ध उत्तराखंड के चमोली में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने लिखा था कि उत्तराखंड सरकार आप सभी पर्यटकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। ●



# हरफनमोला परेश रावल

परेश रावल ने मिस इंडिया स्वरूप संपत से शादी की है, स्वरूप संपत ने 1979 में मिस इंडिया का खिताब जीता था और मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, दोनों की पहली मुलाकात 1975 में हुई थी, पहली ही नजर में परेश को स्वरूप संपत से प्यार हो गया और उन्होंने सीधा जाकर स्वरूप से कह दिया था कि वो उनसे शादी करने वाले हैं।

# बाँ



अरुण सिंह  
मुंबई ब्यूरो

लीवुड के जाने-माने सफल और हरफनमोला अभिनेता, एक कामयाब राजनेता परेश रावल जैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में लोगों को कम ही पता है। परेश बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जिन्हें फैंस ने हरेक किरदार में बढ़ चढ़ कर प्यार दिया है। परेश ने अपने करियर में कॉमेडी, नेगेटिव और पॉजिटिव हर प्रकार के किरदार निभाए हैं। सभी किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया है। परेश रावल को उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग के लिए जाना जाता है। वो जो भी रोल करते हैं वो कुछ खास होता है। ऐसे नेता और अभिनेता के फिल्मी सफर, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें अवश्य जाननी चाहिए। परेश रावल का जन्म मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ। 30 मई 1950 को जन्मे परेश रावल गुजराती ब्राह्मण हैं। परेश के पिता का नाम दहालाल रावल और माता का नाम धनलक्ष्मी है। जब परेश बहुत छोटे थे तब उनके पिता दहालाल रावल मुंबई शिफ्ट हो गए थे। परेश ने अपनी पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की। उन्होंने नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से सिविल इंजीनियरिंग की है। किंतु परेश ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत छोटे-मोटे किरदारों से की थी। जब परेश रावल कॉलेज में थे तभी उनकी दिलचस्पी थिएटर में बढ़ने लगी और धीरे-धीरे

उन्हें बॉलीवुड में पहले छोटे और फिर बड़े अहम रोल मिलने लगे। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत को लेकर परेश रावल का कहना है, 'जिस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया उस वक्त एक बाहरी होने के कारण और फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर न होने के बावजूद मुझे कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। इसका कारण उस दौर में कम कॉम्पिटिशन और काम के प्रति मेरी लगन थी।' अपने शुरुआती दौर में परेश ने कुछ टीवी सीरियल में काम किया था। 1984 में परेश दूरदर्शन के धारावाहिक 'चुनौती' में नजर आए थे। फिल्मों में भी परेश ने इसी साल इंटी की थी। बतौर एक्टर परेश रावल की पहली फिल्म 'होली' थी जिसका निर्देश केतन मेहता ने किया था। अधिकतर लोगों को लगता है कि आमिर खान ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से की थी लेकिन ये तथ्य सही नहीं है। आमिर ने 1984 में अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'होली' से की थी इसी फिल्म से परेश रावल ने भी बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि इस फिल्म में परेश रावल एक छोटी सी भूमिका में थे लेकिन बतौर एक्टर फिल्म में उनके काम को सराहा गया था।

## परेश की मिस इंडिया पत्नी

परेश रावल अपनी निजी जिंदगी के बारे में कम ही बात करते हैं। साथ ही उनका परिवार भी मीडिया से दूरी बनाकर रखता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि परेश रावल ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकने के बाद स्वरूप संपत से शादी की है। परेश रावल की शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। स्वरूप संपत ने 1979 में मिस इंडिया का खिताब जीता था और इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और उस समय स्वरूप संपत मिस इंडिया नहीं थी। 1975 में दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। परेश रावल को पहली ही नजर में स्वरूप संपत से प्यार

परेश रावल ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, 2014 में भाजपा ज्वाइन की और उसी साल उन्हें अहमदाबाद पूर्व लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला, चुनाव जीतकर वो लोकसभा सांसद बने, लेकिन इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने यह कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वह राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं।

हो गया था और उन्होंने सीधा जाकर स्वरूप संपत से कह दिया था कि वो उनसे शादी करने वाले हैं। इस बारे में स्वरूप संपत कहती हैं... 'मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मैं पेंपलेटस बांट रही थी, तभी परेश अपने दोस्तों के साथ मेरे पास आया और कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। इसके बाद करीब एक साल तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। कुछ समय बाद परेश को कालेज के एक प्ले में देखा और मैं उनकी अदाकारी की फैन हो गई। वो कमाल का प्ले था और परेश ने अपना किरदार उम्दा तरीके से निभाया था।' स्वरूप संपत बताती हैं कि वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना चाहती थीं, लेकिन उनका परिवार और परेश चाहता था इसलिए उन्होंने इसमें भाग लिया और बाद में जीता भी। उन्होंने बताया कि जब वो मिस इंडिया बनी थी तो परेश उन्हें लेकर थोड़ा परेशान था। उन्हें लग रहा था कि अब चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सब ठीक रहा और बाद में दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में शादी रचाई।

## परेश व स्वरूप की अनोखी शादी

आम तौर पर फिल्मी सितारों की शादी महंगी और सादगी वाली होती है। कुछ चुनिंदा मेहमान ही शादी में शामिल होते हैं। ऐसे ही परेश रावल और स्वरूप संपत की शादी भी अनोखी रही। यानी बिना मंडप के पेड़ों की छांव में उनकी शादी हुई। बॉलीवुड शादी की एक रिपोर्ट के मुताबिक परेश और स्वरूप की शादी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पेड़ों की छांव के बीच हुई थी। इस शादी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और ये बहुत ही इंटिमेट वेडिंग थी। कई पंडित श्लोक पढ़ रहे थे और स्वरूप और परेश एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने अपनी शादी को एन्जॉय किया, दोनों का ये मानना था कि उनकी शादी और रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। परेश रावल और स्वरूप संपत के दो बच्चे हैं। इनके बच्चों का नाम आदित्य और अनिरुद्ध हैं। दोनों अपने माता-पिता की तरह ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अनिरुद्ध रावल जहां पढ़ें के पीछे बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर सलमान खान की फिल्म सुल्तान में काम कर चुके हैं वहीं आदित्य ना सिर्फ न्यूयॉर्क से स्क्रीनप्ले की पढ़ाई कर चुके हैं बल्कि वो अवॉर्ड भी जीत चुके हैं। आदित्य ने बतौर एक्टर भी अपनी पारी शुरू कर दी है और वो अनुराग कश्यप की फिल्म बमफाड़ में दिख चुके हैं।

## शानदार फिल्मी करियर

परेश रावल का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा है। उन्हें नेशनल अवॉर्ड से लेकर पद्मश्री तक से नवाजा जा चुका है। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही परेश रावल को 1993 में फिल्म 'सर' और 'वो छोकरी' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। 2001 में फिल्म 'हेरा फेरी' के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 2003 में फिल्म 'अवारा पागल दीवाना' के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 2014 में भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से परेश रावल को नवाजा गया था। परेश रावल फिल्म इंडस्ट्री में शायद इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सपोर्टिव रोल निभाते हुए 61 साल की उम्र में बतौर लीड हीरो न सिर्फ फिल्म में काम किया बल्कि उसे हिट भी बनाया। यहां हम बात कर रहे हैं 2012 में आई फिल्म 'ओह माई गॉड' की। इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में थे और अक्षय कुमार एक अहम लेकिन साइड रोल में थे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

## परेश की ज्यादा फिल्में हिट हुईं

परेश रावल फिल्मी दुनिया के मंझे हुए अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने दर्शकों को हेरा फेरी के बाबूराव गणपतराव आटे से कभी हंसाया है तो ओह माय गॉड में कांजी लालजी मेहता बनकर जागरूक किया है तो कभी राम लखन में खलनायक का किरदार निभाया है। परेश रावल ने 1980 और 1990 के दशक के बीच 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने फिल्मों में ज्यादातर नकारात्मक किरदार निभाए जैसे, 'कब्जा', 'किंग अंकल' 'सरदार' में वो अपोजिट रोल में नजर आए। 1993 में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वल्लभभाई

- परेश रावल का कहना है कि 'जिस समय मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आया उस वक्त एक बाहरी होने के कारण और फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर न होने के बावजूद मुझे कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उस दौर में कम कॉम्पिटिशन और काम के प्रति मेरी लगन थी।'
- परेश रावल और स्वरूप संपत की शादी अनोखी थी, बिना मंडप के पेड़ों की छांव में उनकी शादी हुई, बॉलीवुड की एक रिपोर्ट के मुताबिक परेश और स्वरूप की शादी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पेड़ों की छांव के बीच हुई थी, इस शादी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और ये बहुत ही इंटिमेट वेडिंग थी।

पटेल की मुख्य भूमिका निभाई। परेश के अनुसार एक अभिनेता के रूप में यह उनके लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि सरदार पटेल के चरित्र का विस्तार से अध्ययन करने में उन्हें कड़ी मेहनत और अपने शिल्प में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस रोल ने उन्हें बदल दिया, जिससे उन्हें भारतीय इतिहास की गहरी समझ मिली और उन्हें राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन महान दिग्गजों के बलिदानों की सराहना करने में मदद मिली। परेश रावल ने तेलुगु फिल्म उद्योग में भी अपने काम के दम पर प्रशंसा हासिल की है। परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत में 1982 में गुजराती फिल्म 'नसीब नी बलिहारी' में सहायक की भूमिका निभाई थी। हिंदी के अलावा परेश रावल ने गुजराती, तेलुगु, अंग्रेजी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने करियर में अंदाज अपना अपना, चाची 420, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, दीवाने हुए पागल, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, गोलमाल फन अनलिमिटेड, भागम भाग, भूल भुलैया, वेलकम, ओएमजी, ओह माय गॉड, संजू सहित तमाम हिट फिल्मों में काम किया है।

## राजनीतिक सफर

फिल्मों में काम करने के साथ परेश रावल ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। परेश रावल ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसी साल उन्हें लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद (पूर्व) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस चुनाव में जीतकर वो लोकसभा सांसद बने। हालांकि इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने यह कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वह राजनीति को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। परेश रावल ऐसे पहले अभिनेता नहीं हैं जिन्होंने पॉलिटिकल में इंटी की। वो उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक हैं जो अपने एक्टिंग और पॉलिटिकल दोनों ही करियर्स के बीच में संतुलन नहीं बना सके। इनमें अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सनी देओल जैसे एक्टरस शामिल हैं जो पॉलिटिकल में आए सांसद बने पर पॉलिटिकल के साथ न्याय नहीं कर सके इसलिए राजनीति से किनारा कर लिया।



# मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय

9897450817, 9897791284

ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ

अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं

निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)



## मेघ-

इस माह धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। आपके बरिष्ठ इस माह देवदूतों जैसा व्यवहार करने वाले हैं। अप्रैल में आपको ढेरों दिलचस्प निमंत्रण मिलेंगे-साथ ही आपको आकस्मिक उपहार मिलने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं मिलेंगे। उपाय: मानसिक हिंसा से बचे, प्रभु में विश्वास रखें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

## कर्क:-

इस माह बिना वजह के वाद-विवाद से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई बेहतरीन विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचा सकता है। अपने शब्दों पर काबू रखें, वरना परिवार के बुजुर्ग आहत हो सकते हैं। उन्हें अहसास कराएं कि आप उनका खयाल रखते हैं। इस माह के अंत में कारोबार के लिए की जाने वाली यात्रा फायदेमंद साबित होगी। जीवनसाथी आपका काम बिगाड़ सकता है। धैर्य रखें। उपाय: काला-सफेद कपड़ा साधु संतों को दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 1

## तुला:-

लंबे समय से अटक मुआवजे और कर्ज आदि इस माह आपको मिल जाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिला सकती है। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाने का समय है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: अपने पार्टनर को गुलाब दें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 9

## मकर:-

यह माह मौज-मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें। मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है। जल्दी ही आपको जीवन-साथी मिलने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आने का प्रबल योग है। उपाय: किसी तरह का घर्मंड न करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

## वृषभ:-

इस माह आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहेगी और अजनबी भी जाने-पहचाने से महसूस होंगे। यह माह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है, जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। घरेलू जिंदगी सुकूनभरी और रुशनुमा रहेगी। इस माह आपको सब-कुछ प्रेम के रंग में रंगा दिखाई देगा। कार्यालय में कोई आपको बढ़िया खबर दे सकता है। उपाय: गणेशजी की चार परिक्रमा लेकर आशीर्वाद ले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

## सिंह:-

इस माह आपका आत्मविश्वास और आसान कामकाज आपको आराम के लिए समय देंगे, लेकिन धन आपकी मुट्ठी से सरक सकता है। आपके अच्छे सितारे आर्थिक तंगी नहीं आने देंगे। ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है, जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम करता होगा। कार्यालय में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है, उससे संबंध सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। उपाय: गुरु या पिता की आज्ञा का पालन करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

## वृश्चिक:-

रिश्तेदारों का सहयोग तनाव कम करेगा। सगे संबंधियों से मिलन होगा। उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें। बच्चे और परिवार को केंद्र में रखें। किसी दिलचस्प इंसान से मुलाकात की प्रबल संभावना है। अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी समय से काम कर रहे हैं वह टल सकता है। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। जीवनसाथी प्रेम से भरपूर रहेगा। उपाय: पूजा स्थान पर सफेद शंख स्थापित करें, कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 2

## कुंभ:-

इस माह कमीशन, लाभांश या रायल्टी के जरिए फायदा होने का योग बन रहा है। आपको ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाने में सहायक हों। आपका प्यार आपके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। लेखन और मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वालों को बड़ी ख्याति प्राप्त होने से प्रसन्नता होगी। अपने व्यक्तित्व और रंग-रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। उपाय: छोटी कन्याओं को भोजन कराएं कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

## मिथुन:-

इस माह खीज और चिढ़चिढ़ेपन के अहसास को खुद पर हावी न होने दें। इस माह धन योग है। आप काफी धन कमा सकते हैं। बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और सुकून देंगे। प्रिय के साथ बाहर जाते समय अपने पहनावे और बरताव में नयापन दिखाएं। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। जीवनसाथी के साथ शांत रहे ताकि लड़ाई-झगड़ा न हो। उपाय: काले चने, उड़द, तिल, सरसो का तेल दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 6

## कन्या:-

इस माह रियल एस्टेट संबंधी निवेश अच्छा-खासा मुनाफा दे सकता है। घर में कुछ बदलाव भावुक बना सकते हैं। अपने प्रिय जीवनसाथी के बिना समय बिताने में दिक्कत महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में चीजें वाकई बेहतर की ओर बढ़ सकती हैं। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। आपके लिए यह माह खूबसूरत रोमानी रहेगा। सेहत का खयाल रखे वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय: धर्म स्थान पर झंडा दान करें कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 7

## धनु:-

इस माह खुद को किसी सृजनात्मक काम में व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। बीमारी से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखें। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन धन का व्यय आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है। प्रिय से रोमांटिक मुलाकात होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। जीवनसाथी यह बताएगा कि आप उसके लिए कितने कीमती हैं। उपाय: सोते समय तांबे के बर्तन में पानी रखे सुबह घर के बाहर पेड़ पौधों में डाले कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 8

## मीन:-

यह माह फायदेमंद साबित होगा। आप किसी पुरानी बीमारी से राहत और आराम महसूस करेंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन खर्च में इजाफा आपकी बचत को मुश्किल बना देगा। आप अपनी कामयाबी की फेहरिस्त में एक नया मोती जुड़ेंगे। दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखें। इस माह आपको निराशा हाथ लग सकती है। उपाय: अपने प्रिय को पिंक कलर के मोती या सिसप की बनी हुई वस्तु गिफ्ट करें। कार्य सिद्ध होंगे। भाग्यांक 3



# नुपुर नृत्य कला केंद्र हल्द्वानी

में सभी के लिए  
01 फरवरी 2021 से पुनः

## कक्षाएं आरंभ होगई है।

जिसमें क्लासिकल डांस,  
तबला वादन, सेमी  
क्लासिकल, गिटार, पेंटिंग  
आदि का प्रशिक्षण राज्य  
सरकार द्वारा निर्धारित  
मानकों का पालन करते  
हुए तथा कक्षाओं (क्लास)  
को नियमित रूप से  
सेनेटाइज कर आधुनिक  
तरिके से देने की व्यवस्था  
पूर्ण कर ली गई है।

एडमिशन के लिए  
संपर्क करें।

www.facebook.com/nupurnityakalakendra

You Tube: Search: nupurnityakalakendra

nupurnitya99@gmail.com

www.nupurnitya.com

NEAR KANDPAL ENT. Hospital, SHAKTI SADAN GALLI,  
NAWABI ROAD, HALDWANI  
(NAINITAL), Uttarakhand

05946 220841, 91 9760590897

91 9411161794

